हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 01 सितम्बर, 2026 को माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकत प्रश्न

01.09.2026/1100/av/dc/1

अध्यक्ष : इससे पहले कि प्रश्न काल आरम्भ हो, मैं सबसे विनती करना चाहता हूं कि प्रश्न काल को डिबेट आवर में परिवर्तित न करें। अगर आप मीडिया और आज के समाचार पत्रों में देखेंगे तो जो-जो मुद्दे यहां पर डिस्कस हुए, वे सारे हिमाचल प्रदेश की जनता से संबंधित थे तथा वे सभी रिपोर्ट हुए हैं। समाचार पत्रों में पढ़कर प्रदेश के लोग प्रसन्न होते हैं कि सदन के अंदर हमारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा-से-ज्यादा मुद्दे आएं परंतु वे तभी आ सकते हैं जब आप सभी सहयोग करेंगे। इसलिए 'प्रश्न काल' को प्रश्न काल ही रहने दिया जाए अन्यथा मेरे पास दो ऑप्शन्ज हैं। इसमें एक तो कैमरा बंद करना पड़ेगा। दूसरा, ई-विधान सभा के मोड्यूल को रखेंगे परंतु भाषण देने की प्रक्रिया को बंद करेंगे। मेरे हिसाब से यह प्रक्रिया तब से प्रारम्भ हुई जब से यह कैमरा आया। ...(व्यवधान) कोई नहीं, we can regulate ourselves. इसलिए मेरा आप सबसे यही आग्रह है।

अब प्रश्न काल शुरू होता है।

स्थगित प्रश्न संख्या : 3300

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने सत्ता में आते ही पहले दिन से हिमाचल प्रदेश में संस्थाओं को बंद करने के साथ अपने काम की शुरुआत की थी। इस प्रश्न का उत्तर हम पिछले साढ़े तीन वर्षों से मांग रहे थे और आखिरकार इस प्रश्न का उत्तर आज आया है तथा मुझे लगता है कि यह उत्तर भी पूरा नहीं है। हमने यह पूछा था कि गत तीन वर्षों में दिनांक 31 जुलाई, 2025 तक प्रदेश में विभिन्न विभागों में कुल कितने संस्थान बंद, विलय और डीनोटिफाई किए गए। इस प्रश्न के लिखित उत्तर के अनुसार हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने अभी तक 2035 संस्थान

डीनोटिफाई करके उन पर ताला लगाया है। उसके बाद आगे उत्तर में यह भी कहा है कि 362 संस्थान खोले गए हैं।

टी सी द्वारा जारी

01.09.2026/1105/टी0सी0वी0/डी0सी0-1
प्रश्न संख्या : 3300 . क्रमागत-------श्री जय राम ठाकुर.... जारी

स्वाभाविक रूप से जब आप सत्ता में आए यानी सरकार में आए तो कुछ स्थानों पर आपके समक्ष भी आग्रह आए होंगे और उस आधार पर आपने संस्थान खोले होंगे। इस प्रश्न के "ख भाग" में एक महत्वपूर्ण जानकारी हमने चाहिए है, वह यह है कि भाजपा की सरकार के दौरान जो संस्थान खोले गए थे उनमें से आपने कितने संस्थान डीनोटिफाई करके बंद किए और उनमें से कितने संस्थान बंद करने के बाद फिर से उसी स्थान पर उसी रूप में खोले हैं। यह आंकड़ा भी बड़ा दिलचस्प है, 123 इंस्टिट्यूशंस आपने डीनोटिफाई करने के बाद उसी स्थान पर, उसी रूप में फिर खोले हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए पहला प्रश्न यह बनता है कि जो 123 संस्थान आपने फिर खोले हैं उन्हें पहले बंद क्यों किया गया? यदि आपको लगता था कि इनकी आवश्यकता नहीं है और यदि आपके अनुसार हमने गलत संस्थान खोले थे तो उन्हें बंद करने के बाद दोबारा उसी स्थान पर क्यों खोला गया? आप इसका उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न यह है कि वर्तमान सरकार का चार वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इसके बावजूद अभी तक भी संस्थानों को बंद करने का क्रम लगातार चला हुआ है और चुन-चुनकर तथा ढूंढ-ढूंढकर संस्थान बंद किए जा रहे हैं। वैसे आज आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। मैं बार-बार मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो संस्थान आपने बंद किए हैं उन्हें बंद करने के लिए आपने क्या क्राइटेरिया और क्या मापदंड तय किए हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं अगला प्रश्न भी मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि यदि कहीं संस्थान गलत खुल गए हैं और संस्थान खोलने के निर्धारित पैरामीटर्स के अनुसार नहीं खुले हैं तो

उसकी रिपोर्ट आती है, उसमें समय लगता है। आपका मंत्रिमंडल उस समय गठित भी नहीं हुआ था, आपका मंत्रिमंडल बाद में गठित हुआ और उस समय मुख्य मंत्री तथा उप-मुख्य मंत्री ये मात्र दो ही थे। इन्होंने बिना रिपोर्ट लिए और बिना किसी जानकारी के संस्थानों को डीनोटिफाई करने का फैसला किया। उसका आधार क्या रहा? यह भी मैं जानना चाहता हूं। बाकी बहुत सारे प्रश्न हैं जिन्हें मैं आगे पूछूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न थोड़ा लंबा जाएगा।

01.09.2026/1105/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले जो प्रश्न पूछा गया है उसमें चार मिनट सात सेकेंड का समय लगा। दूसरी बात इन्होंने गंभीरता के बारे में कही है। आप विपक्ष के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं इसलिए आपकी हर बात गंभीरता से सुननी ही पड़ेगी, आप बताएं सुननी पड़ेगी कि नहीं सुननी पड़ेगी?

तीसरी बात, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि आपने संस्थान बंद क्यों किए और इस प्रश्न का जवाब तीन या साढ़े तीन वर्ष के बाद आया है। जो प्रश्न आप उठा रहे हैं उसका उत्तर अभी ही आना चाहिए था ताकि आपके पास एक राजनीतिक हथियार हो कि हमने संस्थान बंद किए।

अध्यक्ष महोदय, सरकार भाजपा और कांग्रेस देखकर संस्थान नहीं खोलती। सरकार जनता की जरूरत के हिसाब से संस्थान खोलती है। चुनावों से पहले जून तक आपने काफी संस्थान खोल दिए थे जिसमें शिक्षा संस्थान और कॉलेज भी थे तथा आपने उनकी नोटिफिकेशन्स कर दी थीं। आपने राजनीतिक लाभ के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की रेवड़ियां बांट दीं और इसमें प्रदेश की संपदा लुटी गई।

अध्यक्ष महोदय, जब संस्थानों का रिव्यू किया गया और संस्थानों को रिव्यू करने के बाद यह पाया गया कि जो शिक्षा संस्थान खोले जा रहे हैं, उनमें टीचर्स तक नहीं हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में तकरीबन 750 संस्थान ऐसे खोले गए, जहां कोई टीचर ही नहीं था और ऐसे संस्थान खोले जहां कोई छात्र ही नहीं था। अब बताइए कि जहां विद्यार्थी ही नहीं है वहां संस्थान नोटिफाई कर दिए गए और जो नोटिफाई किए, उनकी अपग्रेडेशन की गई।

मैं स्कूल्स के मामले में उदाहरण देना चाहता हूं। आपने प्राइमरी से उसको एलिमेंटरी किया, एलिमेंटरी से हाई किया और हाई से सेकेंडरी स्कूल किया। आपने कहीं साइंस का विषय शुरू कर दिया, वहां न साइंस का, न फिजिक्स का टीचर है, न केमिस्ट्री का टीचर है, न बायो का टीचर है और न ही मैथमैटिक्स का टीचर है।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

1-9-2026/1110/NS-HK/1

प्रश्न संख्या : 3300------क्रमागत ------मुख्य मंत्री -------जारी

प्लस टू में बच्चों के लिए साथ लगते संस्थान से एक टीचर भेज दिया और कह दिया कि हमने प्लस टू साइंस क्लासिज स्टार्ट कर दी। बच्चों ने नीट, एन0आई0टी0 का टैस्ट देना है तो वे क्या पढ़ेंगे? इसलिए हमने उन संस्थानों के बारे में गंभीरता से विचार किया। शिक्षा मंत्री जी व सभी अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई और हमने फैसला किया कि हम उन संस्थानों को बंद करेंगे और बंद करने के बाद जहां स्ट्रेंथनिंग करनी होगी, एक डिस्टेंस तक कि बच्चों को स्कूल भी ज्यादा दूर न जाना पड़े तो उसके पैरामीटर्स तय किए गए कि 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के दायरे में जो संस्थान सीनियर सेकंडरी स्कूल हैं हम उनको बंद करेंगे और वहां टीचर्स की पूरी स्ट्रेंथ उपलब्ध करवाएंगे। इस दृष्टिकोण से हमने ऐसा किया जो माननीय जय राम ठाकुर जी बोल रहे हैं कि संस्थान बंद किए गए और वहां टीचर की स्ट्रेंथ पूरी करवाई गई। अध्यक्ष महोदय, जो संस्थान खोले गए वे नीड बेस्ड थे। इसे आप देख लें कि जहां जिस संस्थान की जरूरत है, वहां वह संस्थान खोला गया है। यहां हैल्थ सैक्टर में भी संस्थान खोले गए हैं। हिमाचल प्रदेश की जो जियोग्राफी है वह शिवालिक हिल्स, मिड हिमालय और बिग हिमालय की है। हिमाचल प्रदेश के पास 10 प्रतिशत ही प्लेन इलाका है। अध्यक्ष महोदय, आप अंदाजा लगाइए कि अब चम्बा जैसे क्षेत्र में अगर एक संस्थान खोलना है, अगर डिस्पेंसरी खोलनी है और 10-20 किलोमीटर के दायरे में अगर एक डिस्पेंसरी नहीं खुलती तो आप बताइए कि हम लोगों को अच्छी हैल्थ सैक्टर की सुविधा कैसे दे सकते हैं? इन्होंने संस्थान खोल तो दिए, नोटिफिकेशन भी कर दी लेकिन न डॉक्टर उपलब्ध था और न ही पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध था। आप ऐसे संस्थान चलाकर जनता के साथ भी धोखा कर रहे थे। जहां एक्सिअन ऑफिस की जरूरत

थी वहां एक्सिअन नहीं था। उस क्षेत्र के साथ वाले एक्सिअन को चार्ज दे दिया गया। इसलिए प्रदेश सरकार ने इस पर बहुत प्रूडेंटली थिंक किया है और इसमें कोई ऐसी दोराय नहीं है। यह फैसला पार्टी को देखकर नहीं किया गया है और न ही किसी अन्य दृष्टिकोण से किया गया है। हमने बहुत प्रूडेंटली थिंक करने के बाद फैसला किया कि जहां जनता को जरूरत होगी, चाहे वहां 10 लोग भी होंगे लेकिन उसका डिस्टेंस 20 किलोमीटर होगा तो वहां भी हम संस्थान खोलेंगे।

1-9-2026/1110/NS-HK/2

सवाल यह नहीं है कि जनता को खुश करने के लिए अनाप-शनाप संस्थान खोल दिए जाएं। सवाल यह है कि हमें क्वालिटी इंस्टिच्यूशन्स के इन्फ्रास्ट्रक्चर, टीचर और हैल्थ सैक्टर में जो संस्थान खोले गए हैं उनको भरने के लिए क्या करना है? इसलिए मैं माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि हमने जो संस्थान खोले हैं वे भविष्य में भी खोलेंगे और जो संस्थान बंद करने हैं उनके लिए रैशनलाइजेशन व मर्जर चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं यहां एक उदाहरण देना चाहता हूं कि यहां मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेजिज में 120 बच्चों का सेक्शन होता है। 120 के सेक्शन में एम0बी0बी0एस0 के फर्स्ट सेमेस्टर में कोई बच्चा अगर कोई क्वैश्चन पूछना चाहेगा तो वह पूछ ही नहीं पाएगा क्योंकि इतने बच्चों की अटेंडेंस ही नहीं लग पाती। ...(व्यवधान) मैं आपको उसी का उदाहरण दे रहा हूं। अगर वहां उस कॉलेज के इर्द-गिर्द कोई संस्थान खुला है तो वह पी0एस0सी0 में क्यों जाएगा? वह संस्थान में जाएगा, मेडिकल कॉलेज में जाएगा। **वहां हम ऐसे संस्थानों की रैशनलाइजेशन कर रहे हैं जो मेडिकल कॉलेज की विसिनिटी के दायरे में या 2-3 किलोमीटर के दायरे में आते होंगे तो उनमें भी हम आने वाले समय में रैशनलाइजेशन और मर्जर करेंगे।** यह मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसका मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है।

अध्यक्ष : पहले जो 3 माननीय सदस्य हैं उनको एक-एक सप्लीमेंटरी पूछने का समय देने के बाद फिर मैं आपको देता हूं। माननीय रणधीर शर्मा जी आप अपनी सप्लीमेंटरी पूछिए।

1-9-2026/1110/NS-HK/3

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह पोस्टपोन क्वैश्चन है और जो आंकड़ा दिया है वह 31 जुलाई, 2025 तक का है। इसलिए एक तो मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक कितने संस्थान बंद किए गए और कितने संस्थान खोले गए? यही आंकड़ा 31 जुलाई, 2026 तक दें कि जो बंद किए गए उनमें से कितने दोबारा खोले गए? दूसरा, अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि हमने नीड बेस्ड संस्थान खोले हैं तो बंद किस बेस पर किए? मेरे विधान सभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का डिवीजन हमारी सरकार के समय में खुला था। वहां पर एक्सिअन भी पोस्टिड था, स्टाफ भी पोस्टिड था और भवन भी किराए पर लिया था। इस भवन में कार्यालय के हिसाब से मॉडिफिकेशन भी करवाया गया था और वहां पर स्टाफ भी बैठा। दो-तीन कर्मचारी आउटसोर्स पर लगाकर वहां कर्मचारियों की कमी को पूरा किया गया और 6 महीने तक वह डिवीजन चला। सरकार बदली तो आपने वह डिवीजन बंद कर दी और

आर0के0एस0 द्वारा-------जारी

01.09.2026/1115/RKS/HK-1

प्रश्न संख्याः 3300 जारी------श्री रणधीर शर्मा जारी......

उसके तीन वर्ष बाद आपका वहां का दौरा हुआ, आपने उस डिवीजन को वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर किराए के भवन में दोबारा खोलने की घोषणा कर दी। वहां भी एक्सियन ही तैनात है और कर्मचारियों की संख्या उससे भी कम है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह आवश्यकता तीन वर्ष में ही पैदा हुई? क्या तीन वर्ष पहले वहां आवश्यकता समाप्त हो गई थी? अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी बातों को घुमा-फिराकर कहते हैं। सच्चाई यह है कि इसमें राजनीति की जा रही है। हमारी सरकार के समय जिन संस्थानों को बंद किया गया था, अब उन्हें दोबारा खोलकर झूठा श्रेय लेने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें ये सफल नहीं होंगे। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन अन्य संस्थानों को आपने बंद किया है, क्या उन्हें भी इन 123 संस्थानों की तरह भविष्य में खोला जाएगा या उनके साथ भी इसी प्रकार की राजनीति की जाएगी?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, संस्थान खोलना या बंद करना सरकार के अपने आकलन और आवश्यकता पर आधारित होता है। जहां सरकार को संस्थान खोलने की आवश्यकता होगी, वहां संस्थान खोले जाएंगे और जहां उन्हें बंद करने की आवश्यकता होगी, वहां उन्हें बंद किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु चुनावों से 6 या 8 महीने पहले राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्थान खोलना उचित नहीं है। राजनीतिक लाभ के लिए संस्थान खोलने से इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव पड़ता है। हमारे कार्यकाल में जिन संस्थानों को खोला जा रहा है, वहां सर्वप्रथम स्टाफ की नियुक्तियां की जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया जा रहा है और संबंधित क्षेत्र की जनता की आवश्यकता और मांग के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं। जनता किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, सरकार उनकी आवश्यकता के अनुरूप संस्थान खोल रही है। हमारे घोषणा-पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक लाभ के लिए खोले गए संस्थानों की संवीक्षा की जाएगी। जिन संस्थानों की आवश्यकता नहीं थी उन्हें बंद किया गया। अब केवल संस्थान खोलना पर्याप्त नहीं है बल्कि क्वालिटी पर भी ध्यान देना आवश्यक है। ...(व्यवधान) उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी और वह नीड-बेस्ड था।

01.09.2026/1115/RKS/HK-2

...(व्यवधान) आप मेरी बात ध्यान से सुनिये।...(व्यवधान) मुझे आपके ऊपर हंसी आती है। ...(व्यवधान) आप ठहर जाओ। क्या मैं अपनी बात पूरी कर लूं? ...(व्यवधान) जहां भी संस्थान खोले जाएंगे, वहां जनता की आवश्यकता के अनुसार ही खोले जाएंगे। वहां पहले नियुक्तियां की जाएंगी उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा और ये 123 संस्थान उसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। ...(व्यवधान)

Speaker : Let the Hon'ble Chief Minister complete his reply. Please don't raise your hands.

मुख्य मंत्री : आपने 31 जुलाई, 2026 के बाद की स्थिति के संबंध में प्रश्न किया है जबकि आपको 31 जुलाई, 2025 तक की सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। ...(व्यवधान)

Speaker : Please, please don't disturb. Let him reply. Thereafter, I am giving you (towards Shri Randhir Sharmaji) a chance for supplementary.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 31 जुलाई, 2025 के बाद हमने बहुत कम संस्थान खोले हैं। हमने तकरीबन 8-10 संस्थान ही खोले होंगे और हम उनका ब्यौरा कल विधान सभा में उपलब्ध करवा देंगे। संस्थानों को बंद करना भी एक नियमित प्रक्रिया है। जहां आवश्यकता नहीं होती, वहां ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, हम राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों का लाभ आम लोगों तक पहुंचे। क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में जहां आपके समय हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पर था वहीं आज हम पांचवें स्थान पर पहुंचे हैं और यह इसी सोच का परिणाम है। हम प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश देश में नंबर-वन राज्य बनेगा। धन्यवाद।

01.09.2026/1115/RKS/HK-3

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष जी, हमें नीड-बेस्ड की डेफिनेशन ही समझ में नहीं आई है कि कौन-सा संस्थान नीड-बेस्ड है? आपकी सरकार आते ही संस्थान बंद कर दिये जाते हैं और फिर साढ़े तीन वर्ष बाद उन्हीं संस्थानों को दोबारा खोल दिया जाता है। क्या आपको साढ़े तीन वर्ष तक यही पता नहीं चला कि कहां आवश्यकता है और कहां नहीं है? आपने 15 अप्रैल, 2026 को हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रागपुर में एस0डी0एम0 कार्यालय खोलने की घोषणा की थी। आज मई, जून, जुलाई और अगस्त माह बीत चुके हैं लेकिन वहां अभी तक न तो एस0डी0एम0 की तैनाती हुई है और न ही कार्यालय ने कार्य करना शुरू किया है। क्या कारण है कि 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी प्रागपुर में एस0डी0एम0 कार्यालय नहीं खोला गया है?

श्री बी0एस0द्वारा जारी

01.09.2026/1120/बी.एस./वाई.के.-1

प्रश्न संख्याः 3300 क्रमांगत...श्री बिक्रम सिंह जारी...

और आपने एक और एस0डी0एम0 का कार्यालय दे दिया है? क्या यह कार्यालय भी ऐसे ही चलेगा या साल बाद चलेगा या 6 महीने बाद चलेगा? आपने जो घोषणा की गई थी वह आज तक क्यों नहीं पूरी हुई? कृपया उसके कारण बताएं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय बिक्रम सिंह जी के चुनाव क्षेत्र जसवां-प्रागपुर में हमने 15 अप्रैल, 2026 को एस0डी0एम0 का कार्यालय खोलने की घोषणा की थी। इन्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए था लेकिन ये मुझसे ही सवाल कर रहे हैं? शायद ये वहां पर इस कार्यालय को खोलना नहीं चाहते होंगे लेकिन मैं इनकी बात का जवाब दे देता हूं। ...(व्यवधान) मैं आपको कहना चाहता हूं कि उसको कैबिनेट ने पास कर दिया है। कैबिनेट में पास होने के बाद उसकी हाइकोर्ट से रिकमेंडेशन आती है। हमने हाईकोर्ट में इसकी कॉपी भेजी और उनकी रिकमेंडेशन आ गई है। एक-दो दिन में उसको नोटिफाई कर देंगे।

उसके बाद अध्यक्ष महोदय, सेंसस की तरफ से एक चिट्ठी आई है क्योंकि सेंसस का कार्य चल रहा है। इस समय जो संस्थान हैं उनको सेंसस खत्म होने के बाद और अन्य भी जो-जो संस्थान खोलने होंगे जैसे आदरणीय रणधीर शर्मा जी कह रहे हैं या और माननीय सदस्य कह रहे हैं उन संस्थानों को नीड बेस्ड आधार पर देखकर हम खोलेंगे।

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से सिर्फ यही आग्रह कर रहा हूं कि हम लोगों ने पिछले 10-12 सालों में संघर्ष किया है। हमारा चुराह विधान सभा क्षेत्र और पूरा चम्बा एक अति दुर्गम क्षेत्र है। आप चम्बा जिला को हमीरपुर की तरह या ऊना की तरह ट्रीट नहीं कर सकते।

वहां के संस्थानों को खोलने के लिए पूर्व की सरकारों ने भी प्रयत्न किये हैं और जब से मैं विधान सभा में हूं हमने भी कोशिश की है। हमने देखा है कि ऊना, हरोली में

01.09.2026/1120/बी.एस./वाई.के.-2

तीन कॉलेजिज हो गए हैं। आप अगर जाएं तो 45 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर आप 15 मिनट में बाइक दौड़ाएं तो तीनों कॉलेज नापे जा सकते हैं परंतु चुराह भरमौर, भटियात, डलहौजी या सदर चम्बा भौगोलिक दृष्टि से भी हमारा बहुत दूर और फार-फ्लंग टाइप का एरिया हैं। वहां पर संस्थान खुलना जनता की सही मायनों में सेवा है।

हमारा सर्कल केवल डलहौजी में चलता है। भरमौर और चम्बा को एक ही डिवीजन फीड करता है। जब सर्दियां आती हैं, चाहे बरसातें होती हैं, चाहे अब गर्मियों का दौर हो चाहे जैसा भी दौर हो हम सब लोग एक-एक खंभे के लिए एक-एक तार के लिए और एक-एक मीटर के लिए तरसते हैं। हमने बड़ी मुश्किल से एक्सियन बैठाया। वहां पर एक्सियन बैठे और सारा स्टाफ बैठा। हमने आठ महीने पूरा डिवीजन चलाया।

दो पी0एच0सीज0 जो बड़ी महत्वपूर्ण थी, एक बैरागढ़ में खोली थी। वह छह पंचायतों को फीड कर रही थी और उसका पूरा रेडियस कोई 26 -27 किलोमीटर बनता है। जो हमने कोहाल में खोली वह लगभग 7-8 किलोमीटर एक तरफ से बनती है और 10 किलोमीटर दूसरी तरफ से बनती है। ये दोनों पी0एच0सी0 महत्वपूर्ण थीं। जो हमारा डिग्री कॉलेज मसरुंड में खुला था उसमें 98 बच्चे दर्ज हो गए थे और आगे एडमिशनें होनी थीं लेकिन वह डी-नोटिफाई हो गया।

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यही चाहता हूं कि आप जो नीड बेस्ड की बात कर रहे हैं या जो आप चाह रहे हैं कि आप सच में अगर जनता की सेवा करना चाहते हैं तो मार्मिक दृष्टि से उस विधान सभा क्षेत्र की तरफ देखें।

अध्यक्ष जी, क्या आप यहां माननीय सदन को आश्वस्त करवाएंगे कि हमारा बिजली बोर्ड का डिवीजन डी-नोटिफाई हुआ था उसे फिर से खोला जाएगा? जो दो महत्वपूर्ण पी0एच0सी0 थीं उन्हें फिर से खोला जाएगा? तीन जो हमारे प्राइमरी स्कूल थे उन्हें भी खोला जाएगा? प्राइमरी स्कूल में भी बच्चा 6-6 किलोमीटर जा रहा है, सर। यह हमारे लिए

सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि क्या आप एस्पिरेशनल जिला चम्बा और चुराह क्षेत्र पर ऐसी दया रखेंगे कि जो हमारे संस्थान डी-नोटिफाई हुए थे क्या गवर्नमैंट संवेदनशील होते हुए वहां उन संस्थानों को खोलने की घोषणा करेगी? यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा।

01.09.2026/1120/बी.एस./वाई.के.-3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वैसे तो बड़े डायनेमिक हैं। पिछली सरकार में डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। मैं आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी का भी चम्बा जिला है और हम चम्बा का विशेष ध्यान रखते हैं।

आपने चम्बा जिला का नाम लिया है तो मैं चम्बा के बारे में थोड़ा-सा बता दूं। चम्बा जिला के मेडिकल कॉलेज को कम्प्लीट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए सबसे ज्यादा पैसा हमने दिया है। मैं क्वालिटी हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। इसके लिए हमने 200 करोड़ रुपये दिए हैं।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

01.09.2026/1125/DT/HK-1

प्रश्न संख्या 3300 जारी...मुख्य मंत्री जारी...

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने तीन मिनट तक बोला। ...(व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप इतने नाराज मत हुआ करो। आप जब राजनीतिक शब्दावली में बात करेंगे तो मुझे भी राजनीतिक शब्दावली में उनका उत्तर देना पड़ेगा। यह परंपरा है। आप नाराज क्यों होते हो? अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष की सीट पर पानी से भरा गिलास रख दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि चंबा में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार ने कदम उठाए और अब हम चंबा मेडिकल कॉलेज में फैकलिटीज

की पोजिशन को भी ठीक कर रहे हैं। मैं निकट भविष्य में चुराह का दौरा करने जा रहा हूं, वहां जाकर कई स्थितियों का आकलन करूंगा। चुराह क्षेत्र का दौरान करने के बाद ही फैसले लिये जाएंगे क्योंकि हम नोटिफिकेशन्ज में भरोसा नहीं रखते और चुनाव से केवल छः माह पहले जो संस्थान खोले हैं-उनपर तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते। छः महीने में उस संस्थान में कैसे डाक्टर की नियुक्ति होगी? पब्लिक सर्विज कमीशन में ही पदों को भरने की औपचारिकताएं पूरा करने में छः महीने लग जाते हैं-पदों का विज्ञापन प्रकाशित होगा, एग्जाम होगा, पर्सनल इन्टरव्यू होगा। लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंतिम वर्ष के जून माह में संस्थान खोल दिए। वे संस्थान जून के महीने में ही क्यों खोल दिए। जून में ही संस्थान क्यों खोले-आप साढ़े चार साल तक क्यों सोए रहे? आप हमारी सरकार की तरह संस्थान खोलते। जैसे माननीय सदस्य बिक्रम सिंह ने पूछा, उसका उत्तर हमनें दे दिया कि ऐसे खुलते हैं संस्थान। मैं चंबा का दौरा कर रहा हूं और **जहां जरूरत होगी वहां खोलेंगे मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी भावानाओं की कदर करता हूं जहां जरूरत होगी मैं खुद विजिट करके देखूंगा। वहां पर जो भी जरूरत होगी चाहे डाक्टर की या किसी अन्य चीज की वह भी हम उपलब्ध करवाएंगे।** माननीय सदस्य जिस अधिशाषी अभियन्ता के कार्यालय की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। स्मार्ट मीटरिंग आ गई है और फीडर मीटर आ रहे हैं। अब अधिशाषी अभियन्ता के कार्यालय की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि मोबाइल की तरह ही बिजली के बिल भी प्रीपेड हो जाएंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करनी है, उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार गंभीरता से विचार करेगी।

01.09.2026/1125/DT/HK-2

अध्यक्षः लास्ट सप्लीमेंटरी, माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी जो जवाब देते हैं उस जवाब से सच्चाई कोसों दूर है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी कभी तो इस माननीय सदन में आप सत्य वचन बोलिए।

अध्यक्ष महोदय, सरकार पांच वर्ष के लिए चुनी जाती है और पांच वर्ष तक उस सरकार को प्रदेश के विकास से संबंधित- प्रदेश के हित में कोई भी फैसला लेने का अधिकार है, क्योंकि वह चुनी हुई सरकार है। हिमाचल प्रदेश में जैसे कांग्रेस की सरकार बनी सरकार बनने के बाद इनको कैसे मालूम पड़ा कि जो संस्थान पूर्व सरकार ने खोले हैं वे नीड बेस्ड नहीं हैं? आपने दूसरे दिन 11 दिसंबर को शपथ ली और या 13 अथवा 14 दिसंबर को सरकार ने फैसला लिया कि प्रदेश में पिछले छः महीने में जितने भी संस्थान पूर्व सरकार द्वारा खोले गये हैं, उनको बंद करने के आदेश दे दिए। आप बंद करिए, आप चुप-चुप करिए आप (माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी को कहा गया) ।...(व्यवधान) हां क्या... यह क्या... कमेंटरी करते रहेंगे। आप मुख्य मंत्री के नजदीक होने का इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी भी बोलते रहें और कुछ भी बोलते रहें ।...(व्यवधान) आपको कैसे मालूम पड़ा कि इन स्कूलों में बच्चे ही नहीं हैं? शपथ लेने के बाद केवल दो दिन ही आपको सत्ता में आए हुए थे और आपने वे सारे स्कूल बंद कर दिए। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ इन्होंने उन संस्थानों को बंद कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि आज आप घोषणा कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री हैं और जिम्मेवारी के साथ काम करिए। आज पूरे देश जनगणना चल रही है और जनगणना का मूल कॉन्सेप्ट होता है वह यह है कि जिस दिन जनगणना करने बारे नोटिफिकेशन होती है उसके बाद जब तक सेंसस कम्प्लीट नहीं होती है और नोटिफाई नहीं हो पाती है तब तक के लिए सारे रेवेन्यू यूनिट खोलने पर पूरे देश में प्रतिबंध होता है और सारे कार्य फ्रीज़ कर दिए जाते हैं। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री

01.09.2026/1125/DT/HK-3

वाह-वाही लूटने के लिए जनसभाओं में घोषणाएं कर रहे हैं। आप एक प्रकार से सारे हालात का तमाशा बना रहे हैं- इस पर आपका क्या कहना है?

दूसरा सप्लीमेंटरी मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या जो 123 संस्थान जो पूर्व सरकार ने जनता के कहने पर खोले थे ऐसा नही है कि मुख्य मंत्री के नाते मुझे सपना आया और मैंने वहां जाकर संस्थान खोल दिए। वहां के जनप्रतिनिधियों ने जनसभा में मांग की थी-उसी के पश्चात हमने वे संस्थान खोले थे। लेकिन आप ने वह संस्थान बंद कर दिये। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार इन सारी चीजों को रिव्यू करेगी? जो संस्थान आपने बिल्कुल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ

श्री एन0जी0 द्वारा जारी....

01.09.2026/1130/ए.जी.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 3300.........जारी--------श्री जय राम ठाकुर......... जारी

बंद किए हैं, उनको दोबारा खोलने के लिए पयत्न करेंगे?

अध्यक्ष महोदय, मैं लास्ट में यह भी कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने छह महीने के नहीं बल्कि हमारी सरकार के अंतिम एक साल के संस्थान बंद किए हैं। हम आपके पांच साल के सारे संस्थान जो खोले हैं, संस्थान ही नहीं, बल्कि जो फैसले लिए हैं, उन सभी फैसलों को रिव्यू करेंगे।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी, पहले यहां आ तो जाओ, उसके बाद करना। कोई राजनीतिक पार्टी यह तय नहीं करती बल्कि जनता ने तय करना है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हमारा आना तय है और सत्ता पक्ष के लोग हमें रोक नहीं पाएंगे। मुख्य मंत्री जी, जो बदले की भावना के साथ आपने कार्रवाई की है, उसको रिव्यू करेंगे, एक बात और दूसरी बात, जो सेंसस का बेसिक मूल सिद्धांत है कि आप कोई

रेवेन्यू यूनिट या डेवलपमेंट यूनिट तब तक नहीं खोल सकते हैं, जब तक सेंसस कंप्लीट होकर नोटिफाई न हो जाए, उस पर आपका क्या कहना है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी के मुंह से सत्य बोलने वाला शब्द अच्छा नहीं लगता कि सत्य तो बोला करो। आप अपने आप ही परेशान हो जाते हो।...(व्यवधान) मैं आपको सच बता रहा हूं। आप परेशान मत हुआ करो। आप परेशान इसलिए होते हो क्योंकि जब तनाव होता है या रात को नींद नहीं आती, तब इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं।

01.09.2026/1130/ए.जी.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, संस्थान खोलना और बंद करना सरकार के नीतिगत फैसले होते हैं। कोई व्यक्तिगत तौर पर ये फैसले नहीं लिए जाते हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश का अध्ययन करने के बाद ये फैसले लिए जाते हैं। अगर आपको खोलने ही थो तो चुनावों से पहले नहीं करना चाहिए था। पहले वहां पर एम्प्लॉयी भरने थे। पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य चयन आयोग के माध्यम से आपको एम्प्लॉयी भरने चाहिए थे, टीचर लगाने चाहिए थे, तब संस्थान खोलने चाहिए थे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिसको आप सब-ऑर्डिनेटेड सिलेक्शन बोर्ड बोलते थे, जहां पेपर लीक होते थे, पेपर बेचे जाते थे...(व्यवधान)

Speaker : Please don't disturb.

मुख्य मंत्री : जब आप बोल रहे थे, तब मैंने कितने प्यार से सुना। मैं गंभीरता से सुन रहा था और आपने उस पर भी टिप्पणी कर दी। अध्यक्ष महोदय, पेपर लीक होते थे और पेपर बेचे जाते थे। हमारी सरकार ने देखा कि वहां भ्रष्टाचार है, इसलिए सिलेक्शन बोर्ड को बंद कर दिया। किया ना? संस्थानों को इसलिए भी बंद किया जाता है। जिन्होंने पेपर लीक किए थे, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक, वे जेल की सलाखों के पीछे हैं। NEET का पेपर लीक हुआ और उसमें अभी तक ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं हुआ। हमने एक्शन लिया। उसके बाद

हमने दोबारा उस संस्थान को खोला है। वह नीड बेस था क्योंकि वहां पेपर होने हैं। यह मैंने एक उदाहरण आपको इसलिए दिया, क्योंकि यह ताजा-ताजा है और आपको याद रहेगा।

दूसरा, इन्होंने कहा कि सेंसस की बात है। सेंसस ने फ्रीज़ किए हैं और इसके बारे में हमें भी पता है। यह स्टेट सब्जेक्ट है। संस्थान खोलना हमारे अधिकार क्षेत्र में है। हमने लॉ भी की है और पढ़े-लिखे हैं, हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं।...(व्यवधान) आपको किसने कहा? आप भी बहुत पढ़े-लिखे हैं। मैंने थोड़ी कहा कि आप लोग अनपढ़ बैठे हैं।...(व्यवधान)

01.09.2026/1130/ए.जी.-एन.जी./3

Speaker : Please don't disturb.

मुख्य मंत्री : आप सब लोग पढ़े-लिखे चुनकर आए हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है कि इस सभा सदन में 90 प्रतिशत माननीय सदस्य पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, इंजीनियर, डॉक्टर आदि चुनकर आए हैं। यह बड़ी अच्छी बात है।

अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि स्टेट सब्जेक्ट के तहत—आप तो जानते हैं, आप विधि के ज्ञाता भी हैं—तो आप जानते हैं कि जब हमने कोई घोषणा की है तो रूल्स के हिसाब से घोषणा की है। उसकी हम घोषणा करेंगे, कैबिनेट से अप्रूव करेंगे, हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट के बाद वापस आएगा और तब तक सेंसस का टाइम खत्म हो जाएगा तो हम नोटिफाई कर देंगे। तो हमने पहले ही कर दिया है। तो यह कहना कि फ्रिज कर दिया है, यह ऐसा नहीं है। उन्होंने फ्रीज तब तक किया है जब तक सेंसस चल रहा है। हमारा सेंसस जल्दी खत्म हो जाएगा और हम नोटिफाई कर देंगे।...(व्यवधान)

Speaker : Bikramji, no interruption, please. Please take your seat. मुख्य मंत्री जी, आप बोलिए।

मुख्य मंत्री : देखो, अभी तकलीफ तो होगी। मुझे बोलने में आपको तकलीफ तो होगी।

Speaker : You have reasonably explained everything.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको कहना चाहता हूं कि

पी0बी0 द्वारा......जारी

01.09.2026/1135/AG/PB/1

प्रश्न संख्याः 3300 क्रमांगत... मुख्य मंत्री... जारी

अगर पांच दिन में भी वहां एस0डी0एम0 बनाना पड़ेगा तो हर कानून में ऐसा प्रावधान होता है कि जहां जनगणना के आधार पर बैन लगा होता है वहां हम उनसे स्पैशल एग्जम्पशन/अनुमति मांग सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के एक और सवाल का उत्तर देना चाहता हूं। इन्होंने सरकार से दिनांक 31 जुलाई, 2025 तक की ही सूचना मांगी थी। अगर माननीय सदस्य आगे की सूचना मांगेंगे तो हम इन्हें वह सूचना भी उपलब्ध करवा देंगे।...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप गुस्सा मत कीजिए, आप क्यों इतना गुस्सा करते हो? आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ...(व्यवधान)

01.09.2026/1135/AG/PB/2

प्रश्न संख्या : 4167

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था कि हिमाचल प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी विभागों में नौकरियों एवं प्रशिक्षण हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है? मुझे इसके उत्तर में सूचना मिली है कि हमारे जितने एम0बी0बी0एस0 कॉलेज, संस्थान एवं महाविद्यालय हैं, उनमें इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में 102 में से 4, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टाण्डा में 102 में से 2, श्री लाल बहादुर शास्त्री आयुर्विज्ञान महाविद्यालय मण्डी में 102 में से 2, डॉ0 यशवन्त सिंह परमार आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नाहन में 102 में से 2, डॉ0 राधाकृष्णन आयुर्विज्ञान

महाविद्यालय हमीरपुर में 102 में से 2 तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चम्बा में 102 में से 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। ओ0बी0सी0 वर्ग के लिए कुल 610 में से 14 पद आरक्षित किए गए हैं। ओ0बी0सी0 वर्ग को शिक्षा विभाग के तहत विश्वविद्यालयों में सरकारी नौकरी हेतु वर्ग ए और बी के लिए 12 प्रतिशत तथा वर्ग सी और डी के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। ओ0बी0सी0 वर्ग को विभिन्न श्रेणियों में अलग-अलग तरह का आरक्षण दिया गया है। डॉ0 यशवन्त सिंह परमार औद्योनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में 2 सीटें प्रति कोर्स आरक्षित की गई हैं तथा चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर में एक सीट आरक्षित की गई है।

वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में ओ0बी0सी0 वर्ग में बहुत ज्यादा कैटेगरीज़ आ गई हैं। हिमाचल प्रदेश में ओ0बी0सी0 वर्ग की 24 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या है। हिमाचल प्रदेश में ओ0बी0सी0 वर्ग को दिया जाने वाला आरक्षण ओ0बी0सी0 समाज के साथ एक बहुत बड़ा और भद्दा मजाक है। यह आरक्षण ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आप ओ0बी0सी0 वर्ग के लिए एम0बी0बी0एस0 कोर्स की 102 में से 2 और 610 में से 14 सीटें आरक्षित करते हैं। सरकार ए और बी वर्ग में 12 प्रतिशत, सी और डी वर्ग में 18 प्रतिशत और कहीं 15 प्रतिशत तक आरक्षण देती है।

मैं मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि विभिन्न वर्गों एवं विभागों में एक जैसा आरक्षण प्रतिशत किया जाए। हिमाचल में ओ0बी0सी0 वर्ग की जनसंख्या 24 प्रतिशत से ज्यादा है। हमें अभी कुल जनसंख्या का पूरा अंदाजा नहीं है। ओ0बी0सी0 वर्ग में बहुत-सी जातियां समय-समय पर शामिल की गई हैं। आप प्रदेश के

01.09.2026/1135/AG/PB/3

एम0बी0बी0एस0 महाविद्यालयों में इस आरक्षण को बंद ही कर दीजिए। मैं ओ0बी0सी0 समाज की ओर से कहना चाहता हूं कि हमें 610 में से 14 पद नहीं चाहिए। मैं मुख्य मंत्री महोदय से यही आग्रह करना चाहता हूं कि हमें कम-से-कम 18 प्रतिशत आरक्षण एम0बी0बी0एस0 में और सभी विभागों में युक्तीकरण करके दिया जाए ताकि ओ0बी0सी0 समाज के साथ अन्याय न हो।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर किसी ने ओ0बी0सी0 समाज का कल्याण किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है। माननीय सदस्य, आप स्वंय पूर्व सरकार में मंत्री थे। आपने उस समय ओ0बी0सी0 वर्ग का मामला क्यों नहीं उठाया? आप अब राजनीतिक बात कर रहे हैं। आप पिछले पांच वर्ष स्वंय मंत्री थे। आपने उस समय इस विषय से संबंधित कोई मामला नहीं उठाया और आज जोर-शोर से इस विषय पर कह रहे है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम ओ0बी0सी0 वर्ग का कल्याण राजनीतिक लाभ देखकर नहीं कर रहे हैं। हम ओ0बी0सी0 वर्ग का कल्याण उनकी भावनाओं के अनुसार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी कहना चाहता हूं कि हम एम0बी0बी0एस0 के अलावा अन्य क्षेत्रों में आरक्षण देने पर भी विचार करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के अनुसार आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। उन सब चीजों

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

01.09.2026/1140/ए0एस0-ए0पी/-01

प्रश्न संख्या 4167 जारी .....मुख्य मंत्री जारी .....

का अध्ययन कर रहे हैं। हमारी सरकार ने पहली बार ओ0बी0सी0 कमीशन बनाया है ताकि सही समय पर सही अधिकार उन लोगों को मिल सके। जहां नौकरियों में क्लास-1 और क्लास-2 की नौकरियों में 12 प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं, वहीं क्लास-3 और क्लास-4 में 18 प्रतिशत आरक्षण भी दे रहे हैं। यह आरक्षण की व्यवस्था है इसलिए हमने ओ0बी0सी0 कमीशन बनाया गया है कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज के अलावा और जगहों पर भी जो स्थिति है। जैसे इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज, जो गवर्नमेंट के हैं, उनमें 18 प्रतिशत आरक्षण है। राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज में 12 प्रतिशत आरक्षण है। यह क्यों हुआ? इन सब चीज़ों को समय के अनुसार ठीक किया जाना भी जरूरी है। बी0एड0 में 15 प्रतिशत आरक्षण है, आप यह बताना भूल गए। जहां आरक्षण कम है, उस पर हमारा ओ0बी0सी0 कमीशन गाइडलाइन और रिकमेंडेशन बना रहा है। हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, भारत सरकार ने जनसंख्या के आधार पर पॉपुलेशन की काउंटिंग शुरू की है कि कितनी

पॉपुलेशन किस जाति की है और किस प्रकार की पॉपुलेशन है। जब कास्ट सेंसस पूरा हो जाएगा, उसके अलावा ओ0बी0सी0 कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन आएगी, हम उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे। हम यह कहना चाहते हैं कि ओ0बी0सी0 का कल्याण भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। प्रदेश में सर्व समाज का कल्याण कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, आप निश्चिंत रहिए। आने वाले समय में जैसे ही कास्ट सेंसस का डेटा आएगा, हम उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं।

श्री सुख राम चौधरी : सर, मेरा तो सीधा सा प्रश्न है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में क्लास-1 और क्लास-2 में 12 प्रतिशत आरक्षण है और क्लास-3 और क्लास-4 में 18 प्रतिशत आरक्षण है। यह कब से लागू है? यह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से लागू है। यह सारा आरक्षण उसी समय से लागू है। पिछले चार साल में कोई नया आरक्षण नहीं दिया गया है। इसलिए मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि एम0बी0बी0एस0 में जो 610 में से 14 सीटें दी गई हैं, क्या इस पर पुनर्विचार करके ओ0बी0सी0 समाज के साथ अन्याय किया जाएगा? यह बात मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

01.09.2026/1140/ए0एस0-ए0पी/-02

मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि सभी जगह आरक्षण की व्यवस्था है। कई जगह कमी है और उस कमी को पूरा कांग्रेस ने किया है, आपने नहीं किया। मैं तो यह आपसे पूछना चाहता हूं कि एम0बी0बी0एस0 के लिए आरक्षण आपने क्यों नहीं किया? मैं यह बोलना चाहता था कि कांग्रेस और टेक्निकल एजुकेशन, सब कुछ हम कर रहे हैं। जैसे ही कास्ट सेंसस पूरी होगी और कास्ट सेंसस के बाद ये चीज़ें सामने आएंगी। सारी चीज़ों का विचार करेंगे। हमने ओ0बी0सी0 कमीशन बनाया है और उसकी रिपोर्ट भी अभी आएगी।

01.09.2026/1140/ए0एस0-ए0पी/-03

प्रश्न संख्या : 4618

श्रीमती रीना कश्यपः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मंत्री जी ने सदन पटल पर रखी है, वह बहुत ही विस्तृत जानकारी है। मैं केवल इतना ही पूछना चाहूंगी कि पच्छाद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जो पद खाली हैं, चाहे वे डॉक्टर्स के पद हों या मेडिकल स्टाफ के पद रिक्त हों, वे कब तक भरेंगे? साथ में, भाग-ख में जो मेरा प्रश्न है कि राजगढ़ अस्पताल में जो अल्ट्रासाउंड मशीन है, वह ठीक हो गई है। मगर मैं मंत्री जी से एक आश्वासन चाहती हूं कि राजगढ़ हॉस्पिटल में जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित जी हैं। उनका न तो ट्रांसफर किया जाए और न ही उनको डेपुटेशन पर किया जाए। क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है। आप मुझे यह आश्वासन इस सदन में दें। साथ में, मेरे प्रश्न का भाग-ग यह रहेगा कि हमारा जो सराहां हॉस्पिटल है। वहां जिस प्रकार बताया गया है कि अल्ट्रासाउंड मशीन जल्द आने वाली है तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि वहां रेडियोलॉजिस्ट का जो पद है, उसकी स्वीकृति आप सुनिश्चित करें। माननीय मंत्री जी, मैं कहूंगी कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। तभी वहां पर अल्ट्रासाउंड की मशीन से सराहां के लोगों को लाभ मिल पाएगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्रीमती रीना कश्यप जी ने अपने विधान सभा क्षेत्र की तीन प्रकार की समस्याओं को उजागर किया है कि कितने पद स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त हैं और रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा।

श्री ए0टी0 जारी .....

01.09.2026/1145/AT/AS/01

प्रश्न संख्या 4618 जारी....स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी....

कि कितने पद स्वीकृत हैं और कितनी पद भरे हुए हैं और रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा और अल्ट्रासाउंड मशीन की अद्यतन स्थिति। अल्ट्रासाउंड मशीन की अद्यतन स्थिति क्या है? मैं माननीय सदस्या को यह बताना चाहुंगा कि राजगढ़ में स्थिति अच्छी है। साथ में यह भी कहा गया कि क्या आने वाले वर्षों में विशेषज्ञ चिकित्सकों, आधुनिक जांच एवं अन्य सेवाओं को बढ़ाने का विचार है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय का, मैं समझता हूं कि इन गत साढ़े तीन सालों में जो सबसे बड़ा प्रयास रहा है, I think the best of machinery, whatever is high-end equipment technologically, which he also expressed. इसके साथ-साथ इन उपकरणों का प्रयोग करने वाले, that are doctors, paramedics and the nursing staff-they all should be there जो माननीय सदस्य ने तीन अच्छी चीजें उठाई हैं। मैं वताना चाहता हूं कि कुल 317 स्वीकृत पदों में से अभी 164 पद भरे हुए हैं और 153 पद हमारे रिक्त हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है।

नागरिक अस्पताल राजगढ़ में जो ultrasound machine है, that is functional है। In case it is not functioning, we shall give a new one, there is no doubt in it. We have provisions for almost 47 ultrasound machines and we are distributing them also. इनके पास OBG, Pediatrician, Ophthalmologist and Anesthesia के विशेषज्ञ हैं। माननीय सदस्य ने जिन दूसरे विशेषज्ञों की मांग की है, वे भी तैनात किए जा रहे हैं, क्योंकि as told by the Hon'ble Chief Minister, that we are trying to fill the posts in all those areas where there are deficiency and I will say that there are really major deficiencies in Pachhad, no doubt about it. जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है, मैंने भी as a Member of Parliament पछाद के बारे में चीजें उठाता रहा हूं, I appreciate her. जहां तक आपातकालीन सुविधाओं की बात है, ये सुविधाएं हम 24×7 दे रहे हैं। अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। और जो आपने बात कही है, we won't disturb that doctor.

01.09.2026/1145/AT/AS/02

प्रश्न संख्या- 4619

श्री आशीष बुटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर में तकरीबन 82 लोगों ने अनुकम्पा के आधार पर आवेदन किया था। इनमें से तकरीबन 5 लोग क्लर्क के लिए, 11 MTW के लिए और 11 फील्ड असिस्टेंट के लिए eligible पाए गए हैं।

माननीय महोदय, ऐसा हुआ है कि पहली अगस्त को सचिव, कृषि की ओर से रजिस्ट्रार को एक चिट्ठी गई। रजिस्ट्रार ने पहले यह मांग रखी थी कि 11 फील्ड असिस्टेंट की पोस्टें और 5 क्लर्क की पोस्टें भरी जाएं, जो कि दोनों Class-III के अंतर्गत आती हैं। लेकिन सचिव की ओर से रजिस्ट्रार को हाल ही में चिट्ठी गई है, उसमें यह पूछा गया है कि फील्ड असिस्टेंट की पोस्टें क्यों भरी जानी हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रय करना चाहूंगा कि फील्ड असिस्टेंट की पद भी विश्वविद्यालय में बहुत जरूरी है। Clerical cadre की पोस्ट भी भरना जरूरी है और फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट भी। प्रश्न के उत्तर में यह आया है कि इस पर विचार किया जा रहा है, it is under consideration. तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि ये पद कब तक भरे जाएंगे। दूसरा, 11 posts, जो Peon से MTW में conversion के लिए सरकार को भेजी गई हैं, उनकी MTW policy कब तक बनकर तैयार हो जाएगी? यह भी मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा।

एक बात इसमें मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि अगर इस प्रक्रिया को थोड़ा जल्दी कर लिया जाए, क्योंकि इस कृषि विश्वविद्यालय में ये पद बहुत समय से खाली पड़े हैं। अनुकम्पा आधार के 82 मामलों में से दो ऐसे मामले हैं, जिनके आवेदक अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए अगर उन्हें जल्दी नौकरी मिल जाए, तो मुझे लगता है कि हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे।

01.09.2026/1145/AT/AS/03

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 82 आवेदन विश्वविद्यालय में प्राप्त हुई और जांच-पड़ताल करने पर 27 आवेदक पात्र पाए गए। उन्हें श्रेणी-III और श्रेणी-IV के पद दिए गए। 11 आवेदकों को ऑपशन

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी.....

01.09.2026/1150/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 4619-------- क्रमागत--------कृषि मंत्री----------- जारी

दी गई कि आप फील्ड एसिस्टेंट बनना चाहते हैं या क्लास-iii में जाना चाहते हैं? उसमें यूनिवर्सिटी के कुछ नॉर्म्ज थे। सरकार ने करुणामूलक आधार पर नौकरी देने की पॉलिसी में समय-समय पर काफी परिवर्तन किए हैं। इसमें पहले इन्कम का क्राइटीरिया था जिसको रिवाइज करके अब एक वर्ष की तीन लाख रुपये की आमदनी का क्राइटीरिया रखा गया है। **इसमें जो भी एलिजिबल लोग रह जाएंगे उनको भी as per the guidelines of the Government of Himachal Pradesh के मुताबिक मौका दिया जाएगा और उनकी भर्ती भी बड़ी जल्दी कर दी जाएगी। अगर फील्ड एसिस्टेंट की पोस्ट्स की रिक्वायरमैंट है तो हम उसको भी मीटआउट करेंगे।**

01.09.2026/1150/av/dc/2

प्रश्न संख्या : 4620

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय दलाश के भवन के लिए पांच वर्षों से अधिक समयावधि से भूमि हस्तांतरण का मामला प्रक्रियाधीन है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट का भी

कोई प्रावधान नहीं किया गया। क्या सरकार दलाश और उस क्षेत्र की जनता के लिए कोई निश्चित समय-सीमा बताएगी कि राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय दलाश हेतु भूमि हस्तांतरण, वित्तीय स्वीकृति और उसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा?

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला कुल्लू के आनी विधान सभा क्षेत्र के दलाश में राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय खोलने की अधिसूचना दिनांक 06 सितम्बर, 2019 को हुई थी और तब से लेकर माह सितम्बर-अक्तूबर, 2022 तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। उस समय इसके लिए कोई ज्यादा गम्भीर प्रयास नहीं किए गए। यह सही है कि पहले बजट का प्रावधान रखा जाता था परंतु उसका भूमि हस्तांतरण का मामला एफ0सी0ए0 में अप्लाई किया है। जब तक लैण्ड डाइवर्ट नहीं होती तब तक जो टोकन बजट रखा जाता था, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से टोकन बजट रखा जाता था परंतु फाइनली वह खर्च नहीं होता था। इसलिए इस बार इसके लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। इसका एफ0सी0ए0 के लिए केस अपलोड कर दिया है और इसके लिए मुहाल सोईधार (कोठी सिरिगढ़) में भूमि का चयन किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम के तहत दिनांक 08 नवम्बर, 2021 को यह केस अपलोड हुआ था परंतु अभी यह पैंडिंग है। मैं अपने वन विभाग के अधिकारियों को कहूंगा कि इसको टेकअप करके इससे संबंधित सारी औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाए। लेकिन मैं यहां पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि फार्मेसी कॉलेज, बहुतकनीकी महाविद्यालय और आई0टी0आई0 कॉलेज जोकि हमारे तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, इनकी हालत भी स्कूल्ज की तरह हो गई है। हम क्वालिटी ट्रेनिंग इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारे पास इन कॉलेजिज की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। मैं समझता हूं कि न तो इतने कॉलेजिज की जरूरत है

01.09.2026/1150/av/dc/3

और न ही हमारे पास उतने संसाधन उपलब्ध हैं। अगर केवल राजनीति चलाने के लिए इन संस्थानों को खोलने के प्रयास किए जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उससे क्वालिटी प्रभावित

होगी। अगर इस वर्ष का आंकड़ा देखा जाए तो पोलीटैक्निक में कुल सीट्स में से 234 सीट्स खाली हैं जिसमें बच्चों ने एडमिशन नहीं ली है। अतः माननीय सदस्यों को इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि माननीय पूर्व या वर्तमान मुख्य मंत्री का जहां पर भी प्रोग्राम होता है तो हम डिमाण्ड करते हैं कि यहां पर यह संस्थान खोल दीजिए या वह संस्थान खोल दीजिए। पिछले अगर दो-तीन दशक

टी सी द्वारा जारी

01.09.2026/1155/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

प्रश्न संख्या : 4620.. क्रमागत्------नगर एवं ग्राम योजना मंत्री.... जारी

को देखें तो हमारा सड़कों का नेटवर्क बहुत इम्प्रूव हुआ है। हमारे पास ट्रांसपोर्ट के साधन बढ़े हैं और इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन सर्विसीज भी उपलब्ध हैं। इसलिए नये संस्थान खोलने की बजाय हम थोड़ा-सा कंसॉलिडेशन करने, क्वालिटी ट्रेनिंग और क्वालिटी सर्विसीज की ओर जाने का प्रयास करेंगे ताकि इन संस्थानों को प्रॉपर तरीके से फंक्शनल किया जा सके। मुझे लगा कि यह बेहतर रहेगा।

01.09.2026/1155/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

प्रश्न संख्या : 4621

श्री आर0एस0 बाली : अध्यक्ष महोदय, जल शक्ति विभाग में मल्टी पर्पज वर्कर्ज की तीन श्रेणियां हैं। इनमें जो सबसे निचले तबके के वर्कर्ज हैं जो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं और रात-दिन काम करते हैं। जब भी कोई प्रलय या बाढ़ आती है, तब किसी भी समय ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले पैरा-पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टी पर्पज वर्कर्ज होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर के लिए आठ-आठ वर्ष की पॉलिसी का प्रावधान है। आठ वर्ष की पॉलिसी के बाद वे जॉब ट्रेनी बनते हैं जिसमें उनकी तनख्वाह थोड़ी-सी और बढ़ती है, उसके बाद दो वर्ष और लगाने पर उनकी रेगुलराइजेशन होती है। इसमें 15 प्रतिशत का कोटा है जो सीनियरिटी क्राइटेरिया पर आधारित है। मैंने पहले भी यह गुजारिश की थी कि यह 15 प्रतिशत कोटा बढ़ाना अति आवश्यक है क्योंकि इसके अंतर्गत अधिक लोग नहीं आ पाते हैं।

दूसरा विषय यह है कि आप भी संवेदनशील हैं और सरकार भी जरूरतमंद तबके के प्रति संवेदनशील है। पहले जो तनख्वाह 6,600 रुपये थी उसे बढ़ाकर 7,100 रुपये किया गया है। जॉब ट्रेनी लगने पर 12,120 रुपये और रेगुलर होने पर 18,000 रुपये मिलते हैं। अध्यक्ष महोदय, तनख्वाह में 500 रुपये की बढ़ोतरी इस सरकार ने की है, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन आज की महंगाई में 7,100 रुपये में गुजारा नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, इसका अगला भाग, इनका कोटा है। जो लोग पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर हैं उनके लिए यह व्यवस्था है लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मल्टी पर्पज वर्कर्ज की कोई पॉलिसी ही नहीं बनी है। मल्टी पर्पज वर्कर्ज की स्थिति और भी दयनीय है। ...(घण्टी) अध्यक्ष महोदय, बस एक मिनट लूंगा। जहां 5,500 रुपये मिलते थे, वहां 6,800 रुपये किए गए हैं लेकिन क्या सरकार मल्टी पर्पज वर्कर्ज के लिए भी पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर की तरह पॉलिसी बनाना चाहेगी और क्या इस पर काम हो रहा है? इस पर काम होना अनिवार्य है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि इन विषयों पर काम किया जाए। धन्यवाद।

01.09.2026/1155/टी0सी0वी0/डी0सी0-3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, हमारी सरकार गंभीरता से एक पॉलिसी पर कार्य कर रही है। माननीय सदस्य की जो चिंता है, उसे भी ध्यान में रखा जा रहा है कि मल्टी टास्क वर्कर कई प्रकार से हैं, कुछ पार्ट-टाइम के लिए या 6 घण्टे के लिए काम करते हैं और कोई चार घण्टे के लिए काम करते हैं। हर इंस्टीट्यूशंस ने

अलग-अलग पॉलिसी बनाई है। एजुकेशन ने अलग, हैल्थ ने अलग और जल शक्ति विभाग ने अलग पॉलिसी बनाई है। ये पॉलिसियां स्कीम बेस पर बनाई गई हैं। इसलिए हम सबके लिए एक कंपोजिट पॉलिसी पर कानून के आधार पर काम कर रहे हैं। मेरा यह मानना है **कि हम जल्दी ही मल्टी टास्क वर्कर्ज के लिए एक नई पॉलिसी लेकर आएंगे जिसमें 500 रुपये बढ़ाना या 1,000 रुपये बढ़ाना छोड़कर मिनिमम वेजिस की तरफ जाने का प्रावधान होगा। इस दृष्टिकोण से सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।**

एन0एस0 द्वारा ... जारी

01-9-2026/1200/NS-HK/1

प्रश्न संख्या : 4622

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने भी सैद्धांतिक रूप से बजट सेशन में इसका जिक्र किया था। संक्षेप में यही है कि क्या आपके माध्यम से मंत्री जी एश्योर करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में सी0आर0एफ0 के माध्यम से ठाकुरद्वारा से हमीरपुर वाया सुजानपुर सड़क के लिए धन की उपलब्ध करवाकर काम शुरू करवाएंगे?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को कहना चाहूंगा कि हम चाहते हैं कि प्रदेश की ओर से केंद्र को सी0आर0एफ0 के माध्यम से ज्यादा-से-ज्यादा सड़कें भेजी जाएं। शर्त यह है कि उसमें केवल एम0डी0आर0 सड़कें आती हैं। यह सड़क एम0डी0आर0 है और इसकी पूरी डी0पी0आर0 बना दी गई है मगर हमें अभी तक इसकी सैंक्शन प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए हम इसको जल्दी से री-प्रायोरिटाइज करके केंद्र सरकार को भेजेंगे। प्रदेश में और भी सड़कों की जहां-जहां भी एम0डी0आर0 हैं और उनकी रिक्वैस्ट भी माननीय विधायकों की आती है। हम उनको मुख्य मंत्री जी के माध्यम से लगातार केंद्र सरकार को भिजवाते रहते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश की लिमिट और कोटा फिक्स है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो सैस लगता है उसके तहत हमें ऑन एवरेज हर साल 150 करोड़ रुपये इस हैड के तहत मिलते हैं। **हम इसको भेज देंगे और हम प्रयास करेंगे कि अगले वित्तीय वर्ष में इसकी सैंक्शनिंग निश्चित तौर से लेकर आएंगे।** यह मुख्य मंत्री जी की भी प्राथमिकता है क्योंकि वहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र टौणी देवी है और आगे ब्यास नदी के ऊपर आपके विधान सभा क्षेत्र

का जो इलाका है उसको जोड़ता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी कनेक्टिविटी करवाना सरकार की प्राथमिकता है।

प्रश्न काल समाप्त।

1-9-2026/1200/NS-HK/2

अध्यक्ष : अब शून्य काल होगा। जीरो ऑवर छूट रहा है और बहुत सारे इश्यूज जो हैं...(व्यवधान) नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो ...(व्यवधान) नहीं, बेरूखी कहां? मैंने आपको आधा घंटा दिया। मैंने सारा टाइम कैलकुलेट किया है। अभी तक की सिटिंग में सबसे ज्यादा टाइम माननीय जय राम ठाकुर जी को मिला है। अब तक की जो सिटिंग्ज हुई हैं ...(व्यवधान) कोई बात नहीं, यह तो प्वाइंट ऑफ ऑर्डर में थोड़ी है। आप resort to the other methods. आपने मुझे शून्य काल में भी एक इश्यू दिया है। ...(व्यवधान) बहुत सारे इश्यूज हैं और बहुत सारे माननीय सदस्यों के बड़े इम्पॉर्टेंट इश्यूज रह जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं बनता है, फिर मैं रिजैक्ट कर दूंगा। फिर उसका क्या फायदा होगा? यह अभी आप जो प्वाइंट ऑफ ऑर्डर बोलेंगे वह इसकी एम्बिट में नहीं आएगा। मैंने सारा रूल देख लिया है। माननीय जय राम ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान इस तरफ ले जाना चाह रहा हूं कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से स्वाइन फ्लू के बहुत सारे मामले आ रहे हैं। स्वाइन फ्लू के जो मामले आ रहे हैं उनमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। पिछले कल मेरा आई0जी0एम0सी0, शिमला में जाना हुआ और मैंने देखा कि वहां पर पेशेंट की बहुत बड़ी तादाद है। क्या सरकार ने इस मामले में कोई संज्ञान लिया है? पिछले कल की जो खबर थी कि स्वाइन फ्लू के कारण 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। 8 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड पर आ गए हैं। क्या सरकार ने एहतियात के तौर पर कुछ इंस्ट्रक्शन्ज दी हैं? क्या इस दिशा में एहतियात के तौर पर कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए सरकार आगे बढ़ी है जिससे लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके? मुझे लगता है कि इस सारी चीज को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक न तो कोई इस

प्रकार का वक्तव्य आया है और न ही इस तरह का कोई संज्ञान लिया गया है। इस पूरे विषय में मुख्य मंत्री जी व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू की गंभीर स्थिति बनने जा रही है और हम इसको लेकर चिंतित हैं, उसके संदर्भ में आपने क्या कदम उठाने के लिए विचार किया है या किया ही नहीं है?

अध्यक्ष ------ आर0के0एस0 द्वारा-------जारी

01.09.2026/1205/RKS/HK-1

अध्यक्ष : यद्यपि यह विषय प्वाइंट ऑफ ऑर्डर की परिधि में नहीं आता है लेकिन this is an important reference, if this has come from the Leader of the Opposition, obviously the Government should respond. I would request the Hon'ble Chief Minister. मैंने पहले ही कह दिया है कि यह विषय इस परिधि में नहीं आता है। But this is an important issue. माननीय राजस्व मंत्री जी।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने वैसे तो रूलिंग दे दी है कि यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। यदि यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है तो फिर इस विषय को कैसे उठाया जाएगा? आपने इसे अस्वीकार कर दिया है। आपने बड़े संघर्षों के बाद शून्य काल शुरू किया है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। You could have raise this issue in Zero Hour. ये लोग दूसरों के शून्य काल का समय लेकर इसे प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से उठा रहे हैं। ये किसी नियम का पालन ही नहीं करते हैं। This is to be rejected. No answer should be given to it and the Zero Hour should be started.

Speaker : This issue converted into Zero Hour. I agree with the Hon'ble Revenue Minister that it doesn't fall within the purview of the Point of Order, yet it is a very important issue. ...(Interruption) Yet it is a very important issue. Let the Government respond to this. माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। ...(Interruption) Please, please take your seat. ...(Interruption) Please, please Thakur Sahib. ...(Interruption) माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय। Please, please

take your seat. …(Interruption) Please, please ….(Interruption) This is an important issue. Swine-flu is a very important issue and this has to be responded from the Minister or the Chief Minister or the Government should be respond to this.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह निःसंदेह जनहित से जुड़ा विषय है no doubt and as Hon'ble Members have questioned our dignity, I would also submit.

Hon'ble Speaker, really speaking that the Zero Hour, which have been started here.

01.09.2026/1205/RKS/HK-2

Speaker : Hon'ble Minister, this issue converted into Zero Hour, kindly respond to it now.

Health & Family Welfare Minister : Hon'ble Speaker, whatever issues are raised, that will go to the department concerned and they are attended to them. One cannot say that they are not attending them. But anyway since you have given direction that we have to respond to it and we respond. स्वास्थ्य विभाग ने इस विषय का संज्ञान लिया है। मैं जानता हूं कि कुछ मृत्यु के मामले सामने आए हैं but it is not necessary that it is because of Swine-flu. Swine-flu, no doubt. निःसंदेह स्वाइन फ्लू का खतरा गंभीर है and we have to take note of it. So, written directions have gone to all the health institutions across Himachal Pradesh that we have to be careful. And whatever the steps needed they have also been outlined. That we have to do it, definitely, yes.

Speaker : Before we take next issue, the Hon'ble Chief Minister wants to respond to this swine flu.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए विषय का उत्तर दे दिया है लेकिन इस संबंध में मैं भी कुछ बातें रखना चाहता हूं। बरसात के मौसम में स्वाइन फ्लू या विभिन्न प्रकार के वायरल रोग फैलते हैं।सरकार समय-समय पर डायरैक्शन्ज़ जारी करती है और इन विषयों पर कार्रवाई कर निरंतर निगरानी भी रखती है। पूर्व मुख्य मंत्री ने जो स्वाइन फ्लू मामलों के बारे में कहा है उसमें यह मामला एम्स, बिलासपुर से ट्रांसफर हुआ है। जब फ्लू की स्थिति गंभीर होकर नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो रोगी का जीवन बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाता है। वर्तमान समय में जो रिन्यूअल डिजीज़ या मौसमी बीमारियां होती हैं वे विशेष रूप से बरसात के महीनों में अधिक देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार जब पोलन गिरता है तो शिमला शहर में खांसी या जुकाम आदि बीमारियां फैलने का डर रहता है। सरकार सभी प्रकार के मामलों पर कार्य करती है। स्वाइन फ्लू का मामला एम्स से ट्रांसफर होकर यहां आया है। मुझे स्वाइन फ्लू के एक मामले की जानकारी मिली है लेकिन आपने दो मामलों का जिक्र किया है। हम इस विषय पर सभी प्रकार की एहतियात बरत रहे हैं। आपने हमारे ध्यान में जो अन्य बातें लाई हैं, हमारी सरकार उन पर भी गंभीरता से ध्यान देगी और आवश्यक इंस्ट्रक्शंस जारी करेगी। धन्यवाद।

01.09.2026/1205/RKS/HK-3

Speaker : Thank you. The remaining issues which were supposed to be raised yesterday, I am giving priority to those issues. माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राजन जी आप अपना शून्यकाल का विषय उठाइए। Do you remember what your issue is?

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक विषय सड़क और दूसरा स्पोर्ट्स से संबंधित था।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

01.09.2026/1210/बी.एस./ वाई.के.-1

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेलों को उपयुक्त प्रक्रिया के तहत सूची में शामिल करने बारे

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में मेरा सवाल हिमाचल प्रदेश के उन प्रतिभावान युवाओं के बारे में है जिन्होंने राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है।

ऐसा ही एक मामला हमारे विधान सभा क्षेत्र की एक प्रतिभावान बेटी मिली का है जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोर्फबॉल के टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है और अभी हाल ही में वह चैंपियनशिप में भाग लेकर वापस लौटी है।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को चाहे वे नेशनल लैवल पर हों या इंटरनेशनल लैवल पर जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है उनको सम्मानित किया जाता है। आपके माध्यम से मैं प्रदेश सरकार से चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए क्योंकि कुछ खेल ऐसे हैं जो प्रदेश के सूचीबद्ध खेलों में शामिल नहीं हैं। लेकिन उन खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और हमारे बहुत से युवा उन खेलों में भाग लेते हैं तथा प्रदेश का नाम रोशन करते हैं।

जैसे मिली ने हमारे विधान सभा क्षेत्र का नाम रोशन किया है और प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। मुख्य मंत्री जी ने भी उनको बधाई दी है और जगह-जगह से उनको बधाइयां मिल रही हैं। इसलिए मेरा विशेष आग्रह है कि जो खेल वर्तमान में प्रदेश की निर्धारित अथवा सूचीबद्ध खेल श्रेणियों में शामिल नहीं हैं लेकिन उन खेलों को राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मान्यता प्राप्त है और हिमाचल के खिलाड़ी उन खेलों में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं उन खेलों को भी उपयुक्त प्रक्रिया के तहत सूची में शामिल किया जाए।

साथ-ही-साथ ऐसे खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।

01.09.2026/1210/बी.एस./ वाई.के.-2

आयुष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी खेलों के माध्यम से जीतकर आते हैं उनको हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश सरकार में आदरणीय श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में वर्ष 2024 में अगर आपने देखा होगा तो समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स गेम्स में हमारे जो भी प्राइज मनी था उसमें हमने अभूतपूर्व वृद्धि की है और इसमें लगभग 200 प्रतिशत इंक्रीमेंट किया है।

मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि जो इंटरनेशनल लेवल की गेम्स हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कई गेम्स ऐसी हैं जो ओलंपिक्स में रजिस्टर्ड नहीं हैं। माननीय सदस्य ने अपनी व्यथा यहां पर जाहिर की है। हम सब उन खिलाड़ियों का मान-सम्मान रखते हैं क्योंकि और भी काफी सदस्यों की ओर से यह बात आती है। जिला चम्बा,कांगड़ा, सोलन और अन्य स्थानों से भी बात आती है कि इंटरनेशनल गेम्स में कई ऐसी गेम्स हैं जिनमें अभी तक सरकार द्वारा प्राइज मनी कम दी जाती है।

लेकिन ओलंपिक्स में न आने के कारण जो खेल सूची से बाहर हैं और जिनमें मान्यता प्राप्त खिलाड़ी हैं उनको भी शामिल करने का प्रयास किया जाए। इस मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि **यह जो विचार है सरकार के ध्यान में है यह सारा संज्ञान में है। आने वाले समय में आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि हमने इसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज की है। इसके ऊपर हम पूरी प्रणाली के अनुसार काम कर रहे हैं। जल्द ही आने वाले समय में इसके ऊपर विचारार्थ और अनुमोदन के लिए सरकार अपनी ओर से काम करेगी।**

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री विवेक शर्मा (विक्कू) जी अपना विषय रखेंगे।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

01.08.2026/1215/DT/HK-1

शून्य काल जारी-----

श्री विवेक शर्मा (विक्कू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि हमारे ऐलिमेंटरी विभाग में प्री-प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनको शामिल नहीं किया जा रहा है जिसके कारण सरप्लस स्टाफ होने के कारण काफी अध्यापकों को दूसरी जगह लगाया जा रहा है। परंतु वहां पर जो 20-25 प्री प्राइमरी के बच्चे हैं उनको उसमें काउंट नहीं किया जा रहा है। तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि उनको भी काउंट करके इसमें शामिल किया जाएगा? क्योंकि जब उनकी एनरोलमेंट नहीं की जा रही है तो केवल पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों की स्ट्रेंथ ली जा रही है जिसके कारण अध्यापकों को दूसरी जगह लगाया जा रहा है। इसलिए उनको भी शामिल करना जरूरी है क्योंकि वे अभी तक स्ट्रेंथ में नहीं आ रहे हैं।

अध्यक्षः माननीय शिक्षा मंत्री यहां नहीं हैं और रिस्पोंस कोई आया नहीं है। Now, since this matter has been raised by you and obviously will be an important issue, this Vidhan Sabha Secretariat has taken cognizance of this issue and we will take up this issue with the respective department.

01.09.2026/1215/DT/HK-2

Next issue will be raised by Hon'ble Member Shri Kewal Singh Pathania. He is not present.

Next issue will be raised by Hon'ble Member Shri Ram Kumar.

श्री राम कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है जो किसानों से जुड़ा हुआ है। हमारे मझौली में एक सीड कलेक्शन सेंटर है। लगभग चार-पांच महीने पहले, जैसे ही कनक की फसल आई, लोगों ने अपनी कनक सरकार को बेच दी, लेकिन उस कनक की धनराशि अभी तक संबंधित किसानों को नहीं मिली है। इसमें लगभग उस

एरिया के पांच-छः सौ किसान हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि इनकी पेमेंट समय पर और जल्दी करवाने की कृपा करें।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बहुत से किसान हैं जिन्होंने गंदम सीड के रूप में दिया है और उनकी काफी पेमेंट्स ड्यू हैं। हमने वित्त विभाग को लिखा है कि जल्दी से उन पेमेंट्स को रिलीज किया जाए ताकि किसानों को अगली फसल लगाने में सुविधा हो। अब खरीफ की क्रॉप जा रही है और इसके बाद रबी की क्रॉप लगेगी इसलिए उन किसानों को बीज उपलब्ध करवाना बहुत जरूरी है। हमने इस विषय को वित्त विभाग से टेक-अप किया है और इसको दोबारा भी परस्यू करेंगे ताकि जल्दी से उनकी पेमेंट हो सके। धन्यवाद।

01.08.2026/1215/DT/HK-3

Speaker : Now the next issue will be raised by Hon'ble Member Smt. Reena Kashyap. Please quickly raise your issue.

श्रीमती रीना कश्यप : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। नगर पंचायत राजगढ़ में कूड़ा निपटान हेतु डंपिंग साइट न होने के कारण वहां बहुत गंभीर समस्या पैदा हो गई है। जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। नगर पंचायत ने जो साइट डिसाइड की थी उसमें उस भूमि को लेकर बहुत विवाद है और वहां कोर्ट केस भी चल रहा है। कोठांगर के स्थानीय लोग की आपत्ति यह है कि वहां पर सौ मीटर के दायरे में पानी का स्रोत है और लोग उस पानी का प्रयोग पीने के लिए करते हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि कूड़ा निपटान हेतु कोई अन्य डंपिंग साइट सुनिश्चित की जाए ताकि वहां पर यह समस्या सुलझ सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो पहले ठोट कोलन कूड़ा क्षेत्र में कूड़ा संयंत्र में व्यय की गई 26 लाख रुपये है की जो राशि है वह जमीनी स्तर नजर नहीं आती क्योंकि वहां पर कार्य जीरो है। मेरा निवेदन रहेगा कि यह जनता का पैसा है और जमीनी स्तर पर वहां पर कोई कार्य नहीं हुआ है, इसलिए इसकी भी जांच की जाए।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, you want to respond? यह नगर परिषद पंचायत नहीं बल्कि नगर परिषद है। Since this is an important issue which you have brought to the notice of this Hon'ble House, we have taken cognizance of the issue. We will take up this issue with the respective Ministry and the department, and whatever the response we get, we will apprise you also and we see to it that the issue and the concern raised by you is properly attended by the respective department.

अब डॉक्टर जनक राज आपका प्रश्न संख्या 62 में भी था। हमने इसको जीरो आवर में ले लिया है। यह मणिमहेश यात्रा से जुड़ा विषय है, इसलिए हमने जीरो आवर में इसकी अनुमति दे दी है।

01.08.2026/1215/DT/HK-4

डॉ0 जनक राज : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस वर्ष प्रस्तावित मणिमहेश यात्रा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मणिमहेश यात्रा के प्रबंधों को लेकर जो लेट-लतीफी होती है उसके संबंध में मैंने अनेक बार सुझाव भी दिए हैं कि अगस्त के महीने में यह यात्रा होती है। इसके प्रबंध अगस्त में करने की बजाय अगर हम मई-जून से शुरू

एन0जी0 द्वारा जारी....

01.09.2026/1220/ए.जी.-एन.जी./1

डॉ0 जनक राज......... जारी

कर देंगे तो यात्रियों के लिए बहुत सुविधा होगी। आज भी जगह-जगह मार्ग टूट रहे हैं और हर दूसरे दिन खबर आ रही है कि यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। मेरा सरकार से आग्रह है कि पिछले वर्षों के अनुभवों से सीखते हुए आगामी वर्ष के लिए—इस

वर्ष तो यात्रा चार सितंबर से शुरू होने वाली है—कम-से-कम आगामी वर्ष में समय रहते उन सभी प्रबंधों को पूरा किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा वहां पर श्रद्धालुओं से तीन विभिन्न प्रकार के शुल्क लिए जा रहे हैं। पहला रजिस्ट्रेशन शुल्क है। दूसरा, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ई0डी0सी0 कमेटी बनाकर प्रत्येक श्रद्धालु से ले रहे हैं, वह 100 रुपये है। इसके साथ ही 50 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क है। इनके अलावा जो हेलीकॉप्टर सुविधा दी जा रही है, उसके लिए भी 100 रुपये कन्वीनियंस शुल्क लिया जा रहा है। इस प्रकार प्रति यात्री से 250 रुपये शुल्क लेना, मुझे लगता है कि यह तर्कसंगत नहीं है। हमारे चुनाव क्षेत्र के अधिकतर लोगों के लिए यह यात्रा केवल एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि इसके साथ व्यवसाय और रोजगार का भी बहुत बड़ा दायरा जुड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक परिक्रमा मार्ग है, जोकि ग्राम पंचायत कुगती से होकर जाता है। पिछले वर्ष वहां ठंड और बारिश की वजह से कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई थी। मेरा सरकार से आग्रह है कि वह छोटा-सा इलाका है और वहां के लोगों का रोजगार इस यात्रा से जुड़ा हुआ है। जो परिक्रमा मार्ग है, उस पर सरकार ने जो पाबंदी लगाई है, उसे हटाया जाए, क्योंकि लाहौल से मणिमहेश यात्रा के लिए आने वाले लोग भी इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं और स्थानीय लोग भी इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं।

01.09.2026/1220/ए.जी.-एन.जी./2

उस ग्राम पंचायत कुगती के कम-से-कम 25-30 लड़के टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करते हैं और वहां छोटी-छोटी दुकानें भी लगाते हैं। इससे उन्हें दो-ढाई महीने के लिए रोजगार मिल जाता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि परिक्रमा मार्ग पर जो सरकार ने पाबंदी लगाई है, एक तो उसे खोला जाए और साथ ही तीन विभिन्न प्रकार के जो शुल्क लिए जा रहे हैं, सरकार उस पर पुनर्विचार करे ताकि यात्रियों को

अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर जाने के लिए किसी भी प्रकार का अनावश्यक शुल्क न देना पड़े। धन्यवाद

01.09.2026/1220/ए.जी.-एन.जी./2

अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री, क्या आप इस पर कुछ बोलना चाहते हैं?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज ने एक बहुत ही अहम विषय को सदन में जीरो ऑवर के माध्यम से पेश किया है। यह मणिमहेश यात्रा पिछले वर्ष काफी त्रासदीपूर्ण रही। इसमें काफी लोगों को असुविधा हुई और काफी लोगों की जानें भी चली गईं। इस यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। परंतु जिस स्तर पर हमें इस यात्रा को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए, उसमें ट्रैक को ठीक बनाने की जरूरत है, रहने की व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है और यातायात व्यवस्था को भी बेहतर करने की जरूरत है। चम्बा से लेकर भरमौर के कुगती तक जो सड़क संपर्क है, इन सभी विषयों को लेकर दो-तीन बैठकें हमारे डिप्टी कमिश्नर स्तर पर की गई हैं। मैं भी चाहता था कि इस बैठक में जा पाऊं, परंतु किन्हीं कारणवश इस बार नहीं जा पाया। **इसमें जो-जो सुझाव दिए गए हैं, उन पर हम अवश्य विचार करेंगे।** हेलीटैक्सी को हमने पिछले वर्ष होली से शुरू किया था और इस बार दोबारा होली से हेलीटैक्सी के द्वारा इसे जोड़ा गया है। जहां तक कुगती पास से यातायात शुरू करने की बात है, कुछ सुरक्षा के दृष्टिगत इसे अभी चलाया नहीं गया है। इसको भी सुरक्षित बनाकर, ताकि वहां पर रेस्क्यू की टीमें ज्यादा-से-ज्यादा रख पाएं और जो-जो ट्रैक खराब हो गए हैं, उन पर इस बार भी काफी पैसा हमने लाडा से भी दिया है। **इसके अलावा वहां पर जो मंदिर ट्रस्ट है, हम चाह रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट का पैसा भी इस यात्रा की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाए, इसकी भी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।**

01.09.2026/1220/ए.जी.-एन.जी./3

Speaker: This is a very exhaustively replied by the Hon'ble Minister. We are grateful to you. Next issue is from Shri Sanjay Rattanji.

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो इश्यू थे, क्या उन दोनों को क्लब कर दिया गया है या दोनों पर अलग-अलग बोलूं?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, this is pertaining to 'नगर पंचायत और एम0सी0 के अंतर्गत बी0पी0एल0 परिवारों में शामिल करने बारे'. आपके दोनों विषय सेम हैं।

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री के ध्यान में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लाना चाहता हूं। जिस प्रकार से बी0पी0एल0, आई0आर0डी0पी0 पंचायतों में डाले जाते हैं

पी0बी0 द्वारा......जारी

01.09.2026/1225/AG/PB/1

श्री संजय रत्न जारी...

उसके अनुसार उनका इन्कम क्राइटेरिया पहले 17,500 रुपये होता था, फिर 35,000 रुपये हुआ और उसके बाद 50,000 रुपये हुआ तथा 'अपना परिवार सुखी परिवार' में मुख्य मंत्री महोदय ने इसे 75,000 रुपये कर दिया है। लेकिन पिछले 15 वर्षों से शहरी विकास विभाग में नगर पंचायत या एम0सी0 में बी0पी0एल0 और आई0आर0डी0पी0 में शामिल करने के लिए अभी भी 26,500 रुपये की आय सीमा निर्धारित है। शहर में रहने वाले व्यक्ति की आय गांव में रहने वाले व्यक्ति की अपेक्षा वैसे भी अधिक होती है और लोग इतना तो हाउस टैक्स ही दे देते हैं। अभी भी 26,500 रुपये की आय सीमा से अधिक आय होने पर

व्यक्ति को बी0पी0एल0 से हटा कर दिया जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इस आय सीमा को बढ़ाया जाए। जिस एनालॉजी पर पंचायतों में 17,500 रुपये से 35,000 रुपये, 35,000 रुपये से 50,000 रुपये और 50,000 रुपये से 75,000 रुपये किया गया है उसी एनालॉजी पर इसे भी बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपये किया जाए ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट बैठ जाइए। Now, the minimum income as per the BPL and IRDP families is Rs. 72,000/- to Rs. 75,000/-. So, why should we not revise the income criterion for all other categories? जैसे आंगनबाड़ी में 50,000 रुपये है। माननीय सदस्य ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में 26,500 रुपये की आय सीमा है। When the Government has considered that the minimum income of BPL families will be deemed to be Rs. 72,000/- to Rs. 75,000/-, this should be revised in the respective departments. So, why keeping it in the different manner. This is a very important issue.

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, मुलाजिम लकीर के फकीर होते हैं। जब आय सीमा 17,500 रुपये से 35,000 रुपये की गई, 35,000 रुपये से 50,000 रुपये की गई और अब सरकार ने इसे 75000 रुपये कर दिया है तो अर्बन बॉडीज़ में अभी भी 26,500 रुपये की आय सीमा क्यों है? इससे गरीब लोग अभी भी बी0पी0एल0 और आई0आर0डी0पी0 शामिल नहीं हो पा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि उसी एनॉलजी पर कम-से-कम एक लाख रुपये की आय सीमा करें ताकि लोग उसका लाभ उठा सकें।

01.09.2026/1225/AG/PB/2

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि जब कोई मुलाजिम नगर पंचायत या एम0सी0 से सेवानिवृत्त होता है तो उसके सारे रिटायरी बेनिफिट संबंधित नगर पंचायत या एम0सी0 से दिए जाते हैं, why not from department, पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी रिटायरी फंड्स या उनकी पेंशन है वह सारा सरकारी विभागों द्वारा दिया जाता है। फिर इसे एम0सी0 और नगर पंचायत से देने का क्या औचित्य है? कई नगर पंचायतें और कई

एम0सी0 इतनी गरीब हैं कि उनके पास पैसा ही नहीं होता और सारा फंड मुलाजिम ले जाते हैं जिससे उनके विकास कार्य रुक जाते हैं। इसलिए क्या सरकार इसको अपने अधीन लेकर रिटायर्ड कर्मचारियों के रिटायरी बेनिफिट, पेंशन, ग्रेच्यूइटी और अन्य सारे बेनिफिट विभाग की ओर से दिए जाने की व्यवस्था करेगी instead of concerned MCs or Nagar Panchayats.

Speaker: Hon'ble Minister, whether you want to respond? This is, in fact, a very important issue, which has been raised by the Hon'ble Member. The Vidhan Sabha has taken cognizance of this issue. We will take up this issue with the respective department and the Minister also.

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री संजय रत्न जी ने दो विषय सदन में उठाए हैं, उनमें एक आई0आर0डी0पी0 का इन्कम क्राइटेरिया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि बदलते समय के साथ जिस प्रकार हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इन्कम क्राइटेरिया बढ़ाया गया है उसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी इसे बढ़ाया जाना चाहिए। हम इसे निश्चित तौर से रिव्यू करेंगे।

अभी 'अपना परिवार सुखी परिवार' योजना शुरू होने जा रही है और मुख्य मंत्री जी इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं। इसलिए ग्रामीण परिवेश में तो यह हो ही रहा है। **हम इसे अर्बन एरिया में नगर पंचायत और नगर निकायों में इम्प्लीमैंट करने के लिए प्रयासरत रहेंगे।**

दूसरा, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि **the pension and the arrears of the retired employees is drawn from the kitty of the Municipal Council and Nagar Panchayats, निश्चित तौर से हम इसको भी रिव्यू करेंगे कि नगर पंचायतों के मामले में इसे डिपार्टमैंट और डायरेक्टोरेट की ओर से करवाया जाए।**

01.09.2026/1225/AG/PB/3

इसकी क्या प्रैक्टिस रही है और सरकार पर कितना बर्डन आता है इसकी पहले कंप्रिहैंसिव स्टडी करके if it is feasible, then definitely the department will take a call on it.

Speaker: This is right intervention.
Now, I would request the Hon'ble Member Sukh Ram Chaudharyji. Now, just one minute left. Randhir Sharmaji is also there. In the last, I will give you a chance.

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण सड़कों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

01.09.2026/1230/ए0एस0-ए0पी/-01

शून्य काल जारी .....श्री सुख राम चौधरी जारी .....

पोंटा साहिब में महत्वपूर्ण सड़कें NH-07, शिवपुर, बांगरन, पुगानी और खोदरी-माजरी है। इसकी लंबाई साढ़े 26 किलोमीटर है। इस सड़क में पिछले साढ़े तीन-चार साल में केवल सात-से-साढ़े सात किलोमीटर की टायरिंग हुई है। यह स्टोन क्रशर, माइनिंग और इंडस्ट्री एरिया है। इस सड़क से 24 पंचायतों के लोग गुजरते हैं। आज के समय में यह सड़क खड्ड में तब्दील हो चुकी है। अभी भी केवल साढ़े सात किलोमीटर सेक्शन हुए है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस सड़क पर विशेष ध्यान देते हुए रिपेयर के लिए स्पेशल पैसे दिए जाएं। दूसरी सड़क पुरुवाला, राजपुरा, क्लाथा, वड़ाणा, किलोड़ है। इसकी लंबाई 29.5 किलोमीटर है। इसके साथ एक सड़क रामपुरा घाट, नवादा, मानपुर- दयोड़ा है, जिसकी लंबाई साढ़े आठ किलोमीटर है। इसमें भी पिछले साढ़े तीन-चार साल में केवल

साढ़े सात किलोमीटर की टायरिंग हुई है। यह भी इंडस्ट्री एरिया है। यहां कम-से-कम 25-26 स्टोन क्रशर हैं और माइनिंग एरिया भी साथ ही है। माइनिंग की बहुत-सी गाड़ियां इस क्षेत्र से आती हैं। सड़कों की हालत बहुत दयनीय है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसके लिए विशेष रूप से पैसे का प्रबंध किया जाए ताकि लोगों को आने-जाने में सुविधा हो सके। एक सड़क राजपुरा-से-बनौर है। वहां चार-पांच माइनिंग साइट हैं और वहां से पचास-पचास टन मटेरियल जाता है। इसी तरह जो स्टोन क्रशर एरिया है, वहां ट्रॉले चलते हैं और सात-सात क्विंटल और टनों के हिसाब से मटेरियल जाता है। सड़कों की हालत बहुत खराब है और उन पर चलना भी बहुत मुश्किल है। मैं विशेष रूप से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मैंने जिन चार सड़कों का वर्णन किया है, उन्हें ठीक किया जाए। प्रदेश सरकार को प्रति वर्ष इन सड़कों से 70-से-75 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आता है। इसलिए विशेष ध्यान देकर इन सड़कों की स्पेशल रिपेयर करवाने का मेरा आपसे आग्रह है।

01.09.2026/1230/ए0एस0-ए0पी/-02

लोक निमार्ण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पोंटा साहिब से माननीय विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री सुख राम चौधरी जी ने अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित कई सड़कों का जिक्र किया है। जिनमें भानपुर, शिलपुर, कोड़री, जो एम0डी0आर0 (Major District Road) जोकि 26 किलोमीटर है। इसके साथ पुरावाला, अंबोहा, राजपुरा, किलोड़ की सड़क है जोकि 29 किलोमीटर की है। इन दोनों सड़कों की साढ़े सात किलोमीटर और साढ़े सात किलोमीटर ए0एम0पी0 (Annual Maintenance Programme) सैंक्शन हुई है। मैंने माननीय सदन को पहले भी सूचित किया था कि मार्च-अप्रैल-मई महीने में जो हमारी ए0एम0पी0, उसमें बिटुमिन की कीमत में हुई एस्केलेशन की वजह से निर्धारित टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए। मगर अब, जैसा मैंने पहले भी सदन में कहा है कि हम पूरे प्रदेश में मॉनसून सीजन के बाद ए0एम0पीज0 के टारगेट हमारे विभाग ने फिक्स कर लिये हैं और हम इसको करने जा रहे हैं। इसमें मैंने पहले भी जिक्र किया कि पी0डी0एन0ए0 के तहत हम 770 किलोमीटर और कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में 2,502 किलोमीटर, जिसमें विभिन्न हेड्स में

हमारी टायरिंग होनी है। उसे हम इनिशिएट करने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में माननीय विधायक श्री चौधरी साहब के इलाके पोंटा साहिब में हमने इस वित्तीय वर्ष में 36 किलोमीटर सड़कों की ए0एम0पी0 सैंक्शन कर दिया है। **इसलिए मैं आपके माध्यम से विधायक जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन-जिन सड़कों का आपने जिक्र किया है, उनमें हम निर्धारित समय में टायरिंग का प्रोसेस करने का प्रयास करेंगे।** इसमें मेरा कहना यह है कि आपने कई ट्रॉलर्स का जिक्र किया है, जो गाड़ियां इन सड़कों पर जा रही हैं और उनमें लोडिंग हो रही है। इसमें विशेष रूप से चाहे माइनिंग की गाड़ियां आ रही हैं या गाड़ी क्रशर से आ रही हैं। इसमें उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ओवरलोडिंग करके गाड़ियां चलाएंगे तो सड़कों का हाल बेहाल ही होगा। इसमें entirely the Public Works Department cannot be blamed for it. There has to be accountability from the mining also. They have to see and ensure कि गाड़ियों की जो निर्धारित क्षमता और लोडिंग कैपेसिटी है, उसी के हिसाब से गाड़ियां चलाई जाए। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, धन्यवाद।

01.09.2026/1230/ए0एस0-ए0पी/-03

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी का इश्यू है। But it will be listed tomorrow. ...(Interruption) It will be listed tomorrow on the top and I will be... (Interruption)Hon'ble Member Shri Randhir Sharma Jee, please take your seat. Why I am not allowing it because the Hon'ble Minister is not here. I am requesting all the Hon'ble Ministers kindly respond to these issues, please, please, please. Because we are sending these notices to the respective departments every day and thereafter we are listing it. They are very important issues pertaining to the constituencies of the Hon'ble Members. These are very small issues, and the ministers should respond to it. Instead, you say asking a discussion under Rule -61, 62, 63, 130. So, this is my request, and it should be

taken very seriously, otherwise, I will be taking it very seriously. Thank you very much.

शून्य काल समाप्त।

Speaker : Now the next item which I am taking up that कागजात सभा पटल पर रखें जाएंगे।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

01.09.2026/1235/AT/AS/01

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब उद्योग मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 51वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें, वर्ष 2023-24 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 45(4) के अन्तर्गत डॉ0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन का वार्षिक लेखाओं पर तैयार ऑडिट एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब आयुष मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

आयुष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 (01.04.2023 से 31.03.2024 तक) (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

01.09.2026/1235/AT/AS/02

<u>सदन की समिति के प्रतिवेदन</u>

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्री राकेश कालिया, सभापति, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, प्राक्कलन समिति, के प्रतिवेदनों की एक-एक की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1. समिति का 17वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में जल शक्ति विभाग के अन्तर्गत जल जीवन मिशन की संवीक्षा पर आधारित है;

2. समिति का 18वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की संवीक्षा पर बने समिति के तृतीय मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) में

अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा योजना विभाग से सम्बन्धित है;

3. समिति का 19वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्राक्कलन समिति द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियन्त्रण, नमूना प्रक्रिया एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन की संवीक्षा पर आधारित तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है; और

4. समिति का 21वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) पर बने समिति के चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित है।

01.09.2026/1235/AT/AS/03

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्षः अब नियम-62 के अंतर्गत विषय उठाए जाएंगे। इसमें दो विषय हैं। पहला माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी जी का है और दूसरा माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी का है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज बिल बहुत इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए जो इश्यू आप नियम-62 के अंतर्गत इस सदन में उठा रहे हैं मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि you should be very specific about Rule-62. अब मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी जी से कि अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री विनोद सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 29 और 30 अगस्त तथा पिछले कल 31 अगस्त को हुई भारी वर्षा से परवाणू और नज़दीकी गांवों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सर, अभी जो हाल ही में बारिश हुई है, रिट्रीटिंग मॉनसून के दौरान हमारे पूरे परवाणू क्षेत्र में बहुत अधिक बारिश हुई। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें हमारे लगभग 16 गांव प्रभावित हुए हैं। इनमें बहुत सारी रिटेनिंग वॉल्स गिर गई हैं। पूरा परवाणू, जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें इस त्रासदी का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिला है।

(सभापति, श्री संजय रत्न पदासीन हुए।)

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। कामली गांव एक तरह से पूरी तरह वंचित हो गया था। वहां के सारे पुल बह गए थे। माननीय मुख्य मंत्री जी का काफिला चंडीगढ़ से शिमला की ओर जा रहा था। उस दौरान माननीय मुख्य मंत्री जी वहां रुके और आज उस पर कार्रवाई हुई है। कामली गांव की जो सड़क टूट गई थी, उसे अब NH के साथ जोड़ दिया गया है। अभी-अभी मुझे हमारे SDM ने जानकारी दी है कि उन्होंने उस रोड को NH के साथ जोड़ दिया है। NH की ओर से भी इसमें जो कन्फर्मेशन लेना था और एक लेटर की अप्रूवल लेनी थी कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग के साथ कामली गांव

01.09.2026/1235/AT/AS/04

को जोड़ दिया जाए, वह प्रक्रिया की गई है। इससे जो 16 गांव बाहर हो गए थे और एक तरह से वंचित हो गए थे, उन्हें फिर से जोड़ा जा सकेगा।

मैं हमारे SDM और DSP का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतने बड़े ट्रैफिक जाम को सॉल्व करने और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत बड़ा काम किया है।

सर, पिछले कल तक्साल गांव में बहुत बड़ी आपदा आई थी। हालांकि हम घर-घर जाकर आए थे और सभी जगहों से मलबा भी हटवा लिया था, लेकिन आज फिर से उसी तरह की बारिश हुई है और हमारे बहुत से लोग उससे प्रभावित हुए हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब एक घर में इस तरह की आपदा आती है या पूरे गांव में इस तरह की आपदा आई है, तो अब जो मिट्टी और मलबा आ रहा

है, उसको रिस्टोर करने के लिए स्पेशल फंड की मैं सरकार के समक्ष डिमांड करना चाहता हूं। इसी तरह मसूलखाना गांव में काफी रिटेनिंग वॉल्स है, जो गांव के ऊपर हैं पर वह टूट गई हैं और इस इलाके में बहुत थ्रेटनिंग सिचुएशन उत्पन्न हो गई है। इसी तरह चंद्रायणी गांव में भी हमें यह दिक्कत आई है। सर, टिम्बर ट्रेल के साथ में हमारा एक गांव है, उसमें

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी.....

01.09.2026/1240/av/dc/1

श्री विनोद सुल्तानपुरी----------- जारी

टिम्बर ट्रेल के साथ लगते गांव में भी हमें बहुत दिक्कतें आई हैं। यह बारिश केवल कॉन्संट्रेटिड एरिया में ज्यादा हुई है इसलिए क्लाउड ब्रस्टिंग फिनोमिना के संदर्भ में एक स्टडी करने की आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि स्पेसिफिकली एक टास्क फोर्स बनाकर मशीनरीज और लैबर को भेजा जाए ताकि वे वहां पर लोगों की मदद कर सकें। वहां पर हमारे साथियों ने निर्णय लिया है कि वे आज प्रभावित गांवों में जाकर अपनी ओर से श्रमदान करेंगे। परंतु मेरा यह अनुरोध है कि सरकार उसमें एक टास्क फोर्स गठित करे।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

इसी तरह से हमारे अन्य सेक्टर्ज भी हैं और मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर कई जगह नालों के ऊपर इण्डस्ट्रीज बनी हैं तथा पानी उन नालों को क्रोस करके बह रहा है। मेरे हिसाब से इस प्रकार की एनक्रोचमैंट्स लाइफ थ्रैटनिंग वाली होती हैं। अतः इस प्रकार की एनक्रोचमैंट्स के संदर्भ में सरकार को संज्ञान लेना होगा। हमारे परमाणू बस स्टैंड को भी बहुत नुकसान पहुंचा है और वहां बहुत ज्यादा मलवा आया है। हालांकि वहां के अधिकारीगण ने उसमें अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, जिसके लिए मैं सदन के माध्यम से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सबकी सेफ्टी पर

ध्यान दिया। अभी तक वहां पर लगभग 9 लाख रुपये के नुकसान दर्शाए गए हैं। वहां टकसाल गांव के पास जो नाला चलता है, वह भी बहुत थ्रैटनिंग वाला है। परमाणू-टकसाल-अम्बोटा का नाला बहुत ज्यादा हिट कर रहा है और मुझे लगता है कि इसको रिटेन करने की आवश्यकता है। वहां पर चक्की मोड़ पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग वालों ने पहाड़ी की तरफ ड्रिल करके उसको रिटेन करने का प्रयास किया है। वहां की स्वॉयल फॉर्मेशन रिवर बैड की तरह है और वहां जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग द्वारा उसको प्लग करने का प्रयास किया गया है, वह मुझे लगता है कि एक फेल्ड एक्सपेरिमैंट किया गया है। वहां पर सिल्ट जालों में फंस जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए हिमाचली तरीकों को अपनाकर वहां के स्ट्राटा के संदर्भ में अण्डरस्टेडिंग का सही इस्तेमाल करके इस

01.09.2026/1240/av/dc/2

स्पेसिफिक खड्ड के लिए राशि उपलब्ध करवाई जाए। वहां हमारी विंटेज रेल लाइन को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। इसलिए इस बारे में जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि यह डिजास्टर एक कॉन्संट्रेटिड एरिया में हुआ है। जिसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक टास्क फोर्स दी जाए और इसको फाइनेंशियली देखा जाए ताकि इसको एकदम रिकवर किया जा सके। वहां पर जो अल्ट्रनेट रोड्ज हैं उनके लिए हमें फण्ड्ज दिए जाएं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने हमारी बात को सुना और मैं समझता हूं कि आप सरकार को इस संदर्भ में आदेश करें कि इस बारे में शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।

01.09.2026/1240/av/dc/3

अध्यक्ष : अब माननीय राजस्व मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी ने नियम-62 के अंतर्गत इनके निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत परमाणू तथा उसके नज़दीक के गांवों में दिनांक

29.08.2026 को भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान का जिक्र किया है। यह सही है कि इस बार बरसात में न केवल प्रदेश के सोलन जिला अपितु सभी जिलों में इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। परंतु फिर भी पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से काफी कम नुकसान हुआ है। लेकिन जहां पर भी नुकसान हुए हैं, वे वहां के एरियाज के लिए तो बहुत हैं। परमाणू में दिनांक 29 व 30 अगस्त, 2026 को जो भारी बारिश हुई, उससे वहां बहुत नुकसान हुए और उससे आस-पास के गांव भी बहुत प्रभावित हुए। इसमें हमारे सभी विभाग जिसमें लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति

टी सी द्वारा जारी

01.09.2026/1245/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

माननीय राजस्व मंत्री .... जारी

बिजली बोर्ड तथा नगर परिषद के लोग शामिल हैं, ने तुरंत कार्रवाई की। इसके परिणामस्वरूप समय रहते आपदा से संबंधित काफी कार्य किए गए। यह ठीक है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वहां आठ सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनमें परवाणू-कसौली सड़क, परवाणू-खड़ीन-बनासर सड़क, सैक्टर-4 से चंद्रनैना सड़क, संपर्क सड़क टकसाल, संपर्क सड़क अम्बोटा, ओल्ड कालका-कसौली सड़क तथा ओल्ड एन0एच0-22 से टी0टी0आर0 चौक तक की सड़कें शामिल हैं। अभी नवीनतम स्थिति यह है कि इनमें से सात सड़कों को खोल दिया गया है और तीन जे0सी0बी0 मौके पर काम कर रही हैं क्योंकि 29 की रात को दोबारा बारिश हुई और उसके कारण पहले किए गए कार्यों को भी नुकसान पहुंचा है।

जहां तक दूसरे विभागों की बात है, जल शक्ति विभाग ने अपना काम कर दिया है और पानी रिस्टोर कर दिया गया है। इसी तरह बिजली विभाग ने भी प्रभावित डी0टी0आर0 को काफी हद तक ठीक कर दिया है परंतु अभी काम लगातार चला हुआ है। हमारे अधिकारी चाहे प्रशासन के हों या हमारे विभागों के हैं, सभी मौके पर काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक टास्क फोर्स गठित करने की बात कही है। हम डिप्टी कमिश्नर, सोलन को निर्देश देंगे कि उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर मौके पर जाएं और यह देखे कि इतना वर्षा का पानी परवाणू शहर के अंदर किन कारणों से आया है। यदि एनक्रोचमैंट्स के कारण कोई क्षति हुई है तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे मिटिगेशन के तहत जो भी कार्रवाई आवश्यक होगी, उसे करने का प्रयास किया जाएगा।

जहां तक बस स्टैंड की बात है उसे भी ठीक किया जाएगा। साथ ही सोलन डिस्ट्रिक्ट के लिए 13 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि एन0डी0आर0एफ0 और एस0डी0आर0एफ0 के अंतर्गत उपलब्ध करवा दी गई है। उस धनराशि से भी आपदा से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। इसके साथ ही पी0डी0एन0ए0 (Post-Disaster Needs Assessment)

01.09.2026/1245/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

के तहत मूल्यांकन करके जो सड़कें इसमें डालने के योग्य हैं या हमारे अन्य एसैट्स जिनको नुकसान पहुंचा है उनका कार्य भी किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि मेरा लिखित जवाब काफी विस्तृत है और सदन का समय बचाने के लिए मैं यह पूरा जवाब सभा पटल पर ले कर रहा हूं और उन्हें भी उपलब्ध करवा देंगे। इसमें यदि कोई सुझाव या कमी हो तो वे मुझे बताएं और मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद।

01.09.2026/1245/टी0सी0वी0/डी0सी0-3

Speaker: Thank you very much, Hon'ble Minister. Very exhaustive reply. This has satisfied the Hon'ble Member. ...(Interruption). In any case, if the Hon'ble Member is still not satisfied, you can read the reply thereafter you come to the Vidhan Sabha. ...(Interruption). No, I will not allow you. No clarification is

required. The next issue will be raised by Hon'ble Member Shri Bikram Singh Ji.

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम-62 के अन्तर्गत 18 अगस्त, 2026 को बांगडधार, कमराऊ में खनन के दौरान तीन मजदूरों के दबने से उत्पन्न स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 18 अगस्त, 2026 को शिलाई विधान सभा क्षेत्र की तहसील कमराऊ के बांगडधार में लाइमस्टोन की माइन में माइनिंग के दौरान अंडरकटिंग व ब्लास्टिंग के कारण डांक गिरने से तीन लोगों के दबने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। वहां दो ट्रक और एक जे0सी0बी0 मशीन के दबने की घटना भी हुई है और प्रमुख अखबारों में भी इसकी न्यूज़ प्रकाशित हुई है। मैं मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि बरसात के दिनों में यह घटना हुई है। क्या बरसात के दिनों में माइनिंग करने की परमिशन है? क्या माइनिंग लीज के कागज पूरे थे और उनकी परमिशन थी? वहां कौन-कौन से लोग माइनिंग कर रहे थे? इसमें मरने वाले दो व्यक्ति नेपाल के हैं और एक बड़वास पंचायत का है। उसके परिवार में एक बुजुर्ग मां, तीन छोटी बेटियां, एक छोटा बेटा और पत्नी है। अभी तक इस घटना पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, उसके बारे में बताएं।

अध्यक्ष महोदय, इस माइन की वर्टिकल हाइट बहुत ज्यादा है। जब वर्टिकल हाइट बहुत ज्यादा होती है तो क्या डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन एंड सेफ्टी की ओर से इस माइन के संबंध में कोई ऑब्जर्वेशंस थी? क्या डी0जी0एम0एस0 ने इस माइन को बंद करने के लिए या इसमें माइनिंग करने के संबंध में कोई सजैशन्ज या ऑब्जर्वेशन्ज दी थी? कृपया करके

एन0एस0 द्वारा ... जारी

1-9-2026/1250/NS-HK/1

श्री बिक्रम सिंह-------जारी

उसके बारे में भी पूरी डिटेल बताएं ताकि बरसात के मौसम में माइनिंग के विषय में भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय उद्योग मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय बिक्रम सिंह जी ने इस इश्यू को सदन में रखा है और मेरे पास इसका बड़ी डिटेल में रिप्लाई आया है लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगा। यह घटना 18 अगस्त को दिन में हुई है और इस घटना में तीन लोगों की जान चली गई है। यह माइन वर्ष 1984 में सैंक्शन हुई थी। यह माइन धर्म सिंह जी के नाम पर सैंक्शन हुई थी। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सत्या तोमर के नाम पर ट्रांसफर हुई है और यह लीज 50 वर्षों तक यानी वर्ष 2034 तक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेजर मिनरल में रेत-बजरी आदि आते हैं और मेजर मिनरल का कंट्रोल भारत सरकार करती है। उसमें चाहे माइनिंग प्लान अप्रूव करना हो या सेफ्टी मेजर्स हों तो इनका नियंत्रण भारत सरकार के पास है। राज्य सरकार माइनर मिनरल को देखती है।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुखद घटना हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक व्यक्ति जिसकी डथ हुई है वह बड़वास गांव का है। मैं तीन दिन पहले उसके घर गया था। वह परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि यह माइन एरिया बहुत बड़ा है। इसके कुछ पोर्शन में धारा-22 (सी) लगाई गई थी। धारा-22 (सी) का मतलब यह है कि Director General of Mines Safety ही मॉनिटरिंग और कंट्रोल करता है, उन्होंने उस एरिया में धारा-22 (सी) लगाई थी जिसमें बैंच की हाइट 6 मीटर से ज्यादा हो। पूरी माइन में धारा-22 (सी) नहीं लगाई गई थी। पूरी माइन क्लोज नहीं थी। एक पोर्शन था जिसमें धारा-22 (सी) लगाई गई थी। उन्होंने माइनिंग वालों को कहा था कि इसकी हाइट रिड्यूस करें और बैंच बनाकर इसकी हाइट रिड्यूस करें ताकि इसमें खतरा न रहे। यह बात ठीक है कि मेजर मिनरल की माइन्स में माइन डवलपमैंट का काम बरसात के दौरान किया जाता है और ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया जाता है क्योंकि बारिश में सड़क बंद हो जाती है तथा सड़कों में रुकावट रहती है। इसलिए माइनिंग मटीरियल को माइन एरिया से नहीं

1-9-2026/1250/NS-HK/2

निकाला जाता है। As per the Mine Safety डवलपमैंट का काम चला हुआ था। जो माइनिंग प्लान Indian Bureau of Mines, Government of India के अंडरटेकिंग Ministry of Mines के Indian Bureau of Mines द्वारा अप्रूव किया जाता है। मेजर मिनरल का माइनिंग प्लान Indian Bureau of Mines अप्रूव करता है और यह प्लान पांच वर्षों के लिए होता है और उसके मुताबिक माइनिंग करनी पड़ती है। जब 18 अगस्त को यह घटना हुई तो उसी दिन एफ0आई0आर0 की गई। वहां पर प्रशासन के लोग गए और उस दिन भारी बारिश थी इसलिए बॉडीज को निकालने का कार्य उस दिन नहीं हो पाया। धुंध भी थी और ऊपर से पत्थर आ रहे थे। अगले दिन बॉडीज को निकाला गया। इनमें एक व्यक्ति बड़वास गांव का था और दो नेपाली लेबर थे। जब मैं उनके घर गया तो पता चला कि जब स्लाइड होने जा रहा था तो उस वक्त एल0एंड0टी0 के ड्राइवर ने भी बड़वास गांव के ड्राइवर को कहा कि ऊपर से स्लाइड हो रहा है, तुम आ जाओ लेकिन वहां उसका ट्रक खड़ा था। वह उसको निकालने के लिए ट्रक में बैठ गया और ऊपर से पत्थरों के स्लाइड्ज इतने जोर से आए कि ट्रक के आगे का रास्ता बंद हो गया और वह मलबे में दब गया।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुखद घटना है और इसमें एफ0आई0आर0 भी दर्ज कर दी गई है। माइन सेफ्टी के लोग भी वहां आए हैं और Indian Bureau of Mines के लोग भी आए हैं। वे इसकी छानबीन कर रहे हैं कि इसके क्या कारण रहे हैं? हमारे माइनिंग डिपार्टमैंट का मानना है कि माइन की हाइट को शॉर्ट करने और रिड्यूस करने के लिए as per the directions of the Mine Safety कार्य किया जा रहा था। अब इसमें क्या हुआ है, माइन्स का स्ट्रैटा आमतौर पर लाइमस्टोन बैंड में होगा और इकट्ठा होगा मगर इसका ऊपर वाला पोर्शन स्लैब्ज में था। माइन का अप्पर पोर्शन स्लैब्ज में था। बारिश ज्यादा होने की वजह से पानी के प्रैशर के कारण पानी उसमें चला गया और सारा अप्पर पोर्शन नीचे बैठ गया। अभी तक की जो रिपोर्ट है और अभी तक विभाग का जो मानना है वह यह है कि हाइड्रॉलिक प्रैशर यानी पानी के प्रेशर की वजह से ऊपर वाला पोर्शन स्लाइड हुआ है। हमने एफ0आई0आर0 कर दी है और माइन वालों को भी कहा है। माइन को बंद कर दिया है और कहा है कि जब तक Indian Bureau of Mines और माइन सेफ्टी वाले आपको डायरेक्शन नहीं देते हैं तब तक माइन को न खोला जाए।

1-9-2026/1250/NS-HK/3

अब वे उनको दोषी पाते हैं या नहीं पाते हैं तथा क्या रिपोर्ट देते हैं, यह उनकी रिपोर्ट पर निर्भर होगा। अभी हमने माइन को बंद कर दिया है और as per the manual उचित कम्पेन्सेशन तीनों व्यक्तियों को सरकार द्वारा दे दिया गया है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय बिक्रम सिंह जी कृपया संक्षिप्त में पूछें।

आगे -----आर0के0एस0 द्वारा-------जारी

01.09.2026/1255/RKS/HK-1

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वहां जो धारा 22-C लगाई गई थी क्या उसकी कोई वायलेशन हुई है? दूसरा, क्या बरसात के दिनों में माइनिंग की जा सकती है? सामान्यतः बरसात के दौरान माइनिंग बंद रहती है तो वहां माइनिंग क्यों हो रही थी? क्या माननीय मंत्री जी इस विषय की पूरी जानकारी देंगे कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है और राज्य सरकार की ओर से इसमें कौन शामिल होगा? यह ठीक है कि केंद्रीय विभाग अपनी जांच करेगा लेकिन यह राज्य का भी विषय है।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि एक पर्टिकुलर पोर्शन पर धारा 22(3) लगाई गई थी। यदि किसी क्षेत्र पर 22(3) लगाई जाती है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उस साइट को बिल्कुल छुआ ही नहीं जा सकता। वहां जो मिनरल और मटीरियल उपलब्ध है उसे एक्सट्रेक्ट करना पड़ता है और वहां as per the Director General of Mines Safety उस क्षेत्र की ऊंचाई को कम करने के लिए काम किया जा रहा था। जहां तक बरसात के दिनों में माइनिंग का प्रश्न है सामान्यतः मेजर मिनरल की माइन्स जैसे कोल, लेड, आयरन और लाइमस्टोन की माइन्स में बरसात के दौरान माइन

डवलपमैंट के कार्य किए जाते हैं। इनमें प्लांटेशन, चैक डैम निर्माण तथा बैंचों की ऊंचाई कम करने जैसे कार्य शामिल होते हैं। माइनर मिनरल में नदियों और नालों के किनारे माइनिंग पर प्रतिबंध लगाया जाता है किंतु मेजर मिनरल रूल्स के अंतर्गत आने वाली माइन्स में हमारा नियंत्रण कम होता है और वहां बरसात के दौरान भी माइन डवलपमैंट का कार्य किया जाता है। यह कोई प्लांड गतिविधि नहीं थी और न ही इसमें किसी प्रकार की त्रुटि का मामला प्रतीत होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उस क्षेत्र का स्ट्रेटा स्लेट टाइप पत्थरों वाला है। बरसात के दौरान अधिक वर्षा और हाइड्रॉलिक प्रैशर के कारण ऊपरी भाग का स्लाइड होकर नीचे आ जाता है। इसी प्रकार की घटना वहां भी उत्पन्न हुई है। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसमें एफ0आई0आर0 भी दर्ज कर ली गई है। Director General of Mines Safety और Indian Bureau of Mines अपनी तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यदि उनकी रिपोर्ट में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो according to the report we will do it. We will take suitable action and we will also ensure कि हिमाचल प्रदेश की मेजर मिनरल माइन्स में इस प्रकार की घटना दोबारा न हो।

01.09.2026/1255/RKS/HK-2

सरकारी विधेयकों को वापिस लेने बारे प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब माननीय राजस्व मंत्री भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 23) को वापिस लेने बारे प्रस्ताव करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 23) को वापिस लिया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 23) को वापिस लिया जाए।

तो प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 23) को वापिस करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार।

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 23) वापिस हुआ।

अध्यक्ष : अब माननीय राजस्व मंत्री भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4) को वापिस लेने बारे प्रस्ताव करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4) को वापिस लिया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4) को वापिस लिया जाए।

तो प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4) को वापिस करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार।

01.09.2026/1255/RKS/HK-3

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4) वापिस हुआ।

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरः स्थापना

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अब मुख्य मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10) पुरःस्थापित हुआ।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

01.09.2026/1300/बी.एस./ वाई.के.-1

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब मुख्य मंत्री शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करता हूं।

01.09.2026/1300/बी.एस./ वाई.के.-2

अध्यक्ष : शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13) पुरःस्थापित हुआ।

Now, if you allow me. I will introduce the rest of the Bills also. If you want to go for a lunchbreak that can also be done. So, what is the consensus; introduce कर दें?

अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अब मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करता हूं।

01.09.2026/1300/बी.एस./ वाई.के.-3

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14) पुरःस्थापित हुआ।

अध्यक्ष : अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 15) पुरःस्थापित हुआ।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

01.09.2026/1305/डीटी/वाईK-1

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब राजस्व मंत्री भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 12)को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 12) पुरःस्थापित हुआ।

अध्यक्ष : अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

01.09.2026/1305/डीटी/वाईK-2

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) पुरःस्थापित हुआ।

अब माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न 2.05 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

01.09.2026/1415/ए.जी.-एन.जी./1

(माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनावकाश उपरांत 02:15 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-130 के अंतर्गत चर्चा होगी और जो विषय कल चर्चा में था 'युवाओं के लिए रोजगार सन्दर्भित गारंटी के कार्यान्वयन बारे', इसी पर आगे चर्चा होगी। अभी 6 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है और सभी को काफी समय मिला है। इन 6 माननीय सदस्यों ने 15, 13, 18, 19, 29 और 30 मिनट का समय लिया है। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी की ओर से सूची आ गई है, जिसमें 9 माननीय सदस्यों के नाम हैं। कांग्रेस की तरफ से सूची तो अभी आई नहीं है। क्योंकि लास्ट स्पीकर, यानी अंतिम माननीय सदस्य जिन्होंने चर्चा में भाग लिया था, वे श्री राम कुमार जी थे और कांग्रेस पार्टी से थे। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरुआत होगी। So, I would request Hon'ble Shri Satpal Singh Satti ji to take part in the deliberations. माननीय सदस्य, संक्षिप्त में

अपनी बात कहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कार्यसूची में आगे भी बहुत सारे विषय लगे हैं और नियम-61 के तहत भी विषय लगे हैं।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत जो विषय माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा और अन्य साथियों ने रोजगार से संबंधित उठाया है, उस पर चर्चा के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विशेष रूप से जो हमारी युवा पीढ़ी अलग-अलग कॉलेजों व यूनिवर्सिटीज़ और अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस में शिक्षा ग्रहण कर रही है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है।

01.09.2026/1415/ए.जी.-एन.जी./2

हम सब जानते हैं कि हर परिवार व पैरेंट्स के लिए भी यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस तरह उनका बच्चा सरकारी नौकरी के अंदर एडजस्ट हो।

अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, यह भी बहुत मुश्किल है। हम सब लोग इसे मानते हैं। उसके बावजूद भी जो सरकारी नौकरियां हैं, वे समय-समय पर निकलती रहनी चाहिए। कोई खाली पोस्ट न रहे और अगर रहती है तो उसका दो तरफ से नुकसान होता है। अध्यक्ष महोदय, अगर खाली पोस्ट रहती है तो उसके कारण हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं या कोई भी अन्य दफ्तर हैं, वहां पर काम का ज्यादा बोझ होने के कारण जो कर्मचारी उस समय वहां ऑफिस के अंदर होते हैं, उनको भी दिक्कत आती है और जो युवा शक्ति या जो नौजवान साथी शिक्षा ग्रहण करके घरों के अंदर बैठे हैं, चाहे गांवों के अंदर हों या शहरों के अंदर, उनको भी दिक्कत रहती है क्योंकि समय पर उनकी नौकरी नहीं लगती है। जिसके कारण आजकल परिवारों के अंदर भी बड़ी असमंजस की स्थिति चल रही है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, जब नौकरी देर से निकलती है—मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बी0एड0 या इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और चार साल के बाद नौकरी निकली—तो उसमें मैक्सिमम यही रहता है कि जो व्यक्ति अभी-अभी पास आउट होकर निकलते हैं, वही उसमें एडजेस्ट होते हैं, क्योंकि वे तुरंत अपनी शिक्षा से जुड़े होते हैं

पी0बी0 द्वारा......जारी

01.09.2026/1420/AG/PB/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी...

जिसके कारण वे आसानी से नौकरी में लग जाते है। लेकिन जो व्यक्ति चार-पांच-छः वर्ष बेरोजगारी में इधर-उधर घूमता रहता है वह शिक्षा से कट-ऑफ हो जाता है और कहीं-न-कहीं छोटी-मोटी नौकरी में लग जाता है। इसलिए बाद में उसकी सिलेक्शन में भी बहुत दिक्कत होती है।

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने अलग-अलग गारंटियां दी थीं। उनमें युवाओं और नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी गारंटी और बहुत बड़ा आश्वासन था कि सरकार उन्हें पांच लाख नौकरियां देगी। उस समय पूरे प्रदेश में दीवारों पर भी यह लिखा गया था और आज भी कई जगह ऐसा लिखा दिखाई देता है। यह कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में भी कहा गया था। अध्यक्ष महोदय ने स्वयं बजट सेशन में इसे पढ़कर बताया था कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि पहली कैबिनेट में एक लाख पक्की नौकरियां दी जाएंगी और 58 वर्ष की आयु तक नौकरी तथा पेंशन वाली व्यवस्था होगी। मुझे लगता है कि चुनाव के समय पार्टियों पर कई तरह के दबाव होते हैं और शायद कमरे के अंदर सभी यह मानते होंगे कि यह संभव नहीं है लेकिन लोगों से वोट लेने के लिए उस समय यह कहा गया था।

(श्री संजय रत्न, सभापति पदासीन हुए।)

सभापति महोदय, सरकार ने इसके विपरीत बातें कराना शुरू किया है। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है तब से मुख्य मंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी ने शुरू से ही खजाना खाली होने और बहुत बड़ा कर्ज होने की बातें करनी शुरू कर दी थी। बार-बार यह झूठ भी कहा गया कि पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज छोड़कर गए हैं। मुख्य मंत्री जी ने कुछ दिनों पहले डाडासिबा में भी यही बयान दिया था। उन्होंने ससुराल में जाकर भी यह बात कही जबकि भाभी जी भी उनके साथ थी। उन्होंने उससे पहले शिव जी के मंदिर में पूजा-अर्चना भी की और उसके बाद मंच से उन्होंने झूठ के अंबार लगा दिए।

सभापति महोदय, यह 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज केवल श्री जय राम ठाकुर जी ने नहीं लिया था। यानि जब श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने सत्ता छोड़ी

01.09.2026/1420/AG/PB/2

तब प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपये तक का लोन था। इससे पहले जो आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं उनके समय का कर्ज भी इसमें शामिल था। लेकिन वर्तमान मुख्य मंत्री जी के साढ़े तीन से पौने चार वर्ष के कार्यकाल में चार वर्ष पूरे होने में केवल तीन महीने शेष हैं और वर्तमान सरकार स्वयं लगभग 51,000 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। इसका हिसाब भी जनता को बताया जाना चाहिए। श्री जय राम ठाकुर की सरकार के समय विकास हुआ, सड़कें बनीं, स्कीमें चलीं, सामाजिक सुरक्षा की पेंशनें दी गई, हिमकेयर और सहारा योजनाएं चलाई गई थीं। अब कोई नई स्कीम नहीं चल रही है। इसलिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि रोजगार पर भी प्रतिबंध है, नौकरियां भी नहीं निकल रही हैं और तीन वर्ष सरकार ने सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का बहाना बनाकर निकाल दिए। हम सब यह जानते हैं कि सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी इन बातों को घुमाने और ट्विस्ट करने में बहुत तेज हैं क्योंकि हम सब यूनिवर्सिटी फैलो हैं। उस समय पठानिया जी शायद दूसरी तरफ होते थे और सुक्खू जी तथा पठानिया जी का अलग-अलग ग्रुप था लेकिन विश्वविद्यालय में सभी लोग साथ ही थे। इसलिए दिल्ली से बार-बार सुक्खू जी एन0एस0यू0आई0, यूथ कांग्रेस के नेता बनकर आ जाते थे। उसके नाते इन्होंने दिल्ली में बड़े-बड़े नेताओं की भी चलने नहीं दी। इन्हें लगता है कि मैं अब बी0जे0पी0 की भी चलने

नहीं दूंगा। बी0जे0पी का मामला जनता के बीच है और इसका निर्णय जनता को करना है। हमारे ऊपर केस बनाकर, हमें पीछे हटाकर, लोगों को डराकर या धमकाकर आप हमें रोक सकते हैं लेकिन इस देश में आज तक कोई जनता को नहीं डरा सका है।...(व्यवधान) देश के अंदर कोई किसी को नहीं डरा सकता है। यह देश डेमोक्रैटिक सिस्टम वाला देश है।

सभापति महोदय, रोजगार का मामला सभी के लिए है...(व्यवधान) ...(व्यवधान) और मैं इसी विषय पर बात कर रहा हूं। मैं युवा शक्ति के विषय पर बात कर रहा हूं। हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूनिवर्सिटी में नारा लगाते थे कि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति यानि स्टूडेंट पावर, नेशन्स पावर। वह एक शक्ति भी है और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को इसे किसी नकारात्मक दृष्टि से सोचना चाहिए। वह इस देश की शक्ति भी है क्योंकि आने वाले समय में उन्हीं 65 करोड़ लोगों ने इस देश को संभालना है। आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो 25 करोड़ छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जगह-जगह शिक्षा ग्रहण करके निकल चुके हैं। देश के अंदर उन्हीं 25 करोड़ लोगों की एक तादाद है।

01.09.2026/1420/AG/PB/3

सभापति महोदय, मेरा आग्रह रहेगा कि मुख्य मंत्री जी 75,000 करोड़ रुपये के कर्ज का रोना लोगों के बीच न रोया करें। जब कोई इकॉनमी डेवलपिंग होती है तब वह कर्ज के नीचे चलती है। जितने भी बड़े-बड़े पूंजीपति हैं अगर हम उनकी बात करेंगे तो उनका भी शायद खरबों रुपये का लोन होगा यहां तो फिर भी सरकार ने आगे बढ़ना है। यह आवश्यक है कि उस लोन में कोइ करप्शन न हो

श्री ए0पी0 द्वारा जारी..

01.09.2026/1425/ए0एस0-ए0पी/-01

नियम-130 के अंतर्गत चर्चा जारी .....श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी ....

उस पैसे को खाया न जाए और वह लोन जनता के हित के कामों में लगे। जनता की ताकत के लिए लोन लगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एक दिन आएगा, जब हिमाचल प्रदेश अपने

पैरों पर खड़ा होगा। उस दिन के बारें में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि वर्ष 2032 में वह दिन आ जाएगा। शायद हो सकता है कि हम-आप सब लोग यहां पर हों। परमात्मा करे की वह दिन भी आए। ...(व्यवधान) नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आप मुझे मुख्य मंत्री रखो। उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। ऐसी बात कोई बोल भी नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी है और जनता ने तय करना है किसको कब तक रखना है। हर आदमी की इच्छा होती है कि लंबे समय तक चले, आदमी की लंबी उम्र भी हो और लंबा राजनीतिक करियर और जीवन भी अच्छा हो, वह सब हर आदमी यही चाहता है। सभापति महोदय, मेरा ऐसा मानना है कि रोजगार से संबंधित जो विषय है, उसमें अनेकों चीजें ऐसी आई हैं। जिसमें श्री जय राम ठाकुर जी के समय एडवर्टाइज पोस्टें हुई थीं, उनको भी समाप्त कर दिया गया है। उनकी भर्ती प्रक्रिया को भी रोक दिया गया है। बिजली बोर्ड के अंतर्गत जे0ई0 की पोस्टें निकली थीं। लोगों ने उस पोस्ट के लिए फॉर्म भी भर दिए थे। एक दिन मैं अखबार में न्यूज़ पढ़ रहा था कि उन पोस्टों को अब नहीं भरा जाएंगा। उन्होंने फॉर्म भरने के लिए जो पैसा खर्च किया था, वह पैसा वापिस कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि बिजली विभाग के अंदर बहुत ज्यादा पोस्टें खाली हैं। खासकर जे0ई0 की पोस्ट तो छोटी सी पोस्ट होती है। एक्स0ई0एन0, एस0ई0 तो चलो हम मान लेते हैं कि उन पोस्टों को नहीं भरा जा रहा और उनकी पोस्टों को हम बढ़ा रहे हैं। एक तरफा तो डेवलपमेंट हो रही है लेकिन नीचे काम करने वाले है कर्मचारी जैसे लाइनमैन, ए0एल0एम0, टेक्नीशियन आदि नहीं है। लेकिन ऊपर जाकर के चीफ इंजीनियर और बड़ी-बड़ी पोस्टों में ऑफिसर हैं। हम और आप सभी लोग एक्स0ई0एन0 की पोस्ट क्रिएट कराते हैं। मैं यह नहीं कहता कि एक्स0ई0एन0 का महत्व नहीं है। माननीय मंत्री धर्माणी

01.09.2026/1425/ए0एस0-ए0पी/-02

जी भी इसी फील्ड से हैं। लेकिन ज्यादातर बिल को क्लियर करना, बिलों की बातें करना और बाकी चीजें, स्कीम बनाना और सारे सिस्टम को कंट्रोल करना, इतना काम है और फील्ड के अंदर तो लड़ाई एस0डी0ओ0, जे0ई0, टेक्नीशियन और लाइनमैन लड़ेंगे। ऐसे में उनकी पोस्टें समाप्त कर दी गई। इसी तरह से, मैंने देखा है कि अलग-अलग जगहों पर

जब हम लोग जाएंगे तो जो आउटसोर्सिंग लोग लगे थे, उनकी लगभग दस हजार लोगों की छंटनी की गई। इस पर हमने अखबारों के माध्यम से भी बोला है। श्री जय राम ठाकुर जी ने अनेक बार बोला है, जिन्होंने कोरोना काल में लड़ाई लड़ी, उनको बाहर निकाल दिया गया। इसी तरह से अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐसी-ऐसी स्कीम्स लागू हो रही हैं। जिसके कारण लोगों के लिए रोजगार निकलने भी बंद हो गए है। जिसके कारण विभाग के अंदर प्रमोशन सिस्टम भी बंद होगा। जिस तरह से हम लोगों ने एलिमेंटरी सिस्टम और हायर एजुकेशन सिस्टम को इकट्ठा कर दिया। एक ही प्रिंसिपल के अंदर आठ-से-दस स्कूल कर दिए। माननीय मंत्री श्री रोहित जी, हम सब लोग और शायद आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे। पता नहीं, यह सौभाग्य आपको मिला होगा या नहीं मिला होगा। शायद आप पढ़ने के लिए कोठखाई से शिमला आ गए होंगे। क्योंकि आप बड़े परिवार से संबंध रखते हैं तो शायद आप पढ़ने के लिए शिमला ही आ गए होंगे। क्योंकि हम लोग तो नीचे लड़ाई लड़कर आए हैं। कॉलेज भी हमारे अपने थे और स्कूल भी हमारे अपने थे। लेकिन अच्छी बात है, आप यहां आए होंगे तो वो भी आदमी का सौभाग्य होता है। परिवार के लिए परिवार और पूर्वजों का कंट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए आदमी आगे बढ़ता है। उन पर भी किसी देवता का आशीर्वाद होता है। आज ध्यान में आ रहा है कि एक प्रिंसिपल के पास आठ-से-दस स्कूल आ गए हैं-प्राइमरी, मिडिल और हाई। अब वह प्रिंसिपल उन स्कूलों में रहेगा। अगर किसी प्राइमरी टीचर ने छुट्टी भी लेनी होगी तो उसे एप्लिकेशन देने के लिए पंद्रह किलोमीटर, दस किलोमीटर और पांच किलोमीटर दूर अपने प्रिंसिपल के पास दूर-दूर तक जाना पड़ेगा। जब यह सिस्टम इकट्ठा हो गया तो सी0एच0टी0 की पोस्टें खत्म हो जाएंगी। आने वाले समय में आपके हेड टीचर की पोस्टें भी खत्म हो जाएंगी। ऐसा मैं पासिंग रेफरेंस में ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, क्योंकि विषय बहुत है। कुछ ऐसे विषय भी हो सकते हैं जो शायद इन चीजों से संबंधित न हों। लेकिन

01.09.2026/1425/ए0एस0-ए0पी/-03

उनका असर नीचे गलत पड़ रहा है। उस विषय पर भी बात करनी जरूरी है। लेकिन लंबा सेशन नहीं था, इसलिए वो विषय बीच में रह भी गया। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं

इन चीजों के ऊपर बोलूं। यह सरकार रोजगार के मामले में बहुत डिले कर रही है। अभी टी0जी0टी0 की 414 पोस्टें माननीय मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी ने भरी हैं लेकिन उसके कारण उनको स्टेशन नहीं मिल रहे हैं। अब दे दिए हैं या नहीं यह मुझे पता नहीं है। फाइल शायद मुख्य मंत्री जी के पास होगी जो दो-तीन महीने मंत्री के पास आएगी नहीं। क्योंकि माननीय मंत्री जी भी लाचार हैं, मुख्य मंत्री के वहां से फाइल आती नहीं है। माननीय मंत्री जी आप बोलते क्यों नहीं हैं? आप हमारे साथी हैं। मैंने कई बार देखा है कि आप लोग डरते बहुत हैं और मैंने जज भी किया है कि जब आदरणीय वीरभद्र सिंह जी और धूमल जी थे तो हमें थोड़ा चुप रहना पड़ता था। यह बातचीत में बाहर भी किसी सदस्य से कर रहा था। वह बहुत बड़े आदमी थे, हमसे बहुत बड़े थे हमारे पेरेंट्स की तरह थे। पेरेंट्स का मान-सम्मान हमारी पीढ़ी तो जानती है कि क्या होता है। लेकिन मुख्य मंत्री जी तो हमारे मित्र ही हैं। उनसे बाजू पकड़कर काम करवाया करो। पेन हाथ में निकालकर और पकड़कर कहो कि लिखो यहां पर, नहीं तो हम चलते हैं साथ में। 414 लोगों की पोस्टें आठ-नौ महीने से नहीं भर रहे हैं और स्कूल लग पड़े हैं। स्कूलों के अंदर मास्टर नहीं मिल रहे हैं तो ये रोजगार का मामला आप लोग कर रहे हैं। दूसरा विषय मैं वन विभाग की बात करता हूं जोकि मुख्य मंत्री जी के पास ही है। वर्ष 2025 में 300 से अधिक वन रक्षकों को प्रमोशन देकर डिप्टी रेंजर बनाया गया था। उनका भी सारा काम हो चुका है, लेकिन उनको भी जॉइन नहीं कराया जा रहा है। उनके डिप्टी रेंजर बनने के बाद वन रक्षकों की पोस्टें निकल जाएंगी तो उसको आप लोग भर सकते हैं और लोगों को रोजगार दे सकते हैं। उनको आप लोग नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से सभापति महोदय

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

01.09.2026/1430/AT/AS/01

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी....

वन रक्षकों की पोस्टें निकल जाएंगी, उसके बाद आप उन पोस्टों को भर सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं, पर आप वह नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से, सभापति महोदय,

अगर कहीं कभी कोई आदमी किसी पोस्ट के लिए पात्र होता है तो उसको उलझाने की कोशिश की जाती है।

सरकार ने हाल ही में पांच सौ के लगभग वन रक्षक के पद भरे। अभी आप नई-नई पोस्टें ला रहे हैं, सहायक वन रक्षकों की पोस्टें निकल रही हैं, आप उसमें क्या कर रहे हैं? शायद अभी फाइल अंदर ही होगी, लेकिन मुझे कहीं न कहीं से जो जानकारी मिली है मैं उसके आधार पर कह रहा हूं और आपके सामने लोगों का दुःख व्यक्त कर रहा हूं। उनका कहना है कि जो वन रक्षक भरे हैं या जो सहायक वन रक्षक लगेंगे, उनको 50 प्रतिशत कोटा इसमें दिया जा रहा है। आप बताईये जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वन रक्षक के पद के लिए पात्र होते थे या पूर्व सैनिक थे, उत्कृष्ट खिलाड़ी थे, होमगार्ड के लिए कोटा होता था, वन विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी इसमें प्रमोशन लेकर आते थे, उनके लिए जो सिस्टम था वह तो आपने बर्बाद कर दिया। वे हमें चिट्ठियां लिखकर भेजते हैं कि जरा हमारे बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी बात करो। मैं यह नहीं कहता कि सहायक वन रक्षकों को न रखें, उन लोगों के लिए भी पॉलिसी बनाओ। इस तरह से उनको भी मत लटकाओ। सभापति महोदय, अगर जो नौकरी देते भी हैं और कई बार नौकरी निकलती भी है, तो उसमें यह क्या कर रहे हैं, ये भी दुःखी होंगे।

जब माननीय परमार जी का फंक्शन था, उस दिन मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से बात की। वहां पर रोहित ठाकुर जी, श्री जगत सिंह नेगी जी, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री विनय कुमार जी, माननीय अध्यक्ष महोदय और ठाकुर जयराम जी और मैं भी वहां ही था। तो आपकी कई ऐसी पोस्टें जे0ओ0ऐ0 लाइब्रेरी की निकल रही हैं, जिनमें तनख्वाह 12500 रुपये है और उसमें ऊना के बंदे को किन्नौर लगा दिया। अब आप कल्पना करो कि ऊना का बंदा किन्नौर जाएगा। उसी समय माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी भी बोल

01.09.2026/1430/AT/AS/02

पड़े कि मेरा बंदा लाहौल-स्पीति लगा दिया। मैंने उनको कहा कि यहां पर जोर से बोलो। ऊना के बंदे को किन्नौर में और किन्नौर के बंदे को लाहौल में लगाया गया। आप कल्पना करो कि किस तरह से वह 12,500 रुपये में नौकरी करेगा।

मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चहुंगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आई0टी0 लगे। इसमें मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हैं न ही मेरी कोई बातचीत है, मैंने लिस्टें पढ़ीं, क्योंकि मेरी आदत है ऐसी चीजों को देखने की। कोई भी आदमी अगर कहीं दिक्कत में है तो उस आदमी की दिक्कत का हल होना चाहिए।

मान लो आपने उनको रोजगार दिया और इसमें जॉब ट्रेनी के नाते तनख्वाह 12,500 रुपये लिखी हुई है, इसमें से आप अगर देखेंगे तो सोलन का आदमी कांगड़ा गया, बंजार का आदमी ज्वालामुखी गया और आपका सिरमौर का आदमी चंबा गया, चुवाड़ी में। विरेंद्र कुमार चुवाड़ी गया, बेचारा। आप कल्पना करो, सोलन में जे0ओ0ए0 (आई0टी0) की पोस्ट ही खाली नहीं होगी। ऐसी-ऐसी मेरे पास 42 लिस्टें हैं। कोई मेरे पास आया भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे ही किसी ने फोन किया। उसने कहा, सर, मैं आपको लिस्ट भेज रहा हूं, आप इस पर बात कर सकते हैं। लोगों को पता है कि हम यहां एक साथ पढ़े हुए हैं, इसलिए वे मुझे ज्यादा बोलते हैं ।

सर दूसरा विषय करूणामूलक आधार पर नौकरियां हैं। उसमें आप लोगों ने कहा था कि हम सब लोगों को नौकरियां देंगे और जल्दी देंगे। अब आप उसमें बैरियर लगा रहे हैं कि तीन लाख रुपये से ऊपर आमदनी वालों को नौकरियां नहीं देंगे, इस तरह से नहीं देंगे, उस तरह से नहीं देंगे। उसमें जो दुःखी फैमिलियां हैं उनको भी नौकरी नहीं मिल रही है। उसके बाद जो नौकरियां आपने दी हैं, उसकी लिस्ट भी मेरे पास है। सभापति महोदय, उसमें भी इसी तरह से है।

सभापति महोदय, इसी तरह से है और उसके साथ में लिखा हुआ है सुनीता देवी जो चंबा से संबंध रखती है उसे सिरमौर में पोस्टिंग दे दी जाती है। 12,500 रुपये की आप नौकरी दे रहे हैं। उसकी माता जी घर में अकेली होंगी, छोटा भाई होगा, बड़ी बहन होगी, कोई भी होगा। वह अकेली लड़की

01.09.2026/1430/AT/AS/03

बेचारी वहां जाकर कहां पर कमरा लेगी? 12,500 रुपये में गुजारा करेगी? फिर अगले दो साल में पक्की होगी, उसके बाद फिर वह कैसे वापिस आएगी?

मैंने उस समय इस विषय को माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष रखा। मैंने कहा, इन सबको रोको। आप पहले तो नौकरी दे नहीं रहे, और दे रहे हैं तो उसमें ऐसा हो रहा है। इसका मतलब अफसरशाही आपको पूछ ही नहीं रही है।

सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ऊना में ऊना नंबर-1 की एक शराब की फैक्ट्री थी, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के समय पर वहां कर्मचारियों का विषय आया कि इनकी छंटनी करो। प्रोफेसर साहब ने कहा, छटनी क्यों करनी है? इनको अलग विभाग में भेजो। उन्होंने कहा कि यह फैक्ट्री घाटे में चल रही है। फिर उन्होंने कहा कोई नहीं यहां पर 40,000-40,000 रुपये का कर्मचारी भी है, दिहाड़ीदार भी हैं। यानी लेबर वाला आदमी भी 50,000 रुपये तक पहुंच गया था। क्योंकि वह पुराने लोग थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप 12,000-15,000 रुपये में नए लोग रख लो, लेकिन हम छटनी नहीं करेंगे। 79 लोगों की अलग-अलग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट मांगकर उनमें भेज दो। उस समय टी. आर. जनारथा जी हमारे जनरल इंडस्ट्री के एम0डी0 थे। तो उस समय वहां क्या हुआ कि पहले दस आदमी चंबा, अगले दस आदमी कुल्लू, अगले दस आदमी किन्नौर, अगले दस आदमी सिरमौर भेजा गया। मुझे ऊना से दो फोन आए कि सर, हमें तो वहां भेज दिया। हम 53 साल के हो गए, हमने कभी रोटी भी नहीं बनाई, हम कहां ठहरेंगे और कैसे खाना बनायेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। तो मैंने प्रोफेसर साहब से इस बारे में बात की। उन्होंने जनार्धन साहब को फोन किया कि जनारथा साहब, इसको रोको। उसमें से कुछ पांच-छः लोग ज्वाइन कर गए थे। फिर सबकी लिस्ट मांगी, सबके एड्रेस देखे, जो जिस जिले से संबंध रखता था, उसे उसी जिले में भेज दिया गया। उन्होंने रिपोर्ट मांगी कि वे लोग किस विभाग में जाना चाहते हैं? आबकारी विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, शिक्षा विभाग इत्यादि किस विभाग में जाना चाहते हो?....

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी.....

01.09.2026/1435/av/dc/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती--------- **जारी**

लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, शिक्षा विभाग इत्यादि किस विभाग में जाना चाहते हो? इस तरह से सभी अपनी-अपनी जगह एडजस्ट हो गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज जिनको नौकरियां मिल रही हैं वे इस तरह से परेशान हैं।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कई लोग 14-14 वर्षों से पार्ट-टाइम लगे हुए हैं। अब उन लोगों की समस्या को कौन हल करेगा? वे 8-10 वर्षों तक दैनिक वेतन भोगी ही रहते हैं और तब तक उनकी आयु भी 55-56 वर्ष हो जाती है। उसके बाद वे पक्के होते हैं, उस हिसाब से वे स्थाई तौर पर एक-दो वर्ष ही नौकरी करते हैं। आपको जिन्होंने छोटी-छोटी नौकरियों के ऊपर आपको इतना कंट्रीब्यूशन दिया क्योंकि सबसे ज्यादा काम करने वाले भी ये ही लोग हैं। ये लोग दस-दस घण्टे काम करते हैं मगर सबसे ज्यादा खिंचाई भी इन्हीं लोगों की होती है। वह व्यक्ति एक-दो वर्ष स्थाई नौकरी करने के बाद रिटायर हो जाता है और यह पॉलिसी मेकिंग का मामला है। सरकार को उस व्यक्ति के बारे में भी सोचना चाहिए और उसकी सेवानिवृत्ति 58 वर्ष की जगह कुछ ज्यादा सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि रिटायर होते वक्त उसको चार पैसे तो मिले वरना तो उसकी सारी उम्र पार्ट-टाइम में ही चली जाती है।

यहां पर आज मल्टी टास्क वर्कर्ज का विषय भी उठाया गया। मैं भी उस विषय पर बोलना चाहता हूं क्योंकि उसमें भी बहुत दिक्कतें हैं। उसमें भी 4200 रुपये, 4500 रुपये, 5200 रुपये पर प्रदेश के लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति किस प्रकार से इतने कम वेतन पर नौकरी कर पाएगा। यह तो मैं प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार देने की बात कर रहा था। परंतु इसके अतिरिक्त इनडायरेक्ट रोज़गार की बात भी करना चाहता हूं क्योंकि आपने वायदा किया था कि हम प्रदेश के लोगों से इतने-इतने रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदेंगे। परंतु आज उसमें भी लिमिट लगा दी गई है कि एक परिवार से केवल 20 लीटर्ज दूध खरीदा जाएगा। परंतु हमारे एरिया में तो लोगों

ने 20-20 भैंसे रखी हैं और आपकी सरकार ने एक परिवार से केवल 20 लीटर्ज दूध खरीदने की लिमिट लगाई है, अब वे अपना बाकी दूध कहां डालेंगे? यह एक इनडायरेक्ट रोज़गार है और इसके लिए भी सरकार की ही

01.09.2026/1435/av/dc/2

जिम्मेवारी बनती है तथा सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। प्रदेश के लोगों को रोज़गार प्राप्त करने में अनेकों दिक्कतें आ रही हैं।

आप जानते हैं कि दिव्यांग लोग कब से धरना दे रहे हैं और शायद उनका भी रोज़गार से ही संबंधित विषय है। उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आप उनके साथ बैठकर बातचीत कीजिए। वे भी हमारे ही साथी हैं जोकि धरने पर बैठे हैं और रोज़गार ढूंढ रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि दिव्यांगों का प्रमोशन कोटा भी लागू नहीं हो रहा है। वे प्रमोट होंगे तभी नीचे से पोस्ट खाली होगी। आपको पी0ई0टी0 का स्टेट कैडर करना चाहिए, कई लोग ऊना के अंदर 12-12 हजार रुपये में फंसे हुए हैं और ऊना का आदमी चम्बा में फंसा हुआ है। इसके लिए जिम्मेवार लोगों को साथ बैठाकर मंथन करना चाहिए। ऐसी अनेकों चीजें हैं और एक बार माननीय श्री राजेश धर्माणी ने भी यह विषय उठाया था। यह विषय थोड़ा-सा हटकर है। हमने अपने साथियों को बोला कि आप लोग इस विषय पर बोलिए। मान लो मेडिकल कॉलेज का विषय है। सभी मेडिकल कॉलेजिज में साढ़े चार वर्षों की फीस ली जाती है जोकि शायद मेडिकल कमीशन ने तय की हुई है। हिमाचल सरकार भी यहां सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजिज में साढ़े चार वर्षों की फीस ले रही है। मगर सोलन का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पांच वर्षों की फीस ले रहा है जोकि एक-एक स्टूडेंट से 8-8 लाख रुपये ज्यादा ले रहा है। उस कॉलेज में कुल डेढ़ सौ सीट्स हैं, अब आप खुद अन्दाजा लगाइए कि कितना पैसा जा रहा है। हमारे प्रदेश के लोग ही 8-8 लाख रुपये ज्यादा देने को मजबूर हैं तो हम यहां पर किस लिए बैठे हैं? हम यहां बैठकर क्या कर रहे हैं, उसके लिए प्रदेश सरकार कुछ-न-कुछ तो कर ही सकती होगी? उसको रेगुलेटरी कमीशन ने शायद सौ करोड़ रुपये फाइन डाला था कि आज तक बच्चों से जितना अतिरिक्त पैसा लिया है, उसको वापिस किया जाए। परंतु उसने कोर्ट में जाकर स्टे ले

लिया। अब यह हमारी सरकार की भी मजबूरी है परंतु हम उसकी चाबी कहीं-न-कहीं से तो घुमा ही सकते हैं यानी किसी-न-किसी तरीके से तो बातचीत की जा सकती है।

01.09.2026/1435/av/dc/3

हमारे साथी कई इस प्रकार की स्कीम्ज चलाते हैं जैसे पशु मित्र इत्यादि। आप अगर इस प्रकार से बहुत कम वेतन पर रोज़गार देंगे तो यह एक तरह से हमारे युवाओं का एक्सप्लॉयटेशन है। हमारी नई जनरेशन बहुत ज्यादा पढ़ी-लिखी है। आप देखते होंगे आज एम0ए0, पी0एच0डी0 वाले भी चपड़ासी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। हमारे से पूर्व की पीढ़ी तो बहुत अच्छी थी। हमने खुद देखा है, डॉ0 राजीव बिन्दल जी जब पहली बार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बने थे तो उस समय जो भी नर्सिंग या फार्मासिस्ट्स का कोर्स करके आता था तो उसको पूछा जाता था कि आपने कहां लगना? उसको उसी समय स्टेशन मिला जाता था क्योंकि सारे पद रिक्त पड़े हुए थे। ठीक है, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने कार्यकाल में नर्सिंग कॉलेज खोलें। हमारे अपने लोग अपने एरिया में

टी सी द्वारा जारी

01.09.2026/1440/टी0सी0वी0/एच0के0-1
श्री सतपाल सिंह सत्ती.... जारी

इससे हमारे अपने लोगों को अपने एरिया में ही नर्सिंग की पढ़ाई करने का अवसर मिला और प्रदेश का पैसा प्रदेश में ही रहा। आज इन कॉलेजों से नर्सिंग करने वाले लोग मैक्स, फॉर्टीज, अल्कमिस्ट, दिल्ली ए0आई0आई0एम0एस0 इत्यादि अस्पतालों में लगे हुए हैं। मैंने देखा है कि हमारे ऊना के लड़के भी ए0आई0आई0एम0एस0 में गए हुए हैं जिन्होंने हिमाचल से नर्सिंग की है, इसका यह फायदा हुआ है। लेकिन दूसरी दिक्कत यह हो गई है

कि नर्सिज को अब नौकरी नहीं मिल रही है। मुख्य मंत्री जी ने ठीक कहा कि सरकारी क्षेत्र में हम अभ्यर्थियों को मैरिट के ऊपर लगाएंगे। इसी तरह बहुत-सी पढ़ी-लिखी पीढ़ी रोजगार का इंतजार कर रही है। मेरा इस समय वर्तमान गवर्नमैंट से आग्रह है कि जो वादा आप लोगों ने कैबिनेट के अंदर किया था वह पूरा नहीं हो सकता। मैं स्वयं कह देता हूं कि वह आपने झूठ बोला था। आपने हर महिला को 1,500 रुपये देने का वादा भी झूठ ही बोला था।...(व्यवधान)

मैं आपकी जगह होता तो एक बार माफी मांग लेता और कह देता कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पास जितना है उतना ही दे पाऊंगा। भाखड़ा बांध या हिमाचल को बेचकर तो मैंने देना नहीं है या पेंशन लगानी नहीं है। ठीक है, गलती हो गई, आगे के लिए नहीं लिखेंगे। मैं तो कहता हूं कि नेताओं को पहले यह देखना चाहिए कि वे यह कार्य कर भी पाएंगे या नहीं । हमारा भी मैनिफेस्टो बनेगा और आपका भी बनेगा लेकिन पहले देख तो लो कि खजाने में पैसा है या नहीं है। लोगों को ऐसे ही सपने मत दिखाया करो ...(व्यवधान) आप लोग क्या बात कर रहे हैं? आप लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं? इसी के कारण नेताओं की क्रैडेपेबिलिटी खराब हुई है। मैं आपको बताऊं, कई लोग बोलते हैं कि लोगों को स्कूटियां देंगे, क्या स्कूटियां देना हमारा काम है? हमारा काम है, कॉलेज अच्छे दो, स्कूल अच्छे दो, उनकी फीस कम करो और उनको और सुविधाएं दो, स्कूटी देने के बजाय बस में जा रहे बच्चों के लिए बस में अच्छी सुविधा दो। उसमें बच्चा-बच्ची बैठकर जाएं और उससे उनका एक्सपोजर भी बढ़ता है। जब कोई बच्चा बस में जाता है तो उसका अलग ही एक्सपोजर होता है। कभी खिड़की जबरदस्ती खोलनी पड़ती है, कई बार उबर में बैठकर जाना पड़ता है, कई बार कंडक्टर से लड़ना पड़ता है और कई बार बस में खड़े होकर जाना पड़ता है। आपने शुरू से उसको नवाब बना दिया और स्कूटी दे दी। उसके

01.09.2026/1440/टी0सी0वी0/एच0के0-2

बाद थोड़े से धक्के खाने पड़े तो वह चीखने लग जाते हैं और फिर आत्महत्या कर देते हैं। क्या हमारे टाइम में कोई आत्महत्या करता था? बीस साल का बच्चा तो शेर से भिड़ जाता था और ये आज आत्महत्या कर रहे हैं।

सभापति महोदय, इस देश के अंदर गुरु गोबिंद सिंह ने चार बच्चे वार दिए थे और उन्होंने आत्महत्या नहीं की। इसी देश के अंदर भगत सिंह ने नारे लगाते हुए फांसी के फंदे को चूमा। शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, मंगल पांडे और अशफाकउल्लाह खान ने देश के लिए बलिदान दिया। हिंदुस्तान के अंदर जिस देश में भगवान राम को सुबह राज मिल रहा था, उन्हें उसी समय वनवास हो गया, लेकिन इस देश के वे व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं गये। आज हमारे लोग पनीर इत्यादि खाते-खाते डिप्रेशन में जा रहे हैं। फॉर्चूनर गाड़ियों में घूमने वाला बेटा डिप्रेशन में चला गया। मैंने पूछा कि इसको क्या हो गया? वह छलांगें मारता घूम रहा है और डिप्रेशन में है क्योंकि वह ऐसी बातें सुन रहा है। इसलिए हमें लोगों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि हम किस देश के नागरिक हैं? इस देश को 1200-1400 सालों तक लोगों ने गुलाम बनाया और 1400 सालों तक रौंदा। हमारे-आपके सबके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी और 1200 सालों के बाद हम लोग आजाद हुए। हमने उससे लड़ाई लड़ी जिसके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। चढ़ता भी इंग्लैंड के राज में था और उतरता भी वहीं था लेकिन हमने गले से पकड़कर उसको यहां से भगाया।

सभापति महोदय, देश की हैसियत और देश की युवा पीढ़ी की हैसियत को देखते हुए, हम सब लोगों को इन सब चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं, क्योंकि मैं सच बोल देता हूं और कई बार लोगों को लगता होगा कि झूठ बोलता हूं। मुझे बड़ा दुःख लगता है कि नौजवानों के अंदर फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रही है?

फ्रस्ट्रेशन तब आती है जब 15 अगस्त को एक ऐसे पुलिस वाले को डी0जी0 डिस्क मिलती है जिसकी फोटो चिट्टा बेचने वालों के साथ रोज वायरल होती हैं। मैं आपको ऊना के अंदर चिट्टा बेचने वाले का नाम बता सकता हूं और उस आदमी की फोटो भी दे सकता हूं। ...(व्यवधान) भैया, आप जंतर-मंतर के चक्कर में मत पड़ो। जंतर-मंतर पर जो लोग आए, वे सब लोग आपके भी थे, हमारे भी थे और बाकी लोगों के भी होंगे। जिसको लगता है कि गलत हुआ है उसके विरुद्ध लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में

01.09.2026/1440/टी0सी0वी0/एच0के0-3

आंदोलन करना लोकतंत्र का एक गहना है। उसको हम लोगों को रोकना नहीं चाहिए। वह लोकतंत्र का एक श्रृंगार है लेकिन जो आंदोलन होता है उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। हमने भी आंदोलन किए हैं। लेकिन उसमें मां-बहन की गालियां देना, प्रधानमंत्री को तथा उनकी माताजी को गालियां देना या कल कोई माननीय विक्रमादित्य जी आपको या आपके पेरेंट्स को कोई गाली देगा या आपके घर के बाहर आकर आपका पुतला फूंकेगा, मैं तो यह कहता हूं कि यह चीज बैन होनी चाहिए कि नेताओं के घर के बाहर जाकर उनका पुतला फूंका जाए। उनका घर उनका अपना घर है। वहां उनकी पत्नी है, बच्चे हैं और रिश्तेदार हो सकते हैं। हम बाहर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और घर में रिश्तेदार मिलने के लिए आए है...(व्यवधान) वे यह देखकर हैरान होते हैं कि यह क्या हो रहा है? आपने धरना देना है तो जहां धरना देने के लिए जगह है,वहां बैठो। जंतर-मंतर धरने के लिए है ही और वहां कोई शिवजी का मंदिर थोड़े ही बनना है। वह धरने के लिए रखा हुआ है, इसलिए खाली रखा हुआ है। लेकिन इसके नाते मैं अपने कार्यकर्ताओं को बोलता हूं, जनसभा के अंदर भी बोलता हूं कि कोई भी राहुल गांधी जी जाएं, उनको ऐसा मत बोलो।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

1-9-2026/1445/NS-HK/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती-----जारी

कई बार हमसे भी आवेश में आकर कोई गलत बात बोली जा सकती है और बोली भी हो सकती है लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपके लिए नरेन्द्र मोदी प्यारे हैं तो उनके लिए भी सोनिया गांधी प्यारी हैं और उनके लिए राहुल गांधी भी प्यारे हैं। इसलिए कभी भी किसी के ऊपर पर्सनल कमैंट्स मत करें। आप लोग भावनाओं में बहकर किसी भी नेता की तौहीन करेंगे तो मुझे लगता है कि नेताओं का मान-सम्मान टूटेगा और देश के अंदर अफरा-तफरी मच जाएगी। अगर इस देश को किसी ने संभाला है तो नेताओं ने ही संभाला है। इसमें कोई जो मर्जी बोले, हम आप लोग ही हैं जो सुनकर भी लोगों का काम करते हैं। घर में 7.00 बजे तैयार होकर बैठ जाते हैं। माननीय सुख राम जी बीमार होते हुए, कैंसर होते हुए भी यहां बैठे होते हैं। इस फील्ड के सिवाय कोई ऐसा आदमी है जो ऐसे बैठता है। हमारे

कार्यकर्ता, नेता और हम सबकी पत्नियां, अब तो भाबी जी का पता नहीं अब तो नौकर मिल गए होंगे। एक बार श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी ने कहा था कि हमारी पत्नियों के हाथ चाय के कप साफ करते-करते काले हो गए हैं। सुक्खू जी ने यहां कहा था। बाद में लोग कमैंट डालने लग पड़े कि सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी को अगर चाय नहीं पिलानी है तो वोट क्यों मांगते हैं? उसने जनरल पासिंग रैफरेंस में बोला और सच बोला। क्या किसी में दम है जो यहां पर बोल सकता है? यह स्थिति हम सबकी होती है क्योंकि हम सब लोग कॉमन फैमिली से आए हुए हैं और बहुत से लोगों की नौकर-चाकर रखने की भी हैसियत भी नहीं होती है। पठानिया साहब, आपका भी पहले कुछ बचता होगा, अब तो कुछ नहीं बचता होगा और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं। जब आप बैंक में थे तो आप भी सोचते होंगे कि यह क्या प्रॉब्लम हो गई कि यहां तो कुछ नहीं बचता है? हमारे हालात तो ये होते हैं कि अपनी घरवाली बीमार पड़ी होती है और वह कहती है कि केवल सिंह जी 11.00 बजे आ जाओ, डॉक्टर से टाइम ले आना। केवल सिंह घूमने चले गए कि तब तक मैं दो-चार जगहों पर चला जाता हूं और खबरें ले आता हूं। भाबी फोन कर रही है कि आप आए नहीं और डॉक्टर फोन कर रहा है। आप लोगों की पत्नियों की खबर ले रहे हैं और अपनी पत्नी बीमार पड़ी है। लोगों की पत्नियों को पूछ रहे हैं कि भाबी आपकी लात ठीक है? आप क्या डॉक्टर हैं? आपकी अपनी पत्नी फोन कर रही है और आप गाड़ी लेकर वापिस घर जाओ। अब आप बताओ की हम सबकी ये स्थिति है कि नहीं? मैं सामान्य बात कर रहा हूं। आपका अपना बच्चा जहां लग सकता है वहां दूसरे के बच्चे

1-9-2026/1445/NS-HK/2

को लगाते हैं। यह हमारी ही कैटेगरी है कि यार छोड़ो, कहीं मेरे ऊपर उंगली न उठ जाए, इस गरीब के बच्चे को लगा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई और कैटेगरी है जो यह कहती है कि मेरे बच्चे को रहने दो? क्या ऐसी कोई कैटेगरी है? हम विधायकों को 15 लाख रुपये विधायक ऐच्छिक निधि मिलती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी और को यह निधि मिलती है? सब सफाचट्ट हो जाता है। हम इसको जगह-जगह बांटते फिरते हैं क्योंकि हमने वोट लेना है और हमें जनता के प्रति जवाबदेही है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो कैटेगरी है और मैं भी किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता लेकिन गलतियां भी हम लोग करते हैं जिसके कारण हमारे ऊपर उंगलियां उठती हैं। जैसे मैंने डी0जी0 डिस्क का कहा।

अब श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी को किसने रिपोर्ट भेजी है? मैं उस आदमी की फोटो दे दूंगा जिसको डी0जी0 डिस्क मिली है। वह आदमी जिसकी आज भी चार क्विंटल भुक्की पकड़ी गई, वह अंबाला में उसके साथ गया हुआ था। आप फोन से उसकी लोकेशन देख लो कि उसको छुड़ाने के लिए अंबाला पुलिस में गया हुआ था जिसकी चार क्विंटल भुक्की पकड़ी गई क्योंकि उस गैंग के साथ वह जुड़ा हुआ था जो ऊना में गैंगवार हुआ था। वह उस गैंग के साथ जुड़ा हुआ आदमी है। उसको आप डी0जी0 डिस्क दे रहे हैं। फिर लोगों को निराशा होती है कि 15 अगस्त को हम किसको डी0जी0 डिस्क दे रहे हैं। मैं उसमें सुखविन्दर जी को नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने किया लेकिन नीचे से किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको गलत रिपोर्ट भेज दे। अगर गलत रिपोर्ट भेज दी है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो और नीचे से लेकर ऊपर तक सजा दो ताकि दोबारा कुछ गलत न आए। काम करने वाले को हौंसला हो जाएगा और बेईमान आदमी को डर पैदा हो जाएगा। सरकार इसी का नाम है, अच्छे आदमी को हौंसला और गंदे आदमी को डर तथा इस एक ही लाइन में सरकार होती है। इससे लंबा-चौड़ा इसमें फिर आप जो मर्जी लोग जोड़ते रहें। उसके नाते, सभापति महोदय, ये जो नौकरियां हैं, इन नौकरियों के ऊपर हम लोगों को सोचना चाहिए। युवा शक्ति और नौजवान लोगों को नौकरी टाइम पर मिले और अगर नौकरियां नहीं दे सकते हैं तो हम लोगों को उनकी सैल्फ इम्प्लॉयमैंट का कोई सिस्टम खड़ा करना चाहिए। अगर सेल्फ एम्प्लॉयमैंट नहीं है तो आप लोगों ने एक और शुरू किया है। ठीक है, आप लोगों ने फॉरेन भेजने का काम भी शुरू किया है और उस काम को भी आपने अपने हाथ में लिया है। हम लोगों को बाहर के कंट्रीज में भी जाना ही चाहिए। किसी टाइम इसको ब्रेन ड्रेन माना जाता था लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये भी एक काम है कि बाहर से फॉरेन करंसी आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी 140

1-9-2026/1445/NS-HK/3

करोड़ पॉपुलेशन है और उनकी तो पॉपुलेशन ही मात्र 54-55 लाख है यदि 10-20 लाख लोग चले जाएं तो न्यूजीलैंड में अपना ही राष्ट्रपति बन जाएगा। जाओ, वहां जाकर कब्जा करो। उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा किया था, हम वहां जाकर कब्जा करेंगे। उनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं परंतु हमारे यहां तो लगातार काम चल रहा है। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पूरी 15 यूरोपियन कंट्रीज के जितनी पॉपुलेशन है। उन यूरोपियन

कंट्रीज ने जिस प्रकार हमारे क्षेत्र में आकर सेब सीजन के दौरान अलग-अलग प्रदेशों के लोग हमारे सेब के सीजन को आगे बढ़ाने के लिए तुड़ान और लेबर का काम करते हैं उसी प्रकार पंजाब के अंदर भी लोगों ने काम किया तो आज वहां खेतीबाड़ी संभली हुई है। जब यह गलत काम नहीं है और हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं तो उनके लिए भी एक सिस्टम बनाना चाहिए ताकि उनकी एक्सप्लॉइटेशन न हो, उनसे एजेंट गलत पैसे न लें और वहां जाकर वे अरेस्ट न हों। हमें इस तरह का सोचना चाहिए।

मैं तो नौजवानों से कहता हूं कि निकल जाओ जहां से निकलना है और यह अच्छी बात है वहां से आप लोग पेरेंट्स का एक रूतबा आगे बढ़ाएंगे।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

01.09.2026/1450/RKS/HK-1

श्री सतपाल सिंह सत्ती... जारी

जिसको जहां नौकरी मिलती है वह वहां नौकरी करे। यह बात ओपनली बोलनी चाहिए या नहीं लेकिन वर्तमान में 40-50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए नौकरी प्राप्त करना आसान नहीं है क्योंकि आज 80-90 या 95 प्रतिशत अंक वाले युवा प्रतिस्पर्धा में हैं। इसलिए हमें केवल संस्थानों की संख्या बढ़ाने पर नहीं बल्कि उनके स्तर और गुणवत्ता को बनाए रखने पर अधिक ध्यान देना चाहिए तभी हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और वे बैंकिंग सहित प्रत्येक क्षेत्र में फाइट कर सकेंगे। मैं यह दर्द इसलिए व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि हमारे मित्र मुख्य मंत्री हैं। पूर्व में श्री वीरभद्र सिंह जी, श्री शांता कुमार जी, ठाकुर राम लाल, प्रोफैसर प्रेम कुमार धूमल जी, डॉ0 यशवंत सिंह परमार जी और सभी नेताओं ने अपने-अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार कार्य किया है। आज इस सदन में बैठे अधिकांश सदस्य यूनिवर्सिटी, कॉलेजों और इंजीनियरिंग कॉलेजों से शिक्षित होकर आए हैं। यदि आप लोग व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे और डी0जी0पी0 डिस्क ऐसे ही बांटते

रहेंगे तथा भ्रष्टाचार को नहीं रोकेंगे तो परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। मेरे पास भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थिति नहीं है। मैंने उन्हें बताने के लिए कुछ चीजें लिखी थी लेकिन इन चीजों के बारे में मैं उन्हें अलग से अवगत करवा दूंगा। आपको भी बहुत-सी बातें बताई जा सकती हैं क्योंकि आप भी हमारे साथी हैं। इसलिए आप लोग वहां बैठकर व्यवस्थाओं को सुधारने का कार्य करें वरना परिस्थितियां ऐसी हैं कि लोग हमें विलिन के नाते जानेंगे। मैं यह भी मानता हूं कि सबसे अधिक मेहनत करने वाले लोग हम ही हैं। मैं यह नहीं कहता कि कोई व्यक्ति गलत है तो उसके बारे में कुछ न बोला जाए। किसी से गलती हो जाए वह बात अलग है लेकिन कोई जानबूझकर गलत कार्य करता है या कोई परमानेंट बेईमान है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके कपड़े तो जरूर उतारने चाहिए। यदि किसी से छोटी-मोटी गलती हो जाती है तो उसके पीछे इस प्रकार नहीं पड़ जाना चाहिए जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। मैं यह भी नहीं कहता कि हम सब मिलकर कोई नैक्सस बनाएं बल्कि मेरा आग्रह है कि हम अच्छा कार्य करें। हमें अपने पढ़े-लिखे और अनुभवी लोगों की क्षमता का उपयोग करते हुए रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहिए ताकि युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में विकसित किया जा सके। मेरा युवाओं से भी आग्रह है कि यह प्रतिस्पर्धा और मेहनत का जमाना है इसलिए आप लोग परिश्रम करें। यहिद हम उन्हें यह भरोसा

01.09.2026/1450/RKS/HK-2

देंगे कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई गलत नहीं होगा, कोई बैक डोर एंट्री नहीं होगी और किसी प्रकार की कोई हेराफेरी नहीं होगी तथा जिसकी मेरिट होगी उसे ही नौकरी मिलेगी। हम जनता को जो दे सकते हैं उसके बारे में हमें जनता को भी स्पष्ट रूप से बताना चाहिए और चुनावी घोषणा पत्र में भी उसका उल्लेख होना चाहिए। हमने यह नहीं कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को गैस कनैक्शन देंगे लेकिन श्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार ने सवा दो लाख लोगों को गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाये। हमने यह भी नहीं कहा था कि स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 लाख रुपये की गारंटी देंगे लेकिन हिमकेयर योजना लागू करके यह सुविधा प्रदान की गई। सहारा योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये की सहायता दी गई जबकि इसका भी उल्लेख चुनावी घोषणा पत्र में नहीं किया गया था। मुझे लगता है कि हमें जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि हमारे देश और प्रदेश की परिस्थिति क्या है और हमारी

वास्तविक स्थिति क्या है? यदि हमने लंबे समय तक गुलामी का दौर देखा है तो हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ समय संघर्ष और कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी तभी यह देश आगे बढ़ेगा। इस देश को दुनिया ने सोने की चिड़िया कहा है। हमारे पूर्वजों द्वारा यहां दूध की नदियां बहने की बात कही जाती थी लेकिन आज दूध पैकटों में आना शुरू हो गया है। इसका एक कारण यह भी है कि हम सब लोगों ने काम करना कम कर दिया है। हम लोगों ने एम0ए0 की पढ़ाई करते हुए भी खेतों में हल चलाया है। छुट्टियां मिलते ही हम खेती-बाड़ी के कार्यों में लग जाते थे। सेब के सीजन में यूनिवर्सिटी खाली हो जाती थी और ऊपरी क्षेत्रों के छात्र-छात्राएं बागानों में कार्य करने चले जाते थे। गेहूं की कटाई के समय निचले क्षेत्रों के विद्यार्थी खेती में हाथ बंटाते थे। आज परिस्थितियां बदल गई हैं और लोग ऐसे कार्यों से दूर होते जा रहे हैं। आज बच्चे वहां समोसे और बर्गर खा रहे हैं। ऐसे में गवर्नमैंट हर कार्य अकेले कैसे कर सकती है? इसलिए मेरा आग्रह है कि हम रोजगार पर पूरा ध्यान दें, रिक्त पदों को समाप्त न करें, उन्हें विज्ञापित करें और शीघ्र भरें। यहां इंटरव्यू, लिखित टैस्ट और पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी तभी हमारे युवाओं को विश्वास होगा। हिमाचल प्रदेश में जब भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं तो मैं इसे किसी एक गवर्नमैंट पर नहीं बल्कि हम सभी पर लगा हुआ कलंक मानता हूं। पेपर लीक कोई प्रोफैसर करता है, कोई क्लर्क करता है, कोई चपरासी करता है और रिजाइन हम श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का मांगते हैं। मर्डर कोई करता है और फांसी हम किसी और को दे रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पूरे राजनीतिक तंत्र पर उंगली उठती है जबकि कई बार उसका कोई दोष भी नहीं होता। लेकिन लोग

01.09.2026/1450/RKS/HK-3

हमें देखकर यही कहते हैं कि कसूर इनका ही है। आपने दिल्ली के घटनाक्रम में भी देखा होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसमें श्री धर्मेंद्र प्रधान का क्या कसूर था? मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वे हमारी पार्टी के हैं। आपके समय में भी ऐसे मामले हुए हैं और जहां भी हुए हैं वहां कार्रवाई होनी चाहिए। कई बार मुख्य मंत्री भी कहते हैं कि हमने दोषियों को जेल भेज दिया है। मैंने भी कहा कि आपने अच्छा किया और वे कौन-से हमारी बुआ के लड़के थे। आपने जो किया अच्छा किया। क्या वे कोई साडी बुआ की कुड़ी थी? जिसने अपने बच्चे गलत तरीके से सिलेक्ट करवाए उसे आपने जेल में डाल दिया जो

अच्छी बात है। पेपर रद्द करना भी आवश्यक था और वह भी किया गया लेकिन गलत कार्य करने से हजारों-लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए हमें इस विषय पर अत्यंत कठोर कानून बनाना चाहिए। यदि हिमाचल प्रदेश में कोई पेपर लीक करता है, इसमें जो लोग संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि युवा-शकित को कोई निराशा न हो। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। यह पढ़े-लिखे लोगों की भूमि है इसलिए यहां प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना ही चाहिए।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

01.09.2026/1455/बी.एस./वाई.के.-1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी...

ऐसा निवेदन करते हुए मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि रोजगार के द्वार खोलें और अपनी गारंटियों को पूरा करें। हिमाचल के बच्चों को नौकरी दें ताकि हम सब लोग अगले चुनाव के अंदर छाती चौड़ी करके जा सकें। ऐसा निवेदन करते हुए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।

01.09.2026/1455/बी.एस./वाई.के.-2

सभापति : अब नगर एवं ग्राम योजना मंत्री, श्री राजेश धर्माणी जी चर्चा में भाग लेंगे

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव यहां हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा लाया गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर हमारे युवा साथियों से संबंधित चर्चा हो रही है और इस चर्चा में उनको रोजगार देने के बारे बातें कही जा रही हैं।

यहां जो चर्चा हुई उसमें ज्यादातर फोकस इस बात पर था कि कांग्रेस सरकार ने चुनावों के वक्त रोजगार देने की बात कही थी उसके ऊपर चर्चा हुई और कुछ अच्छे सकारात्मक सुझाव भी दिए गए। अभी जैसे आदरणीय सतपाल सिंह सत्ती जी ने अपनी

बात रखी। उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में और स्पष्ट तरीके से भी कुछ बातें कहने की कोशिश की। थोड़ा-बहुत तो पॉलिटिकली भी बोलना ही पड़ता है क्योंकि किसी पार्टी से संबंधित हैं।

युवाओं से संबंधित जो चर्चा है वह सचमुच चिंताजनक है। इसमें सभी को विचार-विमर्श करके हमें ऐसी नीतियां बनाने पर ध्यान देना पड़ेगा जो न सिर्फ युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने की बात कहें बल्कि स्वरोजगार की भी बात हो और निजी क्षेत्र में भी हम अच्छे एंटरप्राइज खड़े कर सकें। उसके बारे में भी नीतियां होनी चाहिए। जब हमारा युवा अच्छी सर्विसिज देने के काबिल होगा तो स्वाभाविक है कि हमारी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी और हमारी सेवाएं भी बेहतर होंगी।

आज हम अगर देश और प्रदेश की तुलना दुनिया के कई देशों के साथ करें तो हमारी जो पर कैपिटा जी0डी0पी0 है वह बहुत कम है, प्रति व्यक्ति जो उत्पादकता है वह बहुत कम है। कई देश ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश से भी छोटे हैं लेकिन उनकी जो पर कैपिटा जी0डी0पी0 है वह हमसे सैकड़ों गुना ज्यादा है।

जब तक हम उत्पादकता नहीं बढ़ाएंगे तब तक रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे। इसके लिए हर स्तर पर काम करने की जरूरत है। जहां हम बच्चों को अच्छी स्कूल शिक्षा दें वहीं पर हम उनको अच्छी टैक्निकल एजुकेशन भी दें। उनको स्किल ट्रेनिंग भी दें और एंटरप्रेन्योरशिप डवलपमैंट के लिए भी ट्रेन करें।

01.09.2026/1455/बी.एस./वाई.के.-3

हमारी जो नीतियां हैं और सरकार की जो नीतियां हैं चाहे भारत सरकार की हों या प्रदेश सरकार से संबंधित हों वे नीतियां भी ऐसी हों जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। वे प्रोडक्टिविटी का गला न घोंटें और उसको डिस्करेज न करें। हम यहां देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारा जो युवा है वह सरकारी नौकरियों की तरफ अधिक आकर्षित रहता है। उसके पीछे का कारण क्या है? यह जानना बहुत जरूरी है। लोगों ने कोरोना के समय में देखा कि जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे थे और जिन्होंने स्वरोजगार अपनाया था उस समय उन्हें सामाजिक सुरक्षा उतनी नहीं मिल पाई जितनी सरकारी क्षेत्र में मिली थी। इसलिए लोगों

का रुझान और अधिक सरकारी नौकरियों की तरफ बढ़ा। यहां पर जैसा आदरणीय सतपाल सिंह सत्ती जी ने कहा।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

01.09.2026/1500/DT/YK-1

नगर एंव ग्राम योजना मंत्री जारी.....

कि आज हमारा युवा मेंटली उतना स्ट्रॉन्ग या रफ-टफ नहीं है जितना कि हमारे समय में था। हमें याद है कि जब हम स्कूल जाते थे तो कोई हमें छोड़ने नहीं जाता था और न ही स्कूल से कोई हमें लाने जाता था। हालांकि कई लोगों को कई किलोमीटर तक जाना पड़ता था। जब व्यक्ति विशेषकर छोटा बच्चा संघर्ष करता है तो उस संघर्ष में वह तपता भी है और मानसिक तथा शारीरिक तौर पर मजबूत भी होता है। संघर्ष करने का जो जज़्बा है आज निश्चित तौर पर कम हुआ है। हमने बच्चों को ऐसा बनाना शुरू कर दिया है कि वे न तो लड़ सकते हैं और न संघर्ष कर सकते हैं और न ही उस लेवल का काम कर सकते हैं। अगर 100 प्रतिशत लोग केवल सॉफ्ट स्किल्स पर ही काम करेंगे और केवल दिमाग से संबंधित ही काम उन्हें मिलेगा तथा फिजिकल एक्सर्शन नहीं होगी और मैनुअल वर्क करने के काबिल नहीं होंगे तो लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे। उसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर पड़ता है। इसके ऊपर मैं बाद में आता हूं क्योंकि जो विषय जिस पर इस सदन में चर्चा हो रही है वह कांग्रेस सरकार द्वारा रोजगार से संबंधित है, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हज़ारों पद सरकारी क्षेत्र में भरे हैं। शिक्षा विभाग में लगभग 7,000 शिक्षक भरे गए हैं। वन विभाग में 2000 से 2200 वन मित्र लगाए गए हैं। पशुपालन विभाग में भी भर्तियां की गई हैं। जल शक्ति विभाग में लगभग 6,000 पद पहले भरे गए हैं और लगभग 4,000 पदों की भर्ती जारी है। हज़ारों लोगों को अन्य विभागों में भी नौकरियां मिली हैं।

आने वाले समय में मंत्रिमण्डल से स्वीकृत पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और उसके माध्यम से भी हज़ारों लोगों को रोजगार मिलेगा। अप्रत्यक्ष तौर पर भी रोजगार जनरेट

करने के लिए कदम उठाए गए हैं। खासकर हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे हमार स्वास्थ्य ठीक रहता है और इनपुट कॉस्ट कम आती है। लेकिन लोग इसलिए प्राकृतिक खेती नहीं करते क्योंकि शुरू में इसमें पैदावार कम होती है। उसको कंपनसेट करने के लिए एक अनूठी योजना माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां प्रस्तुत की है। पूरे हिंदुस्तान में जितना सपोर्ट प्राइस मक्की, गेहूं, कच्ची हल्दी और अदरक का हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है उतना अन्य राज्यों में कहीं भी नहीं है।

01.09.2026/1500/DT/YK-2

अब यहां पर बात उठी कि यह कांग्रेस सरकार ही कर रही है। कुछ वक्ताओं ने पहले कहा लेकिन आपको याद दिलाना चाहते हैं कि बहुत साल पहले जब शांता कुमार जी की सरकार थी तो उसमें वॉलंटियर रखे गए। पशुपालन विभाग में गोपाल सहायक रखे गए। बाद में बीजेपी की सरकार के समय में पंचायत सहायक रखे गए। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत वेटनरी फार्मेसिस्ट और असिस्टेंट वेटनरी फार्मेसिस्ट रखे गए, वे भी इसी तरीके से रखे गए। बीच में ऐसा फेज भी आया कि आठ-आठ वर्ष तक कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां हुईं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे जो कर्मचारी भाई-बहन आठ वर्ष तक कॉन्ट्रैक्ट पर रहने के बाद रेगुलर हुए और वहीं पर कुछ लोग दो साल बाद रेगुलर हो गए। तो ऐसी डिस्पैरिटी भी बीच में इस वजह से उत्पन्न हुई और विद्या उपासक भी रखे गए। सरकारें समय-समय पर इस तरह से करती हैं। आउटसोर्स पर भर्तियां हुईं। हमारे कार्यकाल में और आपके कार्यकाल में आउटसोर्स में भर्तियां हुईं। बहुत सारे वर्कज आउटसोर्स किए जाते हैं। लेकिन ये स्थिति कब और क्यों उत्पन्न हुई? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसमें नेहरू जी का मॉडल था क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि हमने ऐसी नीतियां अपनानी हैं और अपनाई भी हैं।

श्री एन0जी0द्वारा जारी.....

01.09.2026/1505/ए.जी.-एन.जी./1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री……… जारी

कि हम बड़ी-बड़ी परियोजनाएं बनाएंगे, जल परियोजनाएं बनाएंगे, बड़ी सड़कें बनाएंगे, बड़े संस्थान खोलेंगे और बड़े-बड़े पी0एस0यूज़0 बनाएंगे। उन्होंने इनकी आधारशिला भी रखी और आज उन्हीं की वजह से हमारा देश आगे बढ़ा है। लेकिन जो लोग इन संस्थानों और परियोजनाओं को बनाने वाले हैं, जो इनको स्थापित करने वाले हैं, उनका भी अच्छा घर बने, उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, उनके परिजनों को भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, उनकी बुनियादी जरूरतें भी अच्छे तरीके से पूरी हों और इसके लिए भी उन्होंने कदम उठाए थे। आज भी अगर हम देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में—चाहे भेड़ों के फार्म हों, घोड़ों के फार्म हों, भैंसों के फार्म हों—वहीं पर आधुनिक तकनीक व स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित और बड़ी-बड़ी हेवी इंडस्ट्री से संबंधित पी0एस0यूज़0 भी खड़े किए गए। आधुनिक टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्र में जहां हम काम कर रहे हैं, चंद्रयान और मंगलयान जैसे स्पेस मिशन हमने किए हैं, वहीं पर आज भी सरकारी क्षेत्र में बेसिक सर्विसिज प्रदान की जा रही हैं। आज भी डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रेलवे में मिलता है और रेलवे आज भी भारत सरकार चलाती है। हालांकि उसमें भी बहुत सारी सर्विसिज को आउटसोर्स किया गया है या वर्क आउटसोर्स किया गया है। यहां पर दो बातें पैदा होती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे माननीय सदस्यों ने कही हैं। एक तो सिर्फ पशु मित्र क्यों रख रहे हैं या मित्र क्यों रख रहे हैं? मित्र की डैजिगनेशन तो भारतीय जनता पार्टी की ही इंवेनशन थी। इन्होंने इसकी खोज की और इन्होंने ही इसकी शुरुआत की। हमने तो केवल उसको आगे बढ़ाया है। मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि यह अग्निवीर से बेहतर है। अग्निवीर तो चार साल में घर बैठ जाएगा, लेकिन इनमें से किसी को भी घर नहीं भेजेंगे। इनके लिए आने वाले समय में कोई-न-कोई पॉलिसी जरूर बनेगी।

01.09.2026/1505/ए.जी.-एन.जी./2

इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी गंभीर हैं। जैसा मजाकिया लहजे में हमारे श्री विनोद सुल्तानपुरी जी कह रहे थे कि इसका कोई कॉपीराइट नहीं है। इसी का फायदा हमें मिला। अगर आपने कॉपीराइट कराया होता तो शायद हमने भी इसे न किया होता। दूसरा विषय, पक्की सरकारी नौकरियां देने का है। आउटसोर्स की जो नीति है, वर्ष 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, तब वर्क व जॉब्स आउटसोर्स करने की नीति अपनाई गई। यह नीति क्लास-3 और क्लास-4 वर्गों के लिए थी। उस समय डिफेंस को इससे बाहर रखा गया था। लेकिन आज अग्निवीर के माध्यम से आर्मी भी इसके दायरे में है। प्रश्न यह पैदा होता है कि आखिर यह बात किसके दिमाग में आई, कैसे आई, क्या परिस्थितियां बनीं? मैं ऐसा समझता हूं कि जब टॉप लेवल पर एक्सपेंडिचर बढ़ गया या एम्प्लॉयी कॉस्ट बढ़ गई, तो जो टॉप लेवल के अधिकारी थे, उन्होंने इस पर एक बड़ा अच्छा रिसर्च किया और एक अच्छा पेपर सरकार के सामने रखा। उन्होंने एम्प्लॉयी कॉस्ट को कम करने का बढ़िया तरीका निकाला कि सरकार क्लास-4 और क्लास-3 की पोस्टों को भरना बंद कर दे और इनको आउटसोर्स कर दे या वर्क आउटसोर्स कर दे। सोसायटी के अंदर जो अपवर्ड मूवमेंट होती थी या जो गरीब आदमी सरकारी नौकरी लेकर ऊपर उठता था, उसके परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती थी, अब वह अपवर्ड मूवमेंट बंद हो गई है क्योंकि उस स्तर पर भर्तियां नहीं हो रही हैं। यह तो हमारी सरकारों ने उस समय फैसला लिया कि आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर भरेंगे और लाखों महिलाएं उसमें लगी हैं। आशा वर्कर के रूप में ऐसी लाखों महिलाएं लगी हैं और उनको थोड़ा-सा सहारा दिया गया है। मिड-डे मील वर्कर लगाने का कार्य भी स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी के समय में शुरु हुआ था। यहां पर हमारी सरकार द्वारा ही वाटर कैरियर और इस तरह की अन्य पोस्टें निकाली गईं। लेकिन एम्प्लॉयी कॉस्ट को कम करने के लिए गरीब आदमी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आज हम सरकारी क्षेत्र में देखते हैं कि कोई भी प्रमोशनल पोस्ट

खाली नहीं मिलेगी बल्कि कई पोस्टें तो ऐसी हैं जो जुगाड़ करके क्रिएट की गई हैं। मुझे यह बोलने में कोई गुरेज़ नहीं है। उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है?

01.09.2026/1505/ए.जी.-एन.जी./3

आपने बिजली बोर्ड का उदाहरण दिया और आज बिजली बोर्ड में फील्ड स्टाफ की लगभग 11500 पोस्टें खाली हैं। उनको भरने के लिए माननीय मुख्य मंत्री ने आदेश दिए हैं। कुछ पोस्ट भर रहे हैं

पी0बी0 द्वारा......जारी

01.09.2026/1510/AG/PB/1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जारी...

उनको भरने के लिए माननीय मुख्य मंत्री ने आदेश दिए हैं। कुछ पोस्ट भर भी रहे हैं। लेकिन ये पोस्टें खाली क्यों रह रही हैं? इसका कारण यह है कि आज इम्पलाई कॉस्ट लगभग ढाई रुपये प्रति यूनिट हो गई है। हम इसे इससे अधिक नहीं बढ़ा सकते। आज हमारे पास जितना रेवेन्यू आता है उसमें से लोन कंपोनेंट को माइनस कर दें तो हमारा एस्टैब्लिशमैंट कॉस्ट ही शत-प्रतिशत हो जाता है। यदि सारे पद भर दिए जाएं तो यह खर्च शत-प्रतिशत से भी अधिक हो जाएगा और लोन लेकर भी हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में संतुलन बनाने के लिए चाहे कोई भी सरकार आए, पहले भी सरकारें रही हैं और हमारी भी सरकार है, कुछ पद खाली रखने पड़ेंगे। कई पद ऐसे हैं जो रिडंडेंट हैं और जिनकी आज के समय में आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे पदों को रैशनलाइज करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर जिन पोस्ट्स की आवश्यकता है, उन्हें भी आज के समय के हिसाब से सृजित करने की आवश्यकता है। किसी समय जे0ओ0(आई0टी0) की पोस्ट नहीं थी लेकिन आज उसकी आवश्यकता है। इसी प्रकार किसी समय कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट नहीं थी लेकिन आज उसकी आवश्यकता है। इसलिए आज के समय के हिसाब से

जिन पोस्ट्स की आवश्यकता है, उनको क्रिएट करने का प्रयास हर सरकार समय-समय पर करती है और हमने भी किए हैं। जो रिडंडेंट पोस्ट्स हैं और जिनकी आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल कागजों में रखने की भी आवश्यकता नहीं है। जब पोस्ट्स का डेटा या रिप्लाई आता है तो उसमें यह दिखाई देता है कि इतनी पोस्ट्स खाली हैं। लेकिन कौन-सी पोस्ट आवश्यक है और कौन-सी पोस्ट आवश्यक नहीं है, इसके संबंध में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पाता है। इसलिए जो फंक्शनल पोस्ट्स हैं, उनको बनाए रखने और रिडंडेंट पोस्ट्स को रैशनलाइज करने की प्रक्रिया पहले भी होती आई है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। सरकारों को यह प्रक्रिया आगे भी जारी रखनी चाहिए।

दूसरा, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे युवाओं को हम किस प्रकार आगे बढ़ाएं, यह हमारा मेजर कंसर्न है। आप सब जानते हैं कि आज दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हिन्दुस्तान है और दुनिया में सबसे अधिक युवा जनसंख्या भी हिन्दुस्तान में है। इसमें वर्किंग एज ग्रुप अर्थात कमाने की उम्र वाला युवा वर्ग भी बड़ी संख्या में है। लेकिन देश का प्रोडक्टिविटी पर यूथ और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू

01.09.2026/1510/AG/PB/2

उत्पाद उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मामले में हम दुनिया में लगभग सौवें स्थान पर होंगे। इसलिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जब हम इस पर चिंतन करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई-न-कोई हल निकलेगा। नहीं तो जैसा आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वैसा आरोप हम भी आपके ऊपर लगाते हैं कि आपने (केंद्र सरकार) दो करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था। आज चौबीस करोड़ नौकरियां हिन्दुस्तानी बच्चों को मिलनी थीं लेकिन वे नहीं मिलीं। आपने पंद्रह लाख रुपये देने का वायदा किया था लेकिन वह भी नहीं दे पाए। लेकिन इस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप से समस्या का हल नहीं होगा। समस्या का हल तब होगा जब हम युवाओं के ऑलराउंड डवलपमैंट पर फोकस करेंगे।

हम मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं क्योंकि शिक्षा के जरिये ही बदलाव आएगा। जब तक हम शिक्षा में सुधार नहीं करेंगे तब तक हमारा यूथ समाज के लिए एसेट नहीं बनेगा। उसे एसेट बनाने के लिए हमें उसके डवलपमैंट पर फोकस करना पड़ेगा और उसकी ऑलराउंड डवलपमैंट सुनिश्चित करनी होगी। मैं दो-तीन दिन पहले एक टूर्नामेंट में गया था। वहां मार्च पास्ट के समय दो-तीन स्कूलों के बच्चे तो ठीक प्रकार से अटेम्प्ट कर रहे थे लेकिन बाकी बच्चे इस प्रकार चल रहे थे जैसे कोई शराबी शराब पीकर चलता है। उनके शरीर में हाथ और पांव की कोई सिमिट्री नहीं थी। वहां कई जगह पी0ई0टी0 और डी0पी0 भी हैं। मैंने उनसे भी कहा कि आप मेहनत क्यों नहीं करते? इसमें मार्च पास्ट के लिए तो कुछ विशेष खर्च भी नहीं लगेगा। कई जगह पी0ई0टी0 और डी0पी0 की पोस्टें ही नहीं हैं क्योंकि जब अधिक से अधिक स्कूल खोलने की बात आई तो सरकार में जो कर्ता-धर्ता थे उन्होंने यह भी देखा कि इसकी कॉस्ट को कैसे कम किया जाए। एक तरफ पब्लिक का प्रेशर है क्योंकि आज यह भी सच्चाई है कि कुछ लोग ही डिमांड करते हैं, सभी लोग डिमांड नहीं करते। यह भी सच्चाई है कि सभी लोग उस डिमांड को अप्रिशिएट भी नहीं करते। कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और पांच-सात लोग यह कहते हैं कि यहां कॉलेज खोल दो या यहां डिवीजन खोल दो। यहां माननीय सदस्य डॉ0 हंस राज जी ने भी कहा था कि बिजली बोर्ड का डिवीजन खोल दीजिए। लेकिन केवल डिवीजन खोलने से आपको सर्विसेज नहीं मिलेंगी। इसके लिए फील्ड स्टाफ चाहिए। केवल एक्सिअन के बैठने से कोई हल नहीं होने वाला। वहां मटीरियल की जगह मटीरियल चाहिए और फील्ड

01.09.2026/1510/AG/PB/3

स्टाफ भी चाहिए ताकि लोगों को समय पर सर्विसेज मिल सकें। इसके लिए जो टैक्नोलॉजी उपलब्ध है उसे अपनाने की आवश्यकता है। जैसे स्मार्ट मीटर और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उन पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। आज, जैसा कि मैंने पहले एक प्रश्न के जवाब में भी कहा था, हम सबको यह सोचना पड़ेगा कि अधिक एक्सपैंशन करके हम समाज और हिमाचल प्रदेश का भला नहीं कर रहे हैं। आज यदि पूरे देश के साथ और हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों के साथ तुलना करें तो जो विकसित राज्य हैं या जो फास्ट डवलपिंग राज्य हैं...

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

01.09.2026/1515/ए0एस0-ए0पी/-01

नगर एवं ग्राम योजन मंत्री जारी .....

हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों के साथ जो विकसित राज्य हैं या जो फास्ट डेवलपिंग स्टेट्स हैं, चाहे महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है या फिर आंध्र प्रदेश है। इनमें अगर आप सरकारी एम्प्लॉइज़ और पॉपुलेशन की रेश्यो देखें और उस रेश्यों की तुलना आप हिमाचल के साथ करें तो हम हाईएस्ट में आते हैं। हिमाचल प्रदेश की तुलना जम्मू-कश्मीर से होती है, हिमाचल प्रदेश की तुलना अरुणाचल से होती है। जब हम इस तरह के परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं। अगर सिर्फ सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने से ही प्रदेश डेवलप होता तो आज तक हम सभी राज्यों में सबसे ऊपर होते। इसलिए आज हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए और बाकी चीजों के लिए हमारा कितना पैसा बचना चाहिए ताकि हम बाकी चीजों पर भी खर्च कर सकें और हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। ऐसे कॉलेज हमने देखे हैं जहां लैब नहीं है, ऐसे कॉलेज हैं जहां बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, अच्छे क्लासरूम नहीं हैं। ऐसे स्कूल हैं जहां हर सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं। इसलिए हमारी सरकार की तरफ से जो प्रयास हुआ, माननीय मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के साथ सभी सहयोगियों का उसमें सहयोग रहा, जिससे कुछ स्कूलों को हम सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के तौर पर डेवलप करें। इसलिए सी0बी0एस0ई0 के साथ उनका एफिलिएशन किया गया ताकि बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मिल सके। हमारे आई0टी0आई0 इस तरीके से चल रहे हैं जैसे कि कोई सरकारी स्कूल हैं। वहां कई जगहों पर लैब तक नहीं है और कई जगह पर तो इंस्ट्रक्टर भी नहीं हैं। अभी हमने करीब 120 इंस्ट्रक्टर भरने की परमिशन ली है। जब हमारी सरकार बनी तो उस समय 163 पोस्टें तो पॉलिटेक्निक कॉलेजिस में खाली थी। जब हमारी सरकार बनी, उस समय 154 में से 115 कॉलेजों में प्रिंसिपल ही नहीं थे। जिस कॉलेज का हेड नहीं होगा, वह कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए इन सारी चीजों के बारे में सबको सोचना पड़ेगा। पब्लिक प्रेशर आता है, एम0एल0ए0 के ऊपर भी आता है और एम0एल0ए0 मुख्य मंत्री जी

पर प्रेशर बनाते हैं और उस चक्कर में इंस्टिट्यूशन पर इंस्टिट्यूशन खोले जा रहे हैं। जैसे मैं सुबह भी कह रहा था कि हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी काफी बड़ी है। हमारे पास सड़कों का नेटवर्क लगातार अच्छा डेवलप हो रहा है और

01.09.2026/1515/ए0एस0-ए0पी/-02

ऑनलाइन सर्विसेज की उपलब्धता भी है। आज बहुत सारी चीजें मोबाइल पर उपलब्ध हैं। उसके बावजूद भी हम नए इंस्टिट्यूशन खोल रहे हैं और नए इंस्टिट्यूशन प्रॉपर फंक्शनल नहीं होते हैं। क्या सिर्फ इंस्टिट्यूशन खोलने से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी? अगर ऐसा होता तो आज हिमाचल लीडर होता। अगर ज्यादा-से-ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोलने से सर्विसेज अच्छी मिल रही होती तो आज हमारे राजस्व से संबंधित अदालतों में इतने मामले लंबित नहीं होते। इन राजस्व अदालतों में विशेष अदालतें चलाई गई और उसमें सात लाख मामले निपटाने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछले 20 सालों में आप देख रहे हैं कि कितनी तहसीलें, कितनी सब-तहसीलें और कितने सब-डिवीजन खुल गए हैं। उसके बावजूद भी लोगों के राजस्व से संबंधित मामले क्यों लटके हैं? इन सारी चीजों के बारे में सोच-विचार करने की जरूरत है। आज हमने युवाओं को एम्पावर करने के लिए यह प्रयास किया है कि हमारे यूथ को बेहतर तरीके से स्किल्ड कर सकें। अब एच0पी0के0वी0एन0 का हमारा हिमाचल मॉडल कैसे बनता है, मैं इसको भी कंपेयर करना चाहता हूं। हिमाचल ने हिमाचल प्रदेश कौशल निगम लिमिटेड बनाया और महाराष्ट्र ने एम0के0सी0एल0 यानी महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाया। महाराष्ट्र ने उसमें दो करोड़ रुपये की अपनी इक्विटी डाली और आज लगभग 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का डिविडेंड एम0के0सी0एल0 महाराष्ट्र सरकार को वापिस कर चुका है। आज वह स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है। हमारा एच0पी0के0वी0एन0 का मॉडल था कि हमने ए0डी0बी0 से 600 करोड़ रुपये की फंडिंग करवाई। उन 600 करोड़ रुपये से कई जगहों पर बिल्डिंगें बनाई गई। आप वाकनाघाट में जाएं, वहां पर 100 करोड़ रुपये की बिल्डिंग खाली पड़ी है। मैं नाहन माननीय सदस्य श्री अजय सोलांकी जी के साथ गया। नाहन आई0टी0आई0 में सी0एल0सी0 बनाया, वह खाली पड़ा है। धर्मशाला में सिटी लाइवलीहुड सेंटर बनाया गया, वह भी खाली पड़ा है। सिर्फ बिल्डिंग बनाने से हम क्या साबित करना

चाहते हैं? अभी बिल्डिंग ही कंप्लीट नहीं हुई, सत्ती जी फर्निचर पहले खरीद लिया, कंप्युटर्स पहले ही खरीद लिए गये और यह सारी चीजें किराए के कमरों में रखी हैं। ये सभी चीजें कहीं-न-कहीं हमारे प्रदेश के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को एडवर्सली इम्पैक्ट कर रही हैं। इससे हम फ्यूचर जनरेशन का कोई भला नहीं कर रहे बल्कि उनका

01.09.2026/1515/ए0एस0-ए0पी/-03

नुकसान कर रहे हैं। इसके बारे में हम सबको सोच-विचार करना पड़ेगा क्योंकि अगर यह सिर्फ बीजेपी-कांग्रेस का मसला बन जाएगा तो फिर यूथ रिसीविंग एंड पर रहेगा। आप इस पर एग्री भी करेंगे कि जो हमारी जो डेमोक्रेसी है वह हमारे ऑर्गनाइज्ड ग्रुप्स और जिनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, उन्हीं को बेनिफिट देती है। यूथ की बार्गेनिंग पावर कुछ नहीं है। नंबर ऑफ यूथ और नंबर ऑफ अनइम्प्लॉयड यूथ ज्यादा है, लेकिन वे हड़ताल नहीं कर सकते। आज हड़ताल करेंगे, जैसे अभी जंतर-मंतर में किया गया। वह एक एक्सेप्शन हो सकता है क्योंकि बार-बार पेपर लीक हुआ और यह ठीक है, इन्होंने कहा कि वहां गाली-गलौच हुआ है और यह अधिकार किसी के पास नहीं है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

01.09.2026/1520/AT/AS/01

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जारी .....

चाहे हमारे बच्चे ही क्यों न हों, जैन जी बच्चों को संस्कार देना भी हमारा काम है। किसी को भी गाली देने का अधिकार नहीं है।

जंतर-मंतर पर यह एक अपवाद हो सकता है, लेकिन कितने युवा हैं जो अनइंप्लॉयड हैं और वह लंबे समय तक संघर्ष करते हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए उनकी बार्गेनिंग पावर नहीं है और उनको जितना उनका ड्यू शेयर है वह उन्हें इस डेमोक्रेसी के अंदर नहीं मिल पाता है इसलिए हमें यह जरूर देखना है कि डेमोक्रेसी

हाईजैक न हो और कुछ लोग केवल अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल न कर जाएं।

आज कई टीचर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें दुख होता है कि कई टीचर ऐसे भी हैं, जिन्होंने हमारे विधायक साहब पर प्रेशर बनाया हुआ है। वहां पोस्ट नहीं है, जहां वे जाना चाहते हैं और जहां वे सर्व कर रहे हैं, वहां बच्चे हैं। फिर भी उन्होंने विधायक पर यह प्रेशर बनाया है कि मुझे वहां से हटाकर, जहां वह जाना चाहते है वहां एक्स्ट्रा पर लगा दो, ताकि उसका पर्सनल काम सर्व हो जाए, लेकिन उससे बच्चे अफेक्ट होंगे।

हम तो इलेक्टेड लोग हैं। हमारे ऊपर तो प्रेशर बनेगा, यह स्वाभाविक है। हमें जो जनता चाहती है, जनता के हिसाब से करना पड़ता है। लेकिन जनता में प्रेशर कौन बनाता है? जनता में कुछ लोग हैं जो प्रेशर बनाएंग, सब नहीं बनाते है। इस बारे में भी हमें...(व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी, ने एक बड़ा अच्छी बात कही थी ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस।’ लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। आज जो सतपाल सिंह सत्ती जी, कह रहे थे कि हमेशा लीडर ही आगे आते हैं, लेकिन लीडर कोई जन्मजात नहीं होता। पब्लिक ने बनाया, तभी वह बने है और हम सिफ पांच साल के लिए ही लीडर बनते हैं। पांच साल बाद दोबारा इम्तिहान होता है। हमारी प्रमोशन की कंटीन्यूटी नहीं है।

01.09.2026/1520/AT/AS/02

या तो री-अपॉइंटमेंट होती है या फिर डिसमिसल या टर्मिनेशन होती है। इस में कंटीन्यूटी तो है नहीं।

जब गवर्नमेंट का साइज बढ़ता गया, उस समय यही हमारे सांसद महोदय थे, जिन्होंने पार्लियामेंट में यह कानून बनाया कि मंत्रियों की संख्या कम की जाए। उन्होंने अपने ऊपर कट लगाया, किसी और के ऊपर थोड़ा लगाया। मंत्री बनना हर किसी विधायक की इच्छा होती है और हर सांसद चाहता है कि वह मंत्री बने, लेकिन कट खुद के ऊपर लगाया। यह सिर्फ पॉलिटिकल लोग, इलेक्टेड लोग कर सकते हैं। बाकी लोगों के बस की बात नहीं है। हमें भी बाकी लोगों को इसी तरीके से इससे प्रेरणा लेनी चाहिए।

दूसरा, मैं हमारे टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित विषय है, क्योंकि एक स्किल्ड मैनपावर तैयार करना टेक्निकल एजुकेशन का मैंडेट है। हालांकि जितने संसाधन हमें चाहिए, उतने संसाधन हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। जिस तरह के इंस्टीट्यूशन हमें चाहिए, उस तरह के इंस्टीट्यूशन हम संसाधनों की कमी की वजह से डेवलप नहीं कर पाते हैं और दूसरा नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ज्यादा हैं।

अगर हम जवाहर नवोदय मॉडल पर जाते, जो हमारे NIT वाले मॉडल हैं, उस मॉडल पर जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। हम जगह-जगह सौ बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशन खोलने के बजाय, अगर पांच सौ बच्चों के लिए एक इंस्टीट्यूशन खोलते हैं और वहां उनको हॉस्टल की फैसिलिटी देते हैं, तो हम ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि ITI में ग्रुप इंस्ट्रक्टर की पोस्ट होती है। ग्रुप इंस्ट्रक्टर बोलता है, मेरा काम पढ़ाने का नहीं है। मैंने पूछा, आपका क्या काम है? तो बोलता है, हमारा मटेरियल परचेज और वर्कशॉप को सुपरवाइज करना होता है।

जहां बड़ी ITI हैं, वहां तो यह ठीक है, लेकिन जहां बच्चे 20 या 40 हैं वहां उनका क्या करेंगे? उनसे तो क्लास लेनी पड़ेगी। इसलिए हमने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि क्लास लेनी पड़ेगी। बिना क्लास लिए काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमने कोशिश की है कि जहां न्यू

01.09.2026/1520/AT/AS/03

एज कोर्सेज हैं जिनकी आज की डेट में जरूरत है, जैसे रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स, इस तरह के कोर्सेज भी शुरू किए गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में M.Tech की क्लासेज भी शुरू की गई हैं।

वहीं पर जो हमारे बच्चे कॉलेज में हैं, उनके लिए दो करोड़ रुपये का इनोवेशन फंड भी रखा गया है, ताकि वे स्टार्टअप का कोई प्रपोजल लेकर आएं। उनकी हैंड होल्डिंग के लिए भी प्रावधान रखा गया है और हम चाहते हैं कि वह बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। हमारा जो टेक्निकल एजुकेशन का डायरेक्टरेट था, उसमें इंजीनियरिंग और फार्मेसी का कोई प्रतिनिधि नहीं था। वहां भी हमने उसका री-ऑर्गनाइजेशन किया, ताकि इन दोनों क्षेत्रों के लिए डिप्टी डायरेक्टर वहां लगाया जा सके। इसके अलावा, एंटरप्रेन्योरशिप

डेवलपमेंट किया, ताकि उद्यमिता विकास की तरफ हम बच्चों का ध्यान रख सकें, उसके लिए अलग से एक पोस्ट हमने क्रिएट की।

ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप के लिए भी प्रावधान किया गया है। अप्रेंटिसशिप का बहुत अच्छा कार्यक्रम भारत सरकार का भी है, लेकिन पिछले समय में उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में जो अप्रेंटिस लगते हैं, उनकी सपोर्ट बंद कर दी है। उसको अगर आप चालू करा सकें, तो आप भी केंद्र सरकार से बात करें। प्राइवेट सेक्टर में तो यह सुविधा है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। ताकी बच्चों को अच्छी टेक्निकल ट्रेनिंग अच्छी तरह से मिले, इसके लिए यह जरूरी है और क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ज्यादा होने की वजह से, जिसका श्री सतपाल सिंह सत्ती जी, विरोध कर रहे थे, इसका एक दूसरा पहलू भी है।

जैसे ITI में भी किया गया है, भारत सरकार ने PM-SETU के नाम से एक नई योजना लॉन्च की है।

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी.....

01.09.2026/1525/av/dc/1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री--------- जारी

हम इसमें एक आई0टी0आई0 को हब आई0टी0आई0 डेजिगनेट कर रहे हैं। हमने उसमें नालागढ़ को डेजिगनेट किया है क्योंकि यह इंडस्ट्रियल एरिया के साथ है। हम उसके साथ बाकी आई0टी0आइज0 को एक स्पोक की तरह लिंक करेंगे ताकि एक आई0टी0आई0 में स्टेट ऑफ द आर्ट वर्कशॉप हो। वहां ट्रेनिंग फैसिलिटी हो ताकि बाकी बच्चे भी वहां जाकर कुछ समय के लिए ट्रेनिंग ले सकें। हमारे जो बच्चे पास आउट होंगे, उनके लिए हमने एक ऑनलाइन वेब पोर्टल रोज़गार सेतु के नाम से जारी किया है। इसको माननीय मुख्य मंत्री ने पिछले दिनों लॉन्च किया था। हम इसकी ऐप बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, इसको हम शायद 2 अक्तूबर को लॉन्च करेंगे। इसमें उस प्लेटफॉर्म के जरिए हमने लगभग 600 प्राइवेट इंडस्ट्रीज से बच्चों को आपस में लिंक किया है। उन इंडस्ट्रीज में जब भी कोई प्राइवेट जॉब निकलती है तो हमारे बच्चे उसको ऑनलाइन देख सकते हैं। उसमें

कंट्रोल हमारे डायरेक्टर (टेक्निकल एजुकेशन) का रहता है ताकि कहीं एक्सप्लॉयटेशन न हो। इसी तरीके से ओवरसीज इंप्लॉयमैंट एक्सचेंज है, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जहां दूसरे देशों के अंदर मैन पावर की ज्यादा जरूरत है क्योंकि वहां पर काम करने वाले लोग कम हैं। हम वहां की विदेशी भाषाओं में ट्रेनिंग देने का काम करेंगे जैसे जापानी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन इत्यादि भाषाएं हैं। जहां पर हमारे बच्चे सर्विसिज दे सकते हैं, वहां पर उनके लिए भी हम प्रयासरत हैं। इसके लिए मुख्य मंत्री जी ने बजट में एक स्किल एकेडमी घोषित की है और उसके ज़रिए ऐड-ऑन कोर्सिज या बच्चे जो डिग्री डिप्लोमा लेंगे; उनके लिए वहां पर फैसिलिटी क्रिएट करेंगे।

दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें जॉब क्रिएशन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। आज हमें इको टूरिज्म के ऊपर जैसे हमारी सरकार ने फोकस किया है और हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म में लगभग 27 साइट्स को प्राइवेट को दिया गया है। अब जैसे एक जगह पर हमारा एक गार्डन बनाया था, उसको मेंटेन करने के लिए हमें लाखों रुपए चाहिए थे। एक रैस्ट हाउस को मेंटेन करने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता था। अब जब हम उसे आउटसोर्स करते हैं तो वहां से हमें जी0एस0टी0 के तौर पर अप फ्रंट प्रीमियम मिलना शुरू हो जाता है यानी उसका लीज रैंट मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें नेचर टूरिज्म पर फोकस करना पड़ेगा

01.09.2026/1525/av/dc/2

क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लोग नेचर एन्जॉय करने आते हैं। यहां कोई बड़ी बिल्डिंग में रहने नहीं आते, यहां पर टूरिस्ट्स हमारे लैंडस्केप्स, पहाड़, वैलीज़, वन इत्यादि को देखने आते हैं। हमें इनको प्रोटैक्ट करने के साथ-साथ इन्हें ज्यादा-से-ज्यादा प्रमोट भी करना है।

इसके अतिरिक्त मैं हैल्थ टूरिज्म के बारे में कहना चाहूंगा। वर्तमान में जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है तो आने वाले समय में हमारा हैल्थ टूरिज्म बड़े स्केल पर जा सकता है। यहां पर जैसे हमारी रोबोटिक्स सर्जरी शुरू की गई है, हम इसके बारे में बाहर भी पब्लिसिटी करें। हमारे डॉक्टर्ज जिस दिन इसमें ज्यादा-से-ज्यादा ट्रेंड हो जाएंगे तो नेचुरली इसके लिए भी लोग बाहर से आएंगे। इसके अलावा स्पिरिचुअल टूरिज्म का

बहुत स्कोप है, क्योंकि Himalayas is known for spirituality. यहां पर पहले भी बड़े-बड़े संत-मुनियों ने लंबे-लंबे समय तक तपस्या की है और इसका आकर्षण पूरी दुनिया के अंदर है। आज भी अगर हम धर्मशाला में देखें तो फ्लाइट्स में कुल जितने यात्री होते हैं उसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा तो दलाई लामा जी के दर्शन के लिए आते हैं। उनका यहां बहुत बड़ा आकर्षण है। अतः हमें इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। यहां स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं खासकर हम अगर हाई अल्टिट्यूड ट्रेनिंग की बात करें। कई वर्ष पहले श्रीमती विद्या स्टोक्स जी ने अपने मंत्रीत्वकाल में शिलारू में एक हाई अल्टिट्यूड ट्रेनिंग सेंटर खोला था। वहां पर आज भी बाहर से लोग ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। हमारे पास जो मॉन्टेनियरिंग इंस्टिट्यूट जिस्पा और धर्मशाला में हैं, अगर होस्टल की और अच्छी फैसिलिटीज बनाई जाएं तो हमारे हाई-एंड ऑलंपियन्ज और एशियन प्लेयर्स वहां पर हाई अल्टिट्यूड ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। हमें इस तरीके से सोचना पड़ेगा। यहां पर एडवेंचर टूरिज्म का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और यहां एजुकेशनल टूरिज्म भी हो सकता है क्योंकि बाहर से लोग टूरिज्म बोलें या हम यहां इस प्रकार का प्रॉस्पेक्ट्स क्रिएट करें। आज हम देखते हैं कोटा जैसी जगह जहां इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है। वहां बच्चे हजारों की संख्या में हर वर्ष पढ़ने जाते हैं। उसी प्रकार से यहां भी अच्छे इंस्टिट्यूशन्ज बनें। हिमाचल प्रदेश में भी हम ऐसे इंस्टिट्यूशन क्रिएट करें जो कम-से-कम नेशनल लेवल के हों। वर्ल्ड रैंकिंग में अगर हो जाएं तो इससे बढ़िया कुछ बात नहीं हो सकती। लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में तो इंडिया के इंस्टिट्यूशन्ज बहुत कम हैं। इसलिए अगर कम-से-कम नेशनल लेवल पर भी हमारे फर्स्ट टॉप 100 में 20-25 इंस्टिट्यूशन्ज आ जाएं तो यह बहुत बड़ा

01.09.2026/1525/av/dc/3

आकर्षण हो सकता है। यहां जैसे बाहर से बी0सी0एस0 और सनावर में बच्चे पढ़ने आते हैं, उसी तरीके से हमें आगे सोचना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा न बोलता हुआ आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करुंगा। लेकिन विपक्ष से यह जरूर कहूंगा कि रेजोल्यूशन लाने से

पहले यह इंट्रोस्पेक्ट जरूर कीजिए क्योंकि इससे भी बड़े-बड़े वायदे भारत सरकार ने किए हैं जिसकी वजह से हमारा युवा आज हताश व निराश है और वे बहुत गुस्से में है।

टी सी द्वारा जारी

01.09.2026/1530/टी0सी0वी0/एच0के0-1
नगर एवं ग्राम योजना मंत्री.... जारी

जिसका उदाहरण आपने उस दिन जंतर-मंतर में देख लिया। इसलिए जब भी इस तरह का कोई प्रस्ताव लाया जाए तो प्रस्ताव का विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो, सकारात्मकता का माहौल बने और चर्चा को उन्हें एक दिशा देने की ओर ले जाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

सभापति : अभी बहुत से माननीय सदस्य बोलने को हैं, कृपया समय का ध्यान रखें। अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा जी भाग लेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सभापति महोदय, नियम 130 के अंतर्गत इस माननीय सदन में आदरणीय श्री रणधीर शर्मा जी ने युवाओं के लिए रोजगार से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाया है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय, युवा ही देश और प्रदेश का भविष्य है। जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2022 में अपने घोषणा-पत्र में युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, उसके आधार पर हिमाचल प्रदेश के युवाओं ने सभी पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस को इस उम्मीद के साथ समर्थन दिया था कि उन्हें नौकरियां मिलेंगी। कांग्रेस के घोषणा-पत्र में पहली कैबिनेट में एक लाख नौकरियां और पांच साल में पांच लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था। हिमाचल प्रदेश के युवाओं ने सोचा था कि उन्हें रोजगार मिलेगा और वे

सभी पार्टियों, नाते-रिश्तेदारों को छोड़कर कांग्रेस के साथ खड़े हुए तथा कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाए।

सभापति महोदय, कांग्रेस ने पौने चार साल में मात्र 23,000 नौकरियां दी हैं, वायदे के अनुसार केवल चार प्रतिशत नौकरियां दी गई हैं और 96 प्रतिशत नौकरियां अभी बाकी हैं। ...(व्यवधान) एक लाख नहीं सर, अभी तक चार लाख नौकरियां देनी थीं और चार

01.09.2026/1530/टी0सी0वी0/एच0के0-2

साल हो गए हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं। आपने वायदे के अनुसार अभी तक केवल चार प्रतिशत नौकरियां दी हैं और 96 प्रतिशत नौकरियां अभी बाकी हैं।

सभापति महोदय, पिछली गवर्नमैंट में आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने युवाओं को रोजगार देने के लिए हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं बनाई थीं। 'मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना' में पुरुषों के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी, महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत, विधवाओं के लिए 35 प्रतिशत, एस0सी0 और एस0टी0 के लिए 30 प्रतिशत तथा दिव्यांगजनों के लिए 35 प्रतिशत सब्सिडी थी। वे योजना बिल्कुल स्थिर हो गई है और किसी भी युवा को स्वावलंबन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

इसके अतिरिक्त पूर्व सरकार के समय में 'मुख्य मंत्री युवा आजीविका योजना', 'मुख्य मंत्री स्टार्टअप इनोवेशन योजना', 'कौशल विकास भत्ता योजना' 'बेरोजगारी भत्ता योजना' और 'औद्योगिक कौशल विकास योजना' थीं। ये सभी योजनाएं युवाओं के लिए बंद कर दी गई हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता बंद हो गया है और जो युवा बीमार होते हैं उनके लिए स्वास्थ्य योजनाएं भी बंद कर दी गईं जिनमें 'हिमकेयर योजना' और 'सहारा योजना' शामिल हैं। ये सभी योजनाएं बंद कर दी गई हैं।

सभापति महोदय, मैं इस माननीय सदन में एक बात कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के अधीन कई अर्धसैनिक बलों में भर्तियां हुई हैं जिनमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आई0टी0बी0पी0, सी0आर0पी0एफ0, एस0एस0बी0, सी0आई0एस0एफ0 और असम राइफल शामिल हैं।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

1-9-2026/1535/NS-HK/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा-----जारी

इन सबमें बहुत सारी भर्तियां हुई हैं। थल सेना, वायु सेना और जल सेना में भी भर्तियां हुई हैं। मैं आपको एक ही इंस्टैंस बताना चाहता हूं। मेरे कुपवी क्षेत्र में आर्मी में एक ही भर्ती में 60 बच्चे लगे थे। केंद्र सरकार ने मेरे कुपवी क्षेत्र के 60 परिवारों के बच्चों को आर्मी में भर्ती होने का अवसर दिया है। मैं केंद्र सरकार का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि केंद्र सरकार बहुत सारे इंप्लॉयमैंट के अवसर दे रही है।

सभापति महोदय, हिमाचल का तो आपको पता ही है कि हिमाचल की जवानी और हिमाचल का पानी दोनों देश के लिए यूज हुए हैं। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश के पानी से प्रदेश के युवाओं के हित में कोई योजना बना दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि हिमाचल के युवा बहुत ही मेहनती हैं। जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूं कि हमारे यहां सेब के हाई डेंसिटी प्लांट्स हैं। एक बीघे में करीब 250 पौधे लगते हैं। नौजवान उन 250 पौधों से एक ही वर्ष में 3 लाख रुपये के सेब पैदा कर रहे हैं और दूसरे वर्ष भी फसल आ रही है। इसमें किसी चीज का इंतजार नहीं करना पड़ रहा है परंतु पहाड़ी क्षेत्र में युवाओं के पास पानी नहीं है। अगर सरकार उनके लिए पानी के भंडार बना दे तो पहाड़ी क्षेत्र में और किसी भी अन्य क्षेत्र में चाहे ऊना, बिलासपुर या हमीरपुर हो, वहां पर भी अलग-अलग फ्रूट्स लगाए जा सकते हैं। लेकिन उन युवाओं को पानी नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वे प्लांटेशन, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की तरफ नहीं जा रहे हैं। इसके लिए हमें योजनाएं बनानी पड़ेंगी। सभापति महोदय, अगर हमने युवाओं के लिए योजनाएं बना दीं और बड़े-बड़े तालाब तथा पानी के भंडार बना दिए तो पूरे प्रदेश के नौजवान सब्जियों, सेब, नाशपाती पैदा कर सकते हैं और निचले क्षेत्रों में संतरे, नींबू तथा बहुत सारी सब्जियां जैसे टमाटर, आलू, फूलगोभी और बंदगोभी की खेती कर सकते हैं जिनका रेट बहुत अच्छा मिलता है।

अगर पानी अपना होगा तो हम ऑफ-सीजन की सब्जियां भी तैयार कर सकते हैं। अगर इस दिशा में हर क्षेत्र में पानी का इंतजाम किया जाए तो युवा रोजगार ढूंढने के बजाय अपना रोजगार घर में तैयार करेंगे।

1-9-2026/1535/NS-HK/2

सभापति महोदय, नौकरियां तो कांग्रेस सरकार ने बंद की हैं और नौजवान बहुत फ्रस्ट्रेट हुए हैं जिससे वे नशे की तरफ जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि नशे को रोकना बहुत जरूरी है। नशा दूरदराज के क्षेत्रों में, गांवों में घरों तक पहुंच गया है। इसमें कौन संलिप्त है, युवा कैसे नशे से बचें और कौन-कौन लोग इसे सिर्फ पैसे कमाने के लिए बेच रहे हैं, इस पर ध्यान देना जरूरी है। जो लोग इसमें स्मगलर के रूप में लगे हैं उनके लिए कानून सख्त बनाकर उनकी सारी संपत्तियां जब्त होनी चाहिए। अगर हमारा युवा बचेगा तो हमारा प्रदेश बचेगा। युवाओं को बचाने के लिए चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हम सबको मिलकर इसमें सख्त कानून बनाना चाहिए। यह मैं कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे स्कूल बंद हुए और आई0टी0आई0 जैसे संस्थान बंद हुए। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी आई0टी0आई0 बंद हुई है। हिमाचल प्रदेश में हमारी बेटियां बड़ी खुश थीं जब कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि 18 वर्ष से ऊपर हिमाचल प्रदेश की सभी बेटियों को 1500 रुपये मिलेंगे। बेटियों व युवाओं ने भी सीधे कांग्रेस को वोट डाले। आज प्रदेश के अंदर सारी बेटियां और युवा डंडे लेकर गांव में खड़े हैं कि कांग्रेस वाले वर्ष 2027 में जब वोट मांगने आएंगे तो फिर बताएंगे कि आपने वर्ष 2022 में हमसे झूठी घोषणाओं और झूठे आश्वासनों से वोट लिए थे, पहले पिछला हिसाब क्लीयर करें फिर आगे के लिए हम आपसे अगली बात करेंगे।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

01.09.2026/1540/RKS/HK-1

श्री बलबीर सिंह वर्मा... जारी

सभापति महोदय, मुझे दुःख के साथ एक और बात कहनी पड़ रही है कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में भांग की खेती प्रारम्भ करना चाहती है। मैं उन मुख्यमंत्रियों का धन्यवदी हूं जिन्होंने सख्त कानून बनाकर भांग की खेती पर रोक लगाई और यह नशा बंद करवाया। इस भांग के नशे में युवाओं के साथ अन्य लोग भी संलिप्त थे। मेरी आपके माध्यम से विनती है कि हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती नहीं होनी चाहिए। भांग एक ऐसी चीज़ है जो युवाओं का भविष्य और जवानी ही खत्म कर देगी। भांग का नशा शरीर के लिए अत्यंत खतरनाक है। यदि इसकी खेती को बढ़ावा दिया गया तो युवा स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसलिए प्रदेश में भांग की खेती की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार युवाओं को आत्मघाती परिस्थितियों की ओर धकेलने वाली एक और योजना के रूप में लॉटरी प्रारम्भ करने की बात कर रही है। बड़ी मुश्किल से वर्ष 2002 में आदरणीय प्रोफैसर प्रेम कुमार धूमल जी ने लॉटरी व्यवस्था को बंद किया था। मैं आग्रह करता हूं कि इसे दोबारा प्रारम्भ न किया जाए। अनेक लोगों ने लॉटरी के चक्कर में महिलाओं के जेवरात, अपने खेत-खलिहान, बागीचे एवं सम्पत्तियां दांव पर लगा दी थीं और परिवारों के लिए कुछ भी नहीं बचता था। हिमाचल प्रदेश में बड़ी मुश्किल से यह लॉटरी बंद हुई है इसलिए युवाओं को इसमें नहीं फंसाया जाना चाहिए। यहां उपस्थित सभी माननीय विधायक जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में यह प्रावधान है कि उद्योगों में लगभग 70 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के युवाओं को दिया जाए। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि व्यवहारिक स्तर पर 25 प्रतिशत युवाओं को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। मेरे क्षेत्र सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में बिजली के प्रोजैक्ट तथा अनेक इंडस्ट्रीज़ स्थापित हैं लेकिन उनमें हिमाचल प्रदेश के युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि इस संबंध में सख्त कानून बनाया जाए। अगर हिमाचल प्रदेश में यह सख्त कानून बन जाए तो यहां जितनी भी इंडस्ट्रिज स्थापित हैं उनमें 70 प्रतिशत रोजगार अनिवार्य रूप से स्थानीय युवाओं को प्राप्त होंगे। बाहर से आने वाले उद्योगपति हमारे प्रदेश की शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भूमि का फायदा उठा रहे हैं जबकि यहां स्थानीय युवाओं को अपेक्षित रोजगार नहीं मिल रहा है। मेरी विनती है कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्त

कानून बनाया जाए। जो स्थानीय लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार देने का प्रावधान है वह धरातल पर इंप्लीमेंट होना चाहिए। आज हमारे युवा नशे के साथ-साथ

01.09.2026/1540/RKS/HK-2

विभिन्न बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की लगभग 75 प्रतिशत भूमि फॉरेस्ट लैंड के अंतर्गत आती है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट-1980 के तहत बड़ी मात्रा में वेस्ट लैंड को भी वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया जबकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता शुद्ध हवा, स्वच्छ पर्यावरण और हरित क्षेत्र संरक्षित रखकर पूरे देश को लाभ पहुंचा रही है। हम यहां प्लांटेशन कर रहे हैं। प्रदेश की लगभग 75 प्रतिशत भूमि ग्रीनरी के रूप में संरक्षित है लेकिन इसके बदले राज्य को कुछ नहीं मिल रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गांवों में खेल के मैदानों का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। प्रदेश से इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। जिस प्रकार एफ0आर0ए0 में 13 मदों को शामिल किया गया है उसी प्रकार खेल मैदानों के लिए 14वीं मद को भी शामिल किया जाना चाहिए। यदि गांवों में खेल मैदान विकसित किए जाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे युवाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज स्थिति यह है कि बुजुर्गों का इलाज हॉस्पिटलों में नहीं हो पा रहा है जबकि युवा और बच्चे बड़ी संख्या में हॉस्पिटलों तक पहुंच रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि बच्चों को खेलने के लिए गांवों और विद्यालयों में मैदान उपलब्ध नहीं हैं जिसके कारण बच्चे खेल-कूद की गतिविधियों में भाग नहीं ले पा रहे हैं। हमारी पीढ़ी खेत-खलिहानों सहित विभिन्न शारीरिक गतिविधियों में सक्रिय रहती थी लेकिन वर्तमान पीढ़ी के बच्चों को ऐसे अवसर नहीं मिल रहे हैं। इसलिए एफ0आर0ए0 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को जिन 13 मदों में रियायत प्रदान की गई है उनके अतिरिक्त केन्द्र सरकार को यह प्रस्ताव भी भेजा जाए कि गांवों तथा स्कूलों में खेल मैदानों की स्थापना के लिए एक अतिरिक्त 14वीं मद को शामिल किया जाए।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

01.09.2026/1545/बी.एस./ वाई.के.-1

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी...

गांव में युवाओं को व्यस्त रखने के लिए लाइब्रेरियां भी बनाई जाएं। जैसा मैंने आपको कहा कि हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हिमाचल प्रदेश के युवाओं को मिल सकता है लेकिन हमें विलेज टूरिज्म की पॉलिसी बनानी पड़ेगी।

विलेज टूरिज्म में गांव में लोगों ने बहुत सुंदर-सुंदर घर बनाए हैं। उनके 10-10 और 15-15 कमरों के घर हैं। आप इनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की अनुमति दें और इन्हें गवर्नमैंट लाइसेंस दे और विलेज टूरिज्म के लिए अगर हम एक पॉलिसी बनाते हैं तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि युवाओं को घर में ही रोजगार मिलेगा। वे अपना बगीचा भी देखेंगे और इनकम भी घर में होगी।

विलेज टूरिज्म के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल तक के टूरिस्ट गर्मियों में और बरफ में पहाड़ की तरफ आते ही हैं परंतु उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अगर स्वच्छ पानी, सड़क तथा बिजली की तीन सुविधाएं हमारे यहां उपलब्ध हो जाएं तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि पूरे प्लेन क्षेत्र के लोग पहाड़ की तरफ बढ़ेंगे। इससे हमारी इनकम भी होगी और युवाओं को घर में ही रोजगार भी मिलेगा।

इसके लिए भी मेरी सभापति महोदय, सरकार से विनती है कि टूरिज्म के लिए ईको टूरिज्म पॉलिसी, विलेज टूरिज्म पॉलिसी, हेल्थ टूरिज्म पॉलिसी और स्पिरिचुअल टूरिज्म पॉलिसी बनाई जाए। पहले ऋषि-मुनि और साधु-संत पहाड़ों में ही तपस्या करते थे। यहां से सारी शक्तियां लेकर जाते थे और फिर पूरी दुनिया में वे शक्तियां बांटते थे। मेरी आपसे यह विनती है कि अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटी पहाड़ों में शुरू हो जाएगी तो देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए यहां आएंगे।

01.09.2026/1545/बी.एस./ वाई.के.-2

इसके लिए भी पॉलिसी के माध्यम से व्यवस्था बनाई जाए और सरकार की योजना प्रॉपर हो तथा लोगों का विश्वास हो कि हिमाचल में गांवों में मैं रह सकता हूं तो इसका बहुत लाभ होगा। अन्यथा टूरिस्ट को यह डर लगता है कि कहीं मुझे इलीगल तरीके से तो नहीं रखा जा रहा है, इसके लिए कानूनी पास है भी या नहीं है।

आपने देखा होगा तो धोनी भी एक ऑर्चर्ड में 11 दिन रहा था। बहुत लोगों के बड़े-बड़े ऑर्चर्ड हैं और इसमें युवाओं को काफी रोजगार मिल सकता है। एक और माउंटेनियरिंग एक्सपेडीशन का विषय है। हमारा माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूशन मनाली में है। ...(घंटी)... सभापति महोदय, अभी तो 17 मिनट हुए हैं कुछ माननीय सदस्य 35 मिनट बोल चुके हैं।

इसमें मेरी आपसे माउंटेनियरिंग एक्सपेडीशन को लेकर विनती है। हमारे जितने भी पहाड़ हैं वहां देश-दुनिया के सारे लोग ट्रेकिंग पर जाते हैं। ट्रेकिंग हमारे हिमाचल प्रदेश में लीगली है परंतु हिमाचल प्रदेश में ट्रेकिंग के रूट को अभी तक हमने नोटिफाइड नहीं किया हुआ है।

हिमाचल प्रदेश में ट्रेकिंग के रूट नोटिफाई किए जाएं और बाहर के टूरिस्ट को पता हो कि यह लीगली ट्रेकिंग रूट है। उसमें गवर्नमैंट की फैसिलिटी हो। पानी बिजली और जो भी आवश्यक फैसिलिटी हैं वे उपलब्ध हों। इससे हमारे माउंटेनियरिंग एक्सपेडीशन और ट्रेकिंग के लिए बहुत लोग बाहर से आ सकते हैं।

हमारा हिमाचल प्रदेश एजुकेशन हब भी बन सकता है। हमारे यहां पहले भी बहुत अच्छे स्कूल हैं और आगे भी अच्छे स्कूल बन सकते हैं। इसके लिए गवर्नमैंट से विनती है कि टूरिज्म की जितनी भी पॉलिसी हैं उनमें युवाओं को इंसेंटिव मिले। जब तक इंसेंटिव नहीं मिलेगा तब तक इसमें कुछ नहीं होने वाला।

युवाओं के लिए मैं सब्जी और फ्रूट के लिए कह रहा हूं इसके लिए भी पॉलिसी बनाई जाए। हाई डेंसिटी प्लांट 1,000 रुपये का मिलता है और लगाते-लगाते 2,000 रुपये का पड़ता है। अगर युवाओं को 500-500 रुपये का भी आपने उसमें कुछ बेनिफिट दे दिया तो पहाड़ के

01.09.2026/1545/बी.एस./ वाई.के.-3

सारे युवा हाई डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं और पहली साल लगाते हैं तो पहली साल ही कुछ-न-कुछ कमाते हैं और दूसरी साल पूरा पैसा उसका कमा रहे हैं और बहुत लोग इसमें हाई डेंसिटी में जा रहे हैं। इसमें न मौसम की कोई दिक्कत है न फसल की कोई दिक्कत है और न क्वालिटी की कोई दिक्कत है। तीनों चीजों की कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी हंड्रेड प्रतिशत बढ़िया है और फसल 100 प्रतिशत लगनी है। सिर्फ सरकार की तरफ से इसमें कोई इनसेंटिव नहीं मिल रहा है, सर। सरकार की तरफ से अगर कोई इनसेंटिव मिल जाए तो बहुत सारे युवा इस तरफ बढ़ेंगे। यह मैं कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, भाषणों से, आश्वासनों से और झूठी गारंटियों से कोई भी देश और प्रदेश का युवा खुश नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली उनके लिए कुछ-न-कुछ करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि माननीय श्री जय राम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश में 'मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना' लाई थी।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

01.09.2026/1550/DT/YK-1

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी....

कोई भी देश और प्रदेश का युवा खुश नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली उनको कुछ-न-कुछ करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि माननीय श्री जय राम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई थी- उसमें बहुत से युवाओं ने इस योजना के माध्यम से खुद तो कमाया ही लेकिन बहुत से अन्य युवाओं को भी रोजगार दिए। यानी प्रदेश का युवा नौकरी देने वाले वाले बने, स्वाबलंबी बने। हिमाचल प्रदेश में हजारों युवाओं ने लाखों युवाओं को उसी योजना के माध्यम से नौकरियां दी। उस योजना के माध्यम से एक तो इंसेंटिव युवाओं को मिलता था, व्यवसाय करने में सब्सिडी मिलती थी। वे युवा उसी सब्सिडी से अपना लोन भी कम कर देते थे। आजप्रदेश में ऐसे कितने युवा हैं जिन्होंने

अपने उद्योग लगाए हुए हैं और उसी से अन्य युवाओं को भी वे युवा नौकरी दे रहे हैं। अगर वर्तमान सरकार भी ऐसी ही कोई योजना लाती जिससे हजारों युवाओं को व्यवसाय मिलेगा मैं दावे से कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी बहुत कम हो जाएगगी।

सभापति महोदय, इस सदन में हमारे साथी सदस्यों द्वारा जो अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव चर्चा हेतु लगाया गया है, उसका सभी को समर्थन करना चाहिए। इस प्रस्ताव को वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

01.09.2026/1550/DT/YK-2

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल जी। माननीय सदस्य, प्लीज़ एक मिनट बैठ जाइए, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप कुछ बोलना चाहा रहे हैं?

श्री जय राम ठाकुर : सभापति महोदय, इतने महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है और मैं देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष के चालीस में से केवल दस-ग्यारहा सदस्य ही इस मान्य सदन में बैठे हैं। जब भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती है तो सत्ता पक्ष के लोगों को सदन में उपस्थित रहना चाहिए-लेकिन अभी जो स्थिति हैं उसमें मुझे लगता है कि सदन का कोरम भी पूरा नहीं है। कोरम मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सत्ता पक्ष की होती है। हम लोग इस गंभीर चर्चा को लाए हैं, हमारे माननीय सदस्य जो इस चर्चा में भाग ले रहे हैं वह प्रदेश हित में काफी अच्छे सुझाव दे रहे हैं पर मैं देख रहा हूं कि अधिकारी दीर्घा में भी अधिकारी नहीं बैठे। मुझे लगता है कि सरकार एक साल पहले ही आराम के मूड में आ गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार को यह विषय गंभीर लगता ही नहीं है। प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने का विषय आपके लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं। प्रदेश के विकास के लिए काम करने का विषय तो है ही नहीं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस विषय पर बहुत लंबे-लंबे भाषण हम इस मान्य सदन में सुनते हैं लेकिन यह बहुत गंभीर बात है कि उस विषय पर जो नियम-67 के अंतर्गत चर्चा लाई गई थी उसे कन्वर्ट करके नियम-130 में लगाया गया और सदन में इस पर चर्चा हो रही है तो चर्चा के दौरान

सरकार गंभीर ही नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार ने इस बारे में विचार करने का मन छोड़ दिया है।

01.09.2026/1550/DT/YK-3

सभापति : माननीय नेता प्रतिपक्ष इस समय सदन में कोरम पूरा है कुछ सदस्य बाहर गैलरी में ही थे वे भी अब सदन में आ गये हैं।

श्री जय राम ठाकुर : सभापति महोदय, कोरम के लिए सदन में तेईस सदस्यों को होना आवश्यक है। सदन में अभी दो ही मंत्री बैठे हैं- बाकी मंत्री कहां हैं? मेरे विचार में तो उनको मंत्री बना देना चाहिए जो इस सदन में बैंठे तो सही। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि सरकार की गंभीरता इस बात से ही प्रतीत होती है कि सदन के अंदर चर्चा हो रही है और न मुख्य मंत्री जी यहां हैं और न ही उप-मुख्य मंत्री जी ही हैं तथा सदस्यों की संख्या भी बहुत कम है। इसलिए प्रदेश सरकार को नौजवानों से कोई लेना-देना नहीं है, यह साबित होता है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संसदीय कार्य मंत्री।

संसदीय कार्यमंत्री (उद्योग मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय श्री जय राम ठाकुर जी अभी आए हैं पहले वे सदन में थे। इन्होंने नॉन-इश्यू को इश्यू बनाना था तो उन्होंने ले लिया। मैं एक बात इनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि यह जो प्रस्ताव है यह विपक्ष द्वारा लाया गया है और जिन सदस्यों ने इसे पेश किया है वे भी सदन में नहीं बैठे हैं। जो सदस्य यह चर्चा लेकर आएं उनमें से सिर्फ एक ही सदस्य इस सदन में बैठें हैं शेष चार सदस्य कहां हैं? वे चार सदस्य तो ग़ायब हैं।

सभापति महोदय, विपक्ष के 28 विधायकों में से मात्र आठ विधायक ही सदन में बैठे हैं। यह इनकी सीरियसनेस बताता है कि इस इश्यू पर ये कितने सीरियस हैं। अगर गंभीर होते तो

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

01.09.2026/1555/ए.जी.-एन.जी./1

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री)......... जारी

इनके सारे-के-सारे माननीय सदस्य यहां पर बैठे होते। अब माननीय सदस्य, श्री सुधीर शर्मा को भी बुला लिया गया है। Government is very serious about it. We are noting everything, whatever is being raised by the Hon'ble MLAs. We will give a reply. We are serious about it. ...(Interruption)

सभापति : माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा जी, कंसर्न मंत्री यहीं पर बैठे हुए हैं। अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री किशोरी लाल भाग लेंगे।

01.09.2026/1555/ए.जी.-एन.जी./2

श्री किशोरी लाल : सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा, श्री सुधीर शर्मा, श्री राकेश जम्वाल, डॉ0 हंस राज और श्री जीत राम कटवाल द्वारा लाए गए प्रस्ताव 'युवाओं के लिए रोजगार सन्दर्भित गारंटी के कार्यान्वयन बारे यह सदन विचार करे', की चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, जब हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार का गठन हुआ, तब हमारी सरकार को पिछली सरकार से लगभग 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज तथा लगभग 11,000 करोड़ रुपये की देनदारियां विरासत में मिलीं। उसके बावजूद प्रदेश सरकार व आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने पहली कैबिनेट में फैसला लिया और हमारी जो गारंटियां हैं, उनको पूरा करने के लिए ओ0पी0एस0 को लागू किया। प्रदेश के लगभग 1,36,000 कर्मचारियों और उनके परिवारों को इसका सीधा लाभ पहुंचा है। इस प्रकार से प्रदेश

सरकार ने अपनी पहली गारंटी पूरी की। इसी तरह प्रदेश को कैसे विकास के मामले में आगे ले जाया जाए, इस दिशा में प्रदेश सरकार ने काम किया। प्रदेश सरकार का दायित्व है और प्राथमिकता रही है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया जाए। उसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने सरकारी स्तर पर भर्तियां करते हुए रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। प्रदेश के जल शक्ति विभाग में मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्तियां हुईं हैं। इसमें 6,000 लोगों की भर्ती हुई तथा 4000 लोगों की भर्ती होने जा रही है। इसी तरह वन मित्र व पशु मित्र लगाए गए, डॉक्टरों की भर्तियां हुईं, स्टाफ नर्सों की भर्तियां हुईं, असिस्टेंट स्टाफ नर्सों की भर्तियां हुईं, वाटर कैरियर लगाए गए, आशा वर्कर्स लगाई गईं, आंगनबाड़ी हेल्पर व कार्यकर्ता लगाए गए। इनके अलावा बिजली बोर्ड में भी भर्तियां होने जा रही हैं। इसी तरह हर विभाग में भर्तियां की जा रही हैं।

01.09.2026/1555/ए.जी.-एन.जी./3

अगर मैं शिक्षा विभाग की बात करूं तो शिक्षा विभाग में जे0बी0टी0 से लेकर प्रिंसिपल तक लगभग 2000 पद भरे गए और अभी लगभग 3000 पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया जारी है। अभी इन भर्तियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है और लगातार जारी है। अलग-अलग विभागों में भर्तियां हुई हैं और होने जा रही हैं। पिछली सरकार की तरह नहीं कि पुलिस की भर्तियों में पेपर लीक हुए। यहां पर पूर्व मुख्य मंत्री जी हंस रहे हैं। आपकी सरकार में पेपर लीक हुए हैं। सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, हमीरपुर में नौकरियां बेची गईं और आप हंस रहे हैं। यह प्रदेश के युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है। मैं उसी मुद्दे को उठा रहा हूं। आज प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिल रही है और आप कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है। जो ठीक बात है, सत्य बात है, उसका आप मजाक में उड़ा रहे हैं। यह सब आपके कार्यकाल में हुआ था। आपकी केन्द्र सरकार ने भी कई वादे किए थे। दो करोड़ युवाओं को नौकरी दे देंगे, क्या नौकरी लग गई? 15 लाख रुपये हर खाते में डाल देंगे, क्या खाते में चला गया?

(श्री मोहन लाल ब्राक्टा, माननीय सभापति पदासीन हुए।)

महंगाई कम कर देंगे, आज प्याज के भाव 70 रुपये, आलू के भाव 40 रुपये, चीनी के भाव 75 रुपये और गुड़ के भाव 90 रुपये हैं, महंगाई से हा-हा कार मची हुई है। लेकिन यहां पर आप मजाक उड़ा रहे हैं और हंस रहे हैं। हंसना बंद करो और पहले अपनी सरकार का कार्यकाल देखो

पी0बी0 द्वारा......जारी

01.09.2026/1600/AG/PB/1

श्री किशोरी लाला जारी...

हंसना बंद कीजिए और पहले अपनी सरकार का कार्यकाल देखिए। आज प्रदेश सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लेकर आई है। जिसके तहत सरकार गेहूं की खेती करने वाले किसानों से गेहूं 80 रुपये प्रति किलो और हल्दी पैदा करने वाले किसानों से हल्दी 150 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है...(व्यवधान) और ये हंस रहे हैं। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूध के मूल्य में भी बढ़ोतरी की है। गाय के दूध का मूल्य 61 रुपये और भैंस के दूध का मूल्य 71 रुपये किया गया है। डगवार में 250 करोड़ रुपये की लागत से दूध संयंत्र लगाया जा रहा है। यह संयंत्र हाल ही में तैयार हो जाएगा और गांवों में जो समितियां बनी हैं उनके माध्यम से दूध खरीदा जाएगा तथा लोगों को रोजगार मिलेगा। ...(व्यवधान) ये यहां हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। यह हंसने की बात नहीं है। यह बहुत गंभीर मसला है और युवाओं को रोजगार देने का सवाल है। मैं चाहता हूं कि अधिकतम युवाओं को रोजगार मिले और इसके लिए कोई नीति बनाई जाए। केवल प्रस्ताव रखने से यह मसला हल नहीं होगा बल्कि इसके लिए नीति बनानी पड़ेगी।

आज तक हिमाचल प्रदेश को खड़ा करने में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है लेकिन इस बात की कोई चर्चा नहीं करता। आज तक जो कुछ बना है उसे किसने बनाया?

हिमाचल प्रदेश को किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। पूर्ण राज्य का दर्जा किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आपको याद है कि भा0ज0पा0 में हिमाचल प्रदेश को लेकर मजाक किया जाता था और कहा जाता था कि स्टेट हुड मारो ठुड तथा इस प्रकार की हिमाचल को लेकर कई तरह की बातें कही जाती थीं। लेकिन आज युवाओं के रोजगार का जो मसला है मैं भी इसका पक्षधर हूं कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और वह रोजगार स्थायी होना चाहिए। मैं स्थायी रोजगार देने की मांग कर रहा हूं। कौन इनकार करता है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए? लेकिन प्रदेश के हालात क्या हैं? कर्जे के ऊपर कर्जा और कर्जे के ऊपर कर्जा है। आज उस कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा लिया जा रहा है। आउटसोर्स की भर्तियां किसने शुरू की? पूर्व सरकार ने शुरू की थी। आज उस पैटर्न पर ही भर्तियां हो रही हैं। इनके पास हंसने के सिवाय कोई काम नहीं है। केवल हंस दिया और मजाक उड़ा दिया, यही काम रह गया है।

01.09.2026/1600/AG/PB/2

(श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए।)

मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक खेती को सरकार ने बढ़ावा दिया है और उस खेती के माध्यम से आज हमारा किसान खुशहाल हुआ है तथा उसने प्राकृतिक खेती करना आरंभ किया है। जहां फसल को जानवर नुकसान पहुंचाते थे वहां हल्दी की खेती शुरू हुई है। हल्दी को न पशु खाते हैं और न ही कोई दूसरी चीज नुकसान पहुंचाती है। इसलिए लोगों का रुझान उस ओर बढ़ा है।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाया गया है। आज कांगड़ा में एयरपोर्ट की काफी हद तक कंप्लीशन हो चुकी है। जहां जमीन एक्वायर हुई है वहां बड़े जहाज उतरेंगे, सैलानी आएंगे और हिमाचल का रुख करेंगे। इससे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा। पर्यटन हिमाचल प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। यहां जितना अधिक पर्यटन आएगा और पैसा खर्च करेगा, उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा।

अगर मैं पिछली बात करूं तो हमारे देश की सरकार में आदरणीय डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने 'महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना' शुरू की थी। केंद्र की वर्तमान सरकार ने उसे खत्म कर दिया। उससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। यह गारंटी क्यों खत्म की गई? क्योंकि उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम जी-राम-जी रख दिया गया। अब स्कीम का बट्टा फ्लैट हो गया और अब लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए स्थायी रोजगार देने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों को कोई रणनीति बनानी होगी। केवल आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सभी युवाओं के हितैषी हैं तो युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या रणनीति बनाई जाए इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज के युवाओं ने अपने काम-धंधे सारे छोड़ दिए हैं। कोई काम नहीं करना चाहता और केवल सरकारी नौकरी ढूंढते हैं। पहले जो लोग पढ़ते नहीं थे वे अपना रोजगार चलाने के लिए काम सीखते थे, टैक्निकल एजुकेशन हासिल करते थे और उससे गांवों में रोजगार के साधन उपलब्ध होते थे। आज वह सारी चीज खत्म हो गई है। इसलिए इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

01.09.2026/1600/AG/PB/3

सरकार भी रोजगार के लिए सख्त कदम उठाएगी और रोजगार जो है वह देना सरकार

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

01.09.2026/1605/ए0एस0-ए0पी/-01

श्री किशोरी लाल जारी .....

की प्राथमिकता है और सरकार दे भी रही है। आगे भी सरकार रोजगार देती रहेगी। हमारे जो युवा हैं और जो दूसरे लोग हैं, जिनको रोजगार की तलाश है। आज मैं प्रदेश की बात

करूं तो स्थानीय लोगों में कोई मिस्त्री का काम नहीं करता और न ही कोई लेबर का काम करता है। आज दूसरे राज्य चाहे वे राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के लोग हो आज वे हिमाचल प्रदेश में रोजगार कमा रहे हैं और यहां गाड़ियां आदि खरीदकर अपने घर ले जा रहे हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के लोग तो कोई काम ही नहीं करना चाहते हैं। यह भी एक विडंबना है। यहां के लोग अगर काम करते तो जो बाहर के लोग प्रदेश में आकर पैसा कमा रहे हैं, वह पैसा हमारे यहां के लोगों के पास होता। वे सभी हिमाचल प्रदेश को स्विट्जरलैंड समझते हैं। अगर मैं बैजनाथ की बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में कितने ही राजस्थानी हैं, जो यहां रह रहे है। प्रदेश में काम करके आज वे गाड़ियां और ट्रैक्टर लेकर राजस्थान जा रहे हैं। ऐसी तो हमारे प्रदेश की हालत है, इसमें सुधार होना चाहिए। इसके साथ ही, अच्छी शिक्षा प्रदेश सरकार को देनी है ताकि हमारे युवा अच्छे शिक्षित हो सके और प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ें और यही समय की जरूरत भी है। प्रदेश सरकार इसे लागू करे ताकि प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इस ओर भी मैं सरकार का ध्यान लाना चाहता हूं। अच्छी शिक्षा मिलेगी तो हमारे बच्चें पूरे हिंदुस्तान में प्रतियोगिता करके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई दोराहे की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव माननीय सदन में रखा गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। प्रदेश सरकार और आदरणीय मुख्य मंत्री जी प्रयत्नशील हैं और प्रदेश के जितने भी लोगों को रोजगार मिलेगा, वह कम ही है। आज के समय में युवा हताश हैं लेकिन फिर भी पिछले तीन-चार सालों में सरकार ने जितना रोजगार दिया है, इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने हर वर्ग को राहत दी है और नौकरियों में पारदर्शिता लाई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस की भर्ती हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। सिलेक्शन बोर्ड में भर्तियां हुई, कोई नौकरीनहीं बिकी। पूर्व सरकार में यह सब कुछ होता रहा है। आज उसमें सुधारीकरण हुआ है। प्रदेश सरकार आगे बढ़ी है

01.09.2026/1605/ए0एस0-ए0पी/-02

और भविष्य में भी पारदर्शिता के साथ ही नौकरियां दी जाएंगी। यहां ये बातें भी कही गई कि आउटसोर्स में पैसे लेते हैं। कोई साबित करके तो दिखाए कि पैसे कौन लेता है। उसके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। इसके लिए बोलने को कोई तैयार नहीं है। भर्तियां

तो हो रही हैं और आपने ही आउटसोर्स भर्ती शुरू की थी, इसमें कोई नई चीज तो नहीं है। इसलिए मैं युवाओं के पक्ष में हूं। युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए और जितनी नौकरियां प्रदेश सरकार ने दी हैं, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बाबा बैजनाथ।

01.09.2026/1605/ए0एस0-ए0पी/-03

सभापति : माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा।

श्री प्रकाश राणा: सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत बेरोजगारी का जो विषय माननीय सदन में लाया गया है, उस विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आज इस सदन में हिमाचल प्रदेश के उस वर्ग की आवाज उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिसके कंधों पर प्रदेश का भविष्य टिका हुआ है। वह हमारे युवा नौजवान साथी हैं। आज विषय है रोजगार और बेरोजगारी, लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आज हर एक युवा का यही सवाल है कि मुझे नौकरी कब मिलेगी? जब वह सुबह उठकर अखबार और मोबाइल में नई भर्ती खोजता है और उसकी मां का भी एक ही सवाल है, जिसने अपने बेटे-बेटी की पढ़ाई के लिए अपनी पूरी बचत खर्च कर दी। उस पिता का भी वही सवाल है जिसको उम्मीद थी कि उसका बच्चा पढ़-लिखकर परिवार का सहारा बनेगा। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रश्न यह तो होना चाहिए कि युवाओं को नौकरियां देंगे तो कहां से देंगे

श्री ए0टी0 जारी .....

01.09.2026/1610/AT/AS/01

श्री प्रकाश राणा जारी...

मैं जब पीछे के आंकड़े देख राह था तो वर्ष 2010-11 में हमारे पास लगभग एक लाख नब्बे हजार पांच सौ-सात सौ के करीब एम्प्लॉय थे, वहीं वर्ष 2025-26 तक उनकी संख्या और कम हो गई है। आंकड़ों के अनुसार अब लगभग एक लाख सत्तर हजार एम्प्लॉय ही बचे हैं। सवाल यह भी है कि जिन लोगों ने बी0ए0, एम0ए0, बी0एड0 की हुई है और जो नौकरी की राह देख रहे थे कि हमारा बैचवाइज नंबर कब आएगा, आज उनकी उम्र भी 45-50 वर्ष को पार कर रही है। ऐसे लोग हमसे मिलते हैं, हमारे घरों में भी आते हैं, लेकिन उनके लिए नौकरियां नहीं हैं।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह सत्तापक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। जब आपके पास उतने साधन ही नहीं हैं, तो आपको सच्चाई बताने में क्या समस्या है? प्रदेश की जनता सच्चाई जानना चाहती है। जरूरी नहीं है कि कोई भी सरकार सबको नौकरियां दे सके। मैं भी समझता हूं कि सरकार सबको नौकरियां नहीं दे सकती। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि आप कम से कम युवाओं और हिमाचल की जनता के सामने सच्चाई तो लाएं।

अब जब आपकी सरकार के साढ़े तीन-चार साल तकरीबन निकलने वाले ही हैं, तो अब आपको सच बताने में क्या हर्ज है? सच्चाई बताइए कि हम नौकरियां नहीं दे सकते हैं, हमारे पास उतने साधन नहीं हैं। चर्चा यहां नौकरियों की हो रही है, तो यह भी बताइए कि नौकरियां कहां से देंगे। हमारे प्रदेश के इस समय जो हालात हैं, उन्हें गहराई से देखिए। जब हम आर्थिक स्थिति देखते हैं, सही बात तो यह है कि जो एम्प्लॉय हमारे पास हैं, उनको ही देने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। जनता को सच्चाई बताइए, ताकि लोगों ने जो उम्मीद लगाई हुई है, कम से कम वे उस उम्मीद से बाहर निकल सकें। कब तक हम लोगों को इस तरह ठगते रहेंगे?

जब हम हिमाचल की आर्थिक स्थिति को देखते हैं, तो हमारे जो इनकम सोर्सेज हैं, उनसे तो हम सिर्फ तीन-चार काम नहीं चला पा रहे हैं। अगर आपके पास कुछ

01.09.2026/1610/AT/AS/02

कॉन्फिडेंस है, तो मैं चाहता हूं कि आप श्वेत पत्र जारी करें। हिमाचल की जनता यह देखना चाहती है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पास इस समय जो इनकम सोर्सेज हैं, वह बड़ी मुश्किल लगभग 18-19 हजार करोड़ रुपये का हैं। केंद्र सरकार से हमारा जो शेयर है चाहे वह जी0एस0टी0 का हो वह 13950 करोड़ रुपये का है। इसके अलावा जो ग्रांट हमें केंद्र सरकार से मिलती है जिसमें योजनाएं चल रही हैं और अन्य मदों से जो राशि मिलती है उसे मिलाकर बड़ी मुश्किल से हमें 6-7 हजार करोड़ रुपये मिलते हैं। वह राशि तो खर्च होनी ही है।

अब आप बताइ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बड़ी अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दिखाई। हम सबने देखी और सुनी, पूरे हिमाचल ने सुनी। उसको पूरे भारतवर्ष ने देखा। तो क्या वह प्रेजेंटेशन झूठ थी? उसमें साफ लिखा था और हमें उसकी एक-एक कॉपी भी दी गई थी कि हमारे पास इतना भी धन नहीं है कि हम सिर्फ चार चीजों को पूरा कर सकें। वे चार चीजें सैलरी, पेंशन, बैंक की रीपेमेंट और ब्याज। सीधी और सिंपल बात है जो एम्प्लॉय हमारे पास उन्हें हमें हर महीने लगभग 1200-1300 करोड़ रुपये सैलरी के लिए देने ही हैं। उसके बाद पेंशनर्ों के लिए लगभग एक 1000-1100 करोड़ रुपये देने ही हैं। यह तो अंडरस्टूड है यह कोई बोलने की बात ही नहीं है।

बैंक को जो रीपेमेंट करनी है और जो ब्याज देना है, वह भी तकरीबन हर महीने 700-800 करोड़ रुपये है। उसके बाद रीपेमेंट के लिए हर महीने लगभग 500 करोड़ रुपये के करीब देना है और वह देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आपने इस प्रदेश को कर्जे में पहुंचा है वह कर्ज आज लगभग 110000 करोड़ रुपये का है। यह सीधी-सी बात है कि आपने 10-15 वर्षों के लिए जो पैसा ब्याज पर लिया है, उसकी रीपेमेंट भी देनी पड़ेगी। हर महीने सिर्फ ब्याज भरने के लिए और रीपेमेंट के लिए लगभग 1100-1200 करोड़ रुपये चाहिए।

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी.....

01.09.2026/1615/av/dc/1

श्री प्रकाश राणा--------- जारी

अगर हमें बैंक का पैसा नहीं भरना पड़ता और उसकी जगह हम रोज़गार देते तो इस 11-12 सौ करोड़ रुपये की राशि से 40-50 हजार रुपये सैलरी के हिसाब से अढ़ाई-तीन लाख युवाओं को रोज़गार दिया जा सकता था। लेकिन यह सारा पैसा बैंक को जा रहा है। यहां पर चर्चा तो उस बारे में होनी चाहिए कि हमने जो गलतियां की हैं, उनको हम कैसे सुधारें। परंतु यहां पर उलटा यह बात हो रही है कि हम रोज़गार देंगे। यहां तक कि हम अपने कर्मचारियों का पैसा पूरा नहीं कर पा रहे हैं और आज सभी सड़कों पर उतरकर धरना दे रहे हैं तथा अपना हक़ मांग रहे हैं। आप फिर रोज़गार कहां से दे पाएंगे? मुझे तो यह बात समझ नहीं आती कि यहां पर यह बिना मतलब की चर्चा क्यों की जाती है, शायद हमारे पास इस सदन को चलाने के लिए कुछ और विषय नहीं है। हमें यहां इन्कम रिसोर्सिज को जनरेट करने और हिमाचल को इस कर्ज से बाहर निकालने के विषय पर चर्चा करनी चाहिए। परंतु यह कर्ज तो बढ़ता ही जा रहा है। क्या यह सच नहीं है कि श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के ऐसे पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने अपने साढ़े तीन-चार वर्ष के कार्यकाल में 35-40 हजार करोड़ रुपये कर्ज ले लिया है। मगर इतना कर्ज लेने के बाद भी इनका खजाना खाली ही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपका खजाना कब भरेगा? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस बारे में विचार कीजिए, हम इस तरह से एक-दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाकर नहीं बच सकते। प्रदेश का युवा अपना हक़ मांग रहा है और वह चाहता है कि उसे रोज़गार मिले। लेकिन उसको आप रोज़गार कहां से देंगे? अगर आप पूरे हिमाचल की इन्कम देखते हैं तो हमारे पास सैलरी, पेंशन, बैंक की री-पेमैंट और ब्याज भरने के लिए इन्कम नहीं हो रही है। हम हर दो महीने के बाद उधार ले रहे हैं। अपने संसाधनों में कमी के कारण मुख्य मंत्री जी का ध्यान प्रदेश के विकास कार्यों पर केवल महीने के शुरू के 15 दिन ही रहता है बाकी आगे के 15 दिन उनके दिमाग में एक ही बात घूमती है कि अब सैलरी और पेंशन कहां से देंगे और बैंक का ब्याज और री-पेमैंट कहां से

भरेंगे यानी आधा दिमाग तो उनका इन बातों पर रहता है। इस प्रकार से प्रदेश कैसे चलेगा? इन चार चीजों के बाद आपका सचिवालय का खर्चा है। आपकी सैंकड़ों गाड़ियां चली हुई हैं, उनके खर्चे, डीज़ल, पैट्रोल, ऑफिसिज के बिजली-पानी के रैंट,

01.09.2026/1615/av/dc/2

स्टेशनरीज इत्यादि कहां से आएगी? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कोई इस बात को समझा दीजिए कि मैं यह बात गलत बोल रहा हूं। हम ऑफिस में एक-दूसरे को बोल रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ हैं। लेकिन वह है कहां? आपने 40-50 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने के बाद भी यह प्रदेश खाली-का-खाली है। उसके बावजूद मैं यहां पर बड़ी-बड़ी बातें सुनता हूं। यहां पर मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि वर्ष 2027 में यह प्रदेश आत्मनिर्भर और वर्ष 2032 में यह राज्य पूरे देश में नम्बर वन प्रदेश बनेगा। आप यह बात किस हिसाब से कह रहे हैं? आपको अगर चर्चा करनी है तो इस विषय पर कीजिए कि हमें इन्कम रिसोर्सिज कैसे जनरेट करने हैं। यहां पर दूसरा प्रश्न तो आना ही नहीं चाहिए। इस सरकार ने शुरू में बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं, ठीक है गलती हो जाती है। आपने घोषणाएं कर दीं, हमें नहीं पता क्या सोचकर की कि हम अपने कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां दे देंगे। यहां पर 5 लाख नौकरियां तो जबसे हिमाचल प्रदेश बना तब से नहीं मिली हैं। झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है, ईश्वर ने हर चीज़ की एक लिमिट बनाई हुई है। माना गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती हो भी जाती है। आपने प्रदेश के युवाओं को 5 लाख नौकरियां देने का वायदा करके ठग दिया। उसके बाद आपने कहा कि प्रदेश की प्रत्येक महिला को 15-15 सौ रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। फिर कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आप इस प्रकार से फ्री में बांटने की प्रथा को बंद कीजिए। आप सदन में एक बार खड़े होकर बोल दीजिए कि हमारे हाथ खड़े हैं। आप जनता को सच्चाई बता दीजिए क्योंकि प्रदेश की जनता सच जानना चाहती है। प्रदेश का युवा पढ़-लिखकर और बड़ी-बड़ी डिग्रियां लेकर अपने घर में पड़ा हुआ है और इस तरह से उसका जीवन खत्म हो रहा है। आप देखिए, कर्म से कोई नहीं भाग सकता। आपको कर्म तो भरना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल भरना पड़ेगा। इसलिए हम एक अच्छे भविष्य की तरफ चलें क्योंकि इस तरह से झूठी घोषणाएं करके

लोगों का भविष्य खराब हो रहा है। इसलिए आप झूठी घोषणाएं करना बंद कीजिए और एक अच्छे सिस्टम से प्रदेश को चलाइए। हम यह नहीं कहते कि आपने कर्ज लेकर गलती कर दी। प्रदेश पहले भी कर्ज लेकर चला है और इस कर्ज की शुरुआत वर्ष 1994 से हुई थी।

टी सी द्वारा जारी

01.09.2026/1620/टी0सी0वी0/एच0के0-1
श्री प्रकाश राणा .... जारी

क्या वर्ष 1994 से पहले प्रदेश नहीं चलता था? क्या इससे पहले यहां विकास नहीं हुआ? लेकिन जैसे ही कर्ज़ लेने की शुरुआत हुई वैसे ही लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया।

आज आपके चार वर्ष पूरे होने को आ गए हैं लेकिन आपके इनकम सोर्सिज वहीं के वहीं पड़े हैं। प्रदेश की पूरी इनकम ही 19,000 करोड़ रुपये है और महीने की इनकम बड़ी मुश्किल से 2600 करोड़ रुपये हो रही है। 2600-2700 करोड़ रुपये से तो सैलरी और पेंशन का खर्च भी पूरा नहीं हो रहा है तो आप नौकरियां कहां से देंगे? आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है?

मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके यहां बड़े अच्छे अनुभवी लोग बैठे हैं। अच्छे मंत्री बैठे हैं जिनके पास पूरे प्रदेश का अनुभव है। कम-से-कम आप तो सच बोल दें। माननीय सदन में खड़े होकर बोल दें कि हमारे हाथ खड़े हो गए हैं। हम नौकरियां नहीं दे सकते हैं। हम इस प्रदेश के लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं।

सभापति महोदय, जिस इनकम से एक सिस्टम नहीं चल रहा है उससे सेक्रेटरिएट कैसे चलेगा, कहां से खर्चे चलेंगे, कहां से सी0एम0 हाउस चलेगा? आप ऐसे ही क्यों बोल रहे हैं? कहां से एजुकेशन सिस्टम और हैल्थ सिस्टम चलेगा? कर्ज़ लेकर भी यह सिस्टम नहीं चलेगा। आपकी कर्ज़ लेने की लिमिट 10,000 करोड़ रुपये है और वह तो चार चीजों में ही पूरा हो रहा है तो बाकी चीजें कहां से चलेंगी? यह सब धक्के से चल रहा है। हम विपक्ष वालों को खुश कर दिया और पक्ष वालों को खुश कर दिया लेकिन ये चीजें ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम सच्चाई के रास्ते पर आएं ताकि

जनता को हम सच बता सकें। सरकारें बदलती रहेंगी और आती-जाती रहेंगी लेकिन पहले इस प्रदेश को बचाने की कोशिश करें। यह प्रदेश इस वक्त बहुत बड़े संकट में चला गया है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम इसको बाहर कैसे निकालें? हमारे पास कुछ नहीं है और यहां फालतू की चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। मैं भी मांगूंगा और मैं भी अपनी बात रखता हूं लेकिन बात रखकर क्या फायदा? जब मुझे खुद हालात दिखाई दे रहे हैं तो मैं ऐसी बात क्यों करूं जिसका कोई मतलब ही नहीं है?

01.09.2026/1620/टी0सी0वी0/एच0के0-2

इस माननीय सदन में कितनी बार रोजगार की चर्चा आई और कितनी बार विकास की चर्चा आई। हमें कम-से-कम अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। यदि एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो युवाओं को सही कोचिंग दे पाएंगे। जो डॉक्टर बनना चाहता है उसको डॉक्टर वाली कोचिंग दें, जो इंजीनियर बनना चाहता है उसको इंजीनियर वाली कोचिंग दें, जो जैसा चाहता है उसको उसी के अनुसार शिक्षा और कोचिंग दें।

अगर एजुकेशन सिस्टम को हमने सही कर दिया तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी अपने आप ही सैट हो जाएगी। हमारे पास विकल्प है लेकिन हमने क्या किया है? हमने बहुत ईजी तरीका अपना लिया है कि पांच साल हम (विपक्ष) आ गए और पांच साल वे आ गए। अपना टाइम निकालो और चलो। इससे काम नहीं चलने वाला है। हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

इस वक्त इस प्रदेश में हाइड्रो पावर का बहुत बड़ा स्कोप हमारे पास है। अभी भी 13000-14000 मेगावाट बिजली यहां उत्पन्न हो रही है। अभी भी यहां 24000-25000 मेगावाट की अपॉर्चुनिटी और क्षमता है। हम इसका दोहन कर सकते हैं तो इसके लिए एक-दो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट का ही ख्याल किया होता?

सभापति महोदय, ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास विकल्प नहीं हैं, कई चीजें हैं जिन्हें हम करना ही नहीं चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास संभावनाएं नहीं हैं। हिमाचल में रोजगार पैदा करने की भी काफी संभावनाएं हैं। हमारे पास पर्यटन है,

धार्मिक पर्यटन है, एडवेंचर पर्यटन है और जल विद्युत परियोजनाएं हैं। हमारे पास हाइड्रो प्रोजेक्ट, बागवानी, कृषि, दुग्ध उत्पादन, पेड़-पौधे, आई0टी0,डिजिटल सेवाएं और उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। लेकिनइस वक्त सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रदेश में चार चीजें चरम पर चली हुई हैं जिनमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार,नशा और कर्ज़ है। ये चीजें कैसे शुरू हुईं? ये चीजें ऐसे ही शुरू नहीं होती हैं चाहे कोई घर हो, चाहे प्रदेश

01.09.2026/1620/टी0सी0वी0/एच0के0-3

हो, चाहे देश हो,जब हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती है तो ये चीजें अपने आप उत्पन्न होने लगती हैं, जो आज हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पास इस समस्या से बाहर निकलने के लिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ उपलब्ध है। आप जिस तरह सोच रहे हैं कि शराब, भांग और लॉटरी से इस प्रदेश का भला होगा तो इससे प्रदेश का भला नहीं होगा। इन चीजों के सहारे मत चलिए। इन चीजों से न कभी कोई ऊपर उठा है और न उठेगा। ये चीजें थोड़े दिन के लिए होती हैं।

सभापति महोदय, हैरानी की बात है कि आज इस छोटे से हिमाचल प्रदेश में नशा किस तरह फैल रहा है। इस प्रदेश में आज एक दिन में आठ-नौ लाख बोतलें शराब की लग जाती हैं। आप कहते हैं कि सरकार को रेवेन्यू कितना मिलता है? सरकार को सिर्फ 40-50 परसेंट का रेवेन्यू मिल रहा है। 60 परसेंट शराब जो ब्लैक हो रहा है, वह पंजाब से आ रहा है।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

1-9-2026/1625/NS-HK/1

श्री प्रकाश राणा-----जारी

क्योंकि यहां शराब महंगी है। मैं जोगिन्द्रनगर में देखता हूं कि अवैध शराब बिक रही है। वहां ये हालात हैं। नशे को लेकर ये जो तीन चीजें हैं तो मेरी इस माननीय सदन से हाथ जोड़कर रिक्वैस्ट है कि इन चीजों की ओर इस प्रदेश को और न धकेलें और युवाओं का

भविष्य खराब न करें। आज युवाओं के लिए हमें और अच्छी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं बार-बार एक ही बात कहता हूं कि हम सब मिलजुल कर काम करें। यहां पर एक तो यह सिस्टम है कि सरकार एक पार्टी की बनती है और विपक्ष वालों को ऐसा समझा जाता है कि वे एकदम दुश्मन ही हो गए हैं। आप पहले इस भावना को दूर कीजिए। हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए क्योंकि हम चुन कर आए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको पांच वर्षों तक मिलकर काम नहीं करना है तो कम-से-कम चार या साढ़े चार वर्षों तक मिलकर काम करें। अब यहां तो एक ही बात है कि मुख्य मंत्री का ही डिसीजन है। अरे, आप मुख्य मंत्री हैं तो इस प्रदेश को चलाएं। आपने इस प्रदेश को इस वक्त ऐसी स्थिति में धकेल दिया है कि इसको बाहर निकालने के लिए केवल मेरी ही नहीं बल्कि हम सबकी जरूरत है। हम सबको इकट्ठे होकर इस प्रदेश को इस सिचुएशन से बाहर निकालने का प्रयत्न करना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, जोगिन्द्रनगर में एक्सिअन व एस0डी0ओ0 3-4 महीने से नहीं हैं। वहां पर कई पद खाली पड़े हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लड़भड़ोल कॉलेज है और वहां पर काफी स्ट्रेंथ थी। वहां पर लगभग दो सौ की स्ट्रेंथ थी लेकिन वहां पर भी प्रिंसिपल नहीं है। वहां पॉलिटिकल साइंस का प्रोफैसर 4-5 महीनों से नहीं है। इतिहास का प्रोफैसर पिछले चार वर्षों से नहीं है। इंग्लिश का प्रोफैसर भी चार वर्षों से नहीं है। अब आप बताइए कि वहां पर कितने बच्चे रह गए हैं? वहां पर 60-70 स्टूडैंट्स ही रह गए हैं। अब आप बोलेंगे कि हम कॉलेज बंद करेंगे जबकि वहां पर लगभग 250 स्टूडैंट्स थे। लडभड़ोल में 22 से 25 पंचायतें आती हैं और वहां कोई दूसरा साधन नहीं है। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप इन पदों को शीघ्र भरें। तब आप कहेंगे कि वहां बच्चे नहीं हैं इसलिए हम बंद कर रहे हैं। जब वहां पढ़ाने वाले टीचर, प्रोफैसर नहीं हैं तो सिस्टम कैसे चलेगा? मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा है।

1-9-2026/1625/NS-HK/2

सभापति महोदय, ऐसे ही स्कूलों के हालात हैं। गवर्नमैंट सीनियर सैकंडरी स्कूल, रोपड़ी, कलैरो में प्रिंसिपल नहीं है। गवर्नमैंट सीनियर सैकंडरी स्कूल, पंजालग में भी प्रिंसिपल रिटायर हो गए हैं और प्रिंसिपल नहीं है। गवर्नमैंट सीनियर सैकंडरी स्कूल भगेड़-

लंगेसर में भी प्रिंसिपल नहीं है। गवर्नमैंट सीनियर सैकंडरी स्कूल, गोलवां जो मेरी पंचायत है यानी विधायक की पंचायत में भी प्रिंसिपल नहीं है। वहां पर लेक्चरर तो 3-3 वर्षों से नहीं हैं। गवर्नमैंट सीनियर सैकंडरी स्कूल, नौहली में इंग्लिश का लेक्चरर पिछले तीन वर्षों से नहीं है। बियूंह में भी नहीं है यानी सारे स्कूलों की लगभग यही स्थिति है। सभापति महोदय, यहां ये सब पढ़ कर कोई फायदा नहीं है क्योंकि सरकार के पास सारा डेटा है। मेरी मंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि इन पदों को शीघ्र भरा जाए। अगर टीचर्स नहीं होंगे तो स्कूल खाली ही होंगे। अब एक तरफ दावा किया जा रहा है कि हमने एजुकेशन सिस्टम में सुधार किया है। मैं मानता हूं कि आपने अच्छी शुरुआत की है। आपने सी0बी0एस0ई0 का सिलेबस शुरू किया और यह आपने अच्छी बात की है लेकिन जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है उसका भी कुछ कीजिए ताकि दूरदराज के बच्चों को सुविधा मिल सके।

सभापति महोदय, अभी बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन कई और माननीय सदस्यों ने अभी बोलना है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

1-9-2026/1625/NS-HK/3

सभापति : अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी बात रखेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री : सभापति महोदय, माननीय प्रकाश राणा जी ने बहुत अच्छी बात रखी और इन्होंने बहुत पॉजिटिव बात रखी। ये हमेशा सुझाव देते हैं और प्रदेश-हित में सुझाव देते हैं। इन्होंने पहले भी कहा है और मैंने आपकी बात को हमेशा अप्रिशिएट किया है कि आज हिमाचल प्रदेश को अपने रेवेन्यू को जनरेट करने की बात करनी पड़ेगी, मगर एक प्रश्न इन्होंने पूछा कि ये प्रदेश कैसे चलेगा? जब हिमाचल प्रदेश बना था और हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था उस समय भारत सरकार जानती थी कि हिमाचल प्रदेश कभी इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो सकता क्योंकि हिमाचल प्रदेश जियोग्राफिकल प्वाईंट ऑफ व्यू से एक डिसएडवांटेज पोजिशन पर है। हम मार्केट से दूर हैं, रॉ मटीरियल हमारे पास नहीं है और बहुत सारे हमारे डिसएडवांटेज हैं। मगर हमारे जो पहाड़ी राज्य चाहे जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड या नॉर्थ ईस्ट हों, इन सभी को इकोनॉमिकली वायबल

करने के लिए पिछली जो सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की रही हों या भारतीय जनता पार्टी की रही हैं, वे इस गैप को आर0डी0जी0 के माध्यम से भरती थीं। अब वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक केंद्र सरकार से आर0डी0जी0 के रूप में

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

01.09.2026/1630/RKS/HK-1

उद्योग मंत्री... जारी

40,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। हमें प्रतिवर्ष लगभग 8,000 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 के रूप में मिलते थे। इसके बाद 15वें वित्तायोग ने प्रदेश को लगभग 48,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जिन्हें क्रमशः 11,000 करोड़, 10,000 करोड़, 9,000 करोड़, 8,000 करोड़, 6,000 करोड़ और 3,000 करोड़ रुपये के रूप में टेपरिंग आधार पर दिया गया। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति डगमगाने का मुख्य कारण यह है कि हमारे व्यय और इंकम के बीच जो अंतर था वह आर0डी0जी0 से पूरा होता था जिसे केन्द्र सरकार और 16वें वित्तायोग ने बंद कर दिया है। इससे सारी चीजें डगमगा गई हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं, प्रदेश की दिक्कतों, परेशानियों और प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखना चाहिए। मेरा मानना है कि हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से उतना नुकसान नहीं होता जितना हिमाचल प्रदेश में होता है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो 1500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी वह राशि हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2023 में आई आपदा से हमारे प्रदेश को लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। पी0डी0एन0ए0 के अंतर्गत हमें 2,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जिनमें से 25 प्रतिशत अर्थात् 500 करोड़ रुपये हमें स्टेट शेयर के रूप में वहन करने पड़े। ऐसी स्थिति में प्रदेश को चलाना अत्यंत कठिन कार्य है। आपकी यह बात बिल्कुल सही है कि प्रदेश को अपने संसाधनों को मजबूत करना होगालेकिन जब तक गवर्नमैंट ऑफ इंडिया हमारी सहायता नहीं करेगी तब तक कर्ज और लोन का जो अंतर है वह बढ़ता ही रहेगा। यह स्थिति केवल इस सरकार के कारण नहीं बनी है बल्कि हमें यह विरासत में मिली है और इसे संभालना

आसान काम नहीं है। आपने रेवेन्यू जनरेट करने की जो सकारात्मक बात कही है मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। हमें विभिन्न क्षेत्रों में रेवेन्यू जनरेट करने के प्रयास करने होंगे ताकि हिमाचल प्रदेश सुचारु रूप से आगे बढ़ सके। एक समय ऐसा भी आएगा जब हम पर्याप्त रेवेन्यू जनरेट करेंगे और गवर्नमैंट ऑफ इंडिया पर निर्भर नहीं रहेंगे। हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। माननीय सदस्य आपने बहुत सकारात्मक और अच्छी बात कही है और मैं आपकी बात को पोजिटिव वे में लेता हूं।

01.09.2026/1630/RKS/HK-2

सभापति : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप क्या कहना चाहते हैं? ठाकुर साहब इस विषय में ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसका आपको जवाब देना पड़े। ...(व्यवधान) हम सबको पता है कि आर0डी0जी0 बंद हुई है।...(व्यवधान) केंद्र में तो भाजपा की सरकार है और आर0डी0जी0 भी उन्होंने ही बंद की है। ठाकुर साहब आप अपनी बात रखिए।

श्री जय राम ठाकुर : सभापति महोदय, मैं सोच रहा था कि हमारे माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा जी ने जो बात कही है उसकी माननीय संसदीय कार्य मंत्री सराहना करेंगे कुछ और इअ पर कुछ सकारात्मक सुझाव भी देंगे। राणा जी एक सफल कारोबारी हैं और अर्थशास्त्र की अच्छी समझ रखते हैं। इन्होंने प्रदेश की वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए यह बात कही कि इन हालात में प्रदेश आगे कैसे चलेगा। यदि माननीय मंत्री जी इस संबंध में यह बताते कि सरकार के पास यह फॉर्मूला है तो अच्छा होता। माननीय मुख्य मंत्री बार-बार कहते हैं कि वर्ष 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन जाएगा और वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा लेकिन उस फॉर्मूले को लागू करने में अब बहुत कम समय शेष है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि वह फॉर्मूला कब लागू किया जाएगा? जहां तक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का प्रश्न है, मैं इस संबंध में केवल यह कहना चाहता हूं कि आप हमेशा दूसरों को ही कोसते रहेंगे। आप रोते-रोते सत्ता में आए थे और रोते-रोते ही सत्ता से बाहर चले जाएंगे। यह एक सच्चाई है। केंद्र में जब 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी तो जाने-माने अर्थशास्त्री डॉ0 मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में प्रदेश में दो फाइनेंस कमीशन आए। उनके कार्यकाल में दो वित्तायोग आए और प्रदेश को केवल 18,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके विपरीत माननीय प्रधान मंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में दो वित्तायोग आए जिनके माध्यम से प्रदेश को 89,300 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। क्या आपके पास इसके लिए धन्यवाद के शब्द भी नहीं हैं? मोदी जी की सरकार में जो यह राशि हिमाचल प्रदेश को मिली वह सारी डवलपमैंट के कार्यों में लगाई गई जिसकी वजह से मैंने अपने कार्यकाल में प्रदेश में 4,700 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया जो आज तक एक रिकॉर्ड है। मेरा मानना है कि भविष्य में भी इस रिकॉर्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

01.09.2026/1635/बी.एस./ वाई.के.-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

इसलिए सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका अपना फॉर्मूला क्या है? आप सत्ता में हैं और आपको मालूम है कि रेवेन्यू जनरेट करने का कोई-न-कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। आपका चार साल कार्यकाल यही कहते-कहते बीत गया लेकिन आप रेवेन्यू जनरेट करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए।

आज की स्थिति यह है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश के लिए बंद नहीं हुई है लेकिन यह पूरे 17 राज्यों की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है जिन राज्यों के लिए यह ग्रांट बंद हुई है और उनमें मेजॉरिटी स्टेट बी0जे0पी0 रूल्ड स्टेट हैं।

यह बार-बार कहना कि हिमाचल के साथ अन्याय किया गया है, हम इस बात से सहमत हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से हिमाचल को मदद मिलती थी और वह हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा होता था। लेकिन अब इसको कोसने के बजाय आप आगे बढ़िए। आप आगे बढ़कर करने क्या चाहते हैं? आपका कार्यकाल धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। आपका कार्यकाल खत्म होने को है और इसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

आदरणीय प्रकाश राणा ने प्रश्न पूछा है कि आप बताइए कि इस हालात में जब रेवेन्यू के आपके रिसोर्सेज जनरेट नहीं हो पा रहे हैं तो आप प्रदेश में किस प्रकार से नौजवानों को रोजगार देंगे? रोजगार की गारंटी आपने 5 लाख नौकरियों की दे रखी है।

आप इसे कैसे पूरा करेंगे? इस पर आप जवाब दीजिए। आप बताते कि हमारा डवलपमैंट का मॉडल यह है। हिमाचल प्रदेश में रिसोर्स मोबिलाइजेशन का हमारा मॉडल यह है। हम इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देने का मॉडल लेकर आए हैं। तब बात समझ में आती है।

लेकिन बार-बार केंद्र की सरकार को कोसते रहना उचित नहीं है। जिस सरकार ने हमेशा लड़खड़ाते वक्त में सहारा दिया है वह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार यानी केंद्र की सरकार आपको सहारा दे रही है। इस बात के लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए न कि केंद्र की सरकार को कोसना चाहिए। यह मैं कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

01.09.2026/1635/बी.एस./ वाई.के.-2

सभापति : माननीय सदस्य का कहना था कि आर0डी0जी0 अचानक बंद कर दी गई? अब माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विनोद सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर नियम-130 के अंतर्गत चर्चा हो रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार बनी थी उससे पहले जब इलेक्शन होने वाले थे तो हमारे कुछ अध्यापकों को दिक्कतें आई थीं। उस समय इसी सदन में यह कहा गया था कि जाकर इलेक्शन लड़ो तभी तुम्हें पेंशन लगेगी।

लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ओ0पी0एस0 के मुद्दे पर जो वायदा लोगों से किया था उसको हमने अपनी पहली मीटिंग में पास किया और यह एन्श्योर किया कि हमारे जो लोग इस प्रदेश की सेवा में लगे हैं उनके जीवन को हमेशा के लिए बेहतर कैसे किया जाए तथा उनका आफ्टर सर्विस जीवन बेहतर और अशोर्ड कैसे रहे। हमारी सरकार की ओ0पी0एस0 से शुरुआत हुई।

मैं इस सरकार को धन्यवाद करता हूं कि इतनी कठिनाई के बावजूद भी हमने कर्मचारियों को ओ0पी0एस0 दी लेकिन केन्द्र सरकार से हमें तो पनिशमैंट ही मिली। हमें

तो दिल्ली सरकार ने ओ0पी0एस0 जारी करने के बाद हमारे जो पैसे थे उनको रोकना शुरू कर दिया।

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय पेपर लीक होते थे और अनेकों संस्थानों में जो नियुक्तियां होती थी वहां किस तरह से पेपर बेचे जाते थे? जो अभ्यर्थी फर्स्ट आया था उसे यह भी मालूम नहीं था कि हमारे पूर्व मुख्य मंत्री का क्या नाम है। इस तरह के लोग फर्स्ट आए थे।

इसके बारे में हमारी सरकार ने निर्णय लिया तो सरकार ने यह एन्श्योर किया कि जो हमारी अभी सबऑर्डिनेट कमेटी बनी है उसके द्वारा हमारे जो लूप्स थे उनको दूर किया गया और इन गलतियों के ऊपर विचार हुआ। इनके ऊपर निर्णय लिया गया तथा सख्त निर्णय लिया गया। मैं ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस तरह का विचार रखा और यह निर्णय लिया कि हमारे जो युवा साथी हैं उनके

01.09.2026/1635/बी.एस./ वाई.के.-3

भविष्य के साथ इस तरह जो गलत हो रहा था उस पर तुरंत रोक लगाई गई।

आज हम सक्सेसफुली यह देखते हैं कि हमारा जो 'हिमईरा' लगा है उसके द्वारा हमें बहुत सक्सेस मिली है। कॉटेज इंडस्ट्री के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वे पूरी दुनिया में

जाकर अब जाने लगे हैं। आज मेरे भाई यहां पर बैठे हैं और सामने बहुत सुंदर कोट पहनते हैं।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

01.09.2026/1640/DT/YK-1

श्री विनोद सुल्तानपुरी जारी...

जियोग्राफिकल इंडिकेशन्स होती हैं, जीआई टैग है क्योंकि बड़े सुंदर कलर के कोट ये पहनते हैं, वह हैं हमारे दीप राज जी और हमारे साथी एक फैशन आइकॉन भी हैं, स्मार्ट

हैं। मैं समझता हूं कि हमारे जो घरेलु प्रोडक्ट्स हैं या जो हमारे गांव के प्रोडक्ट्स हैं, अगर हमारे साथी इस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। हमारे लोगों को एम्प्लॉयमैंट मिल रहा है और I appreciate something like this. इस तरह की बात होनी चाहिए। मेरे अन्य साथी श्री सुदर्शन सिंह बबलू जी भी यहां बैठे हैं इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मैं इनके घर गया हूं और जिस फैक्टरी में ये खुद काम करते थे आज उस फैक्टरी के मालिक हैं। आज ये डिफेंडर जैसी ब्रांड गाड़ी में चलते हैं। हमें खुशी है कि हमारे भाई में दम है इसलिए ये जीवन में इन्होंने इतनी सक्सेस पाई है। आज हिमाचल में जब कोई इस तरह से जीवन में आगे बढ़ता है तो हम सभी को खुश होना चाहिए। माननीय प्रकाश राणा जी हेलीकॉप्टर में आते हैं और हमें खुशी होती है। इनके पास हेलीकॉप्टर है यह बहुत अच्छी बात है और हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे हिमाचली के पास हेलीकॉप्टर है। जब हम रोजगार की बात कर रहे हैं तो हमारा जो बेसिक सिस्टम है हमें उस पर भी विचार करना चाहिए। कुछ समय पहले मैं विधान सभा की समिति के साथ एक बार गोवा गया था वहां पर हमें डिनर पर बुलाया गया। वहां भी माननीय लोकेन्दर जी के क्षेत्र वहां लगभग हजार बच्चे थे जो इनके समर्थक थे जिन्होंने अलग-अलग वहां छोटे-छोटे अपने होटल या शैक्स लगाए हुए थे। मैं उन बच्चों से मिलकर हैरान हुआ क्योंकि उन बच्चों में से कोई इटालियन बोल रहा था, कोई हिब्रू बोल रहा था और कोई रशियन बोल रहा था-तथा बड़े फ्लुएंटली बोल रहे थे। मैं समझता हूं कि इस विदेशी भाषाओं की शिक्षा के ऊपर हमें काम करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे, जो टूरिज्म ओरिएंटेड काम में जाते हैं, अगर वे पहले से इस तरह से तैयारी करेंगे तो इस तरह की सुविधाएं टूरिस्टस को यहां भी मिलेंगी क्योंकि इस तरह से हम टूरिस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज इसके ऊपर हमारा जो सिस्टम है उसको इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया है। इन्होंने शिक्षा विभाग में जो़ रैशनलाइजेशन किया है उससे विभाग में बेहतरी हुई है। आज हमारे प्रदेश के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है औ मैं समझता

01.09.2026/1640/DT/YK-2

हुं कि हमारा शिक्षा का जो सिस्टम है वह कई प्रदेशों से बहुत बेहतरीन है। पहले राष्ट्रीय स्तर पर हम इक्कीसवें नंबर पर थे और आज हम पांचवें नंबर पर पहुंच गये हैं तथा मैं

समझता हूं कि बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए अब हम पहले नंबर पर आने की दिशा में अग्रसर हैं। मुझे लगता है माननीय मंत्री जी इसमें आपकी मेहनत दिखती है क्योंकि स्कूलिंग सिस्टम को आपने बेहतर किया है उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं।

प्रदेश में हमारी हेली सर्विस भी बहुत बेहतरीन हुई है। आपको अगर मनाली जाना है तो मात्र 20 मिनट में आप मनाली पहुंच जाते हैं। चंडीगढ़ से यहां आना है तो 15 मिनट लगते हैं। इस तरह की जो सर्विसेज हैं उनसे हमारी जो स्ट्रेंथ है वह बनती है। विपक्ष के हमारे साथीगण यहां काफी समय से सिर्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। हालांकि आपने इतना अच्छा प्रस्ताव लाया था। मुझे लगता है कि हमें इफेक्टिवली आगे बढ़ने के लिए इस प्रदेश को कैसे आगे ले जाना है उसके ऊपर चर्चा करनी थी। आज माननीय मुख्य मंत्री जी पर बातें की जाती हैं और उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपके समय में हमने ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट देखे हैं। चीटिंग के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। आपने प्रदेश के ऊपर जो डेट् है उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई मेहनत ही नहीं की। हम देखते रहे जनमंच कैसे झंडमंच होते थे। झंडमंच में कितना खर्चा होता था। वर्तमान केंद्र सरकार के समय दिल्ली में एक आदमी ने 2,600 करोड़ करोड़ का कर्जा बैंक से लिया और सिर्फ छः करोड़ रुपये की ही भरपाई की। यह क्या हो रहा है? क्या हम ऐसी सरकार को वाह-वाही करेंगे? जिन्होंने इतना बड़ा कर्ज लिया और छः करोड़ में अपना हेयरकट करके निकल गए। इस तरह का जो काम करने का तरीका है वह देश के लिए सही नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं अगर हम 100 रुपये का पूरा बजट मानें तो उसमें से 13.24 रुपये हम इंट्रस्ट दे रहे हैं और लगभग नौ रुपये हम लोन की किस्त पर दे रहे हैं। केंद्र सरकार प्रदेश का लोन ही माफ कर देती, हमारी मदद कर देते। केंद्र सरकार ने हमारे 1,500 करोड़ रुपये रोक रखे हैं। अब दे दो हमें क्योंकि वे पैसे हमारे बनते हैं। हिमाचल के लोग देश में हर जगह अपनी कैपेबिलिटी की वजह से आगे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारे लोगों में कोई कमी नहीं है। आज हमें बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमैंट की ओर प्रोत्साहित करना होगा। जैसे माननीय सदस्य श्री सुदर्शन बबलू जी आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो अपनी मेहनत से पहुंचे हैं। आप हम इनसे इंस्पायर क्योंकि हमारे साथी आज युवाओं को

01.09.2026/1640/DT/YK-3

प्रदेश में रोजगार दे रहे हैं। हमें इस तरह की प्रणाली को विकसित करना होगा। आज हम सस्टेन करते हैं

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

01.09.2026/1645/ए.जी.-एन.जी./1

श्री विनोद सुल्तानपुरी......... जारी

चाहे हमारा टूरिज्म है। अभी माननीय मुख्य मंत्री ने एक सपना संजोया है और एयरपोर्ट के लिए बहुत बड़ा अमाउंट दिया है। यह आने वाले वक्त में इस प्रदेश के लिए कितना बड़ा योगदान होगा, मैं समझता हूं कि यह हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हमारी नेचुरल फार्मिंग भी मजबूत हो रही है। आप हॉर्टिकल्चर को देखिए। प्रदेश सरकार ने हॉर्टिकल्चर को होम टूरिज्म के साथ जोड़ा है। प्रदेश सरकार रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी काम कर रही है। इलेक्ट्रिक कारों के माध्यम से हमारे बच्चों को जॉब्स दिए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने युवाओं से कहा है कि आप सोलर प्लांट लगाइए और उसके द्वारा भी जॉब्स दिए जा रहे हैं। ये सभी जॉब क्रिएशन के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में हमारी एक बहन हैं, जयवंती और उनको अभी स्वेटर बनाने की मशीन मिली है। उन्होंने सबसे पहले मेरे लिए स्वेटर बनाया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हालांकि अभी मुझे वह फिट नहीं आया, लेकिन मेरी बहन ने जो स्वेटर बनाया है, उसे मैं सर्दियों के समय अगले सेशन में जरूर पहन कर आऊंगा। हमारे ऐसे साथियों पर मुझे गर्व है। इसी प्रकार हमारे लोगों को फूड वैन्ज़ दी गई हैं। माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। , आदरणीय श्री अनिरुद्ध सिंह जी हमारे बहुत ही होनहार मंत्री हैं। जिन्होंने गरीब-से-गरीब आदमी तक पहुंचने के प्रयास किए हैं। आज यह आइडेंटिफाई किया जा

सकता है कि गरीब-से-गरीब आदमी कौन है और उसके लिए किस तरह रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा सकते हैं तथा उनके बच्चों के भविष्य को किस तरह सुरक्षित किया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने इस तरह से काम करने का प्रयास किया है।

01.09.2026/1645/ए.जी.-एन.जी./2

सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि आपके द्वारा यह कहा गया है कि लिमिट में बात करनी है, लेकिन मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री, श्री राजेश धर्माणी जी के सामने अपनी बात रखना चाहता हूं। टेक्निकल एजुकेशन में हमारे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां पर स्पेसिफिक जॉब्स के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है—चाहे वह प्लंबर का काम हो या इलेक्ट्रीशियन का काम हो। मेरा मानना है कि इनके सिवाए भी हमें इन्हें आगे बढ़ाना होगा। इसमें और भी एंगल हैं, चाहे वह लैंग्वेज की ट्रेनिंग हो, चाहे हमारे बच्चों को शेफ बनाना हो। हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे शेफ हैं, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है। इसलिए उनको जो पैसा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है, जबकि वे हाईली कैपेबल हैं। यहां पर माननीय मंत्री, श्री हर्षवर्धन चौहान जी भी बैठे हुए हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमें परवाणू में CAD, ऑटोकैड और इस तरह की एजुकेशन के लिए 10 करोड़ रुपये दिए हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि एक बड़ा इंस्टीट्यूट बरोटीवाला और परवाणू के बीच में जो ग्राम पंचायत कोटबेचा है, वहां पर बनाया जा सकता है। वहां पर एक बहुत बड़ा स्कूल था, जो अब बड़ी व नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है। हमें जो 10 करोड़ रुपये मिले हैं, अगर उससे नई बिल्डिंग बनाने की बजाय हम उस इंस्टीट्यूट को उस स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट करके ऑपरेशनल करते हैं, तो वहां के स्थानीय बच्चों को बहुत फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, आज मैं माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करता हूं क्योंकि इन्होंने किसानों के बारे में इतनी सोच रखी कि हमारे गांवों में जो गाय-भैंस का दूध होता है या

हमारी पहाड़ी गाय का दूध है, ये सभी आइडेंटिफाई और एशॉर्ड इनकम के लिए एक साधन बनें हैं। हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्ज़ हैं, उनके ऊपर हमें काम करना है।

01.09.2026/1645/ए.जी.-एन.जी./3

सर, जो पढ़ाई या ट्रेनिंग है, वे इस तरह से होनी चाहिएं कि बच्चा जैसे ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे, वह तुरंत उस इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टडी व ट्रेनिंग के आधार पर उसमें नियुक्त हो जाए।

सभपति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा हमारे जो भेड़ पालक हैं, हमारे फिशरीज के जो किसान हैं, उन्हें भी प्रोत्साहित किया गया है। यह इस सरकार की सोच है। चाहे अदरक हो या लहसुन, ये सारी चीजें एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का एक हिस्सा हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा जो टूरिज्म है—क्योंकि मैं एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन से बिलॉन्ग करता हूं—वह एक हेल्दी टूरिज्म होना चाहिए। हर रोज होटलों में बड़े-बड़े साउंड सिस्टम लगाए जा रहे हैं। उसको कंट्रोल करने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि एक हेल्दी टूरिज्म की तरफ हमें काम करना होगा। ओपन एयर में किस तरह साउंड का इस्तेमाल होगा, उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जिन लोगों के गांव व घर हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है। यह एयर/साउंड पॉल्यूशन है। उनके द्वारा पानी के जो सोर्सिस हैं, उनको डिस्टर्ब

पी0बी0 द्वारा......जारी

01.09.2026/1650/AG/PB/1

श्री विनोद सुल्तानपुरी... जारी

किया जा रहा है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना होगा। हमें भूटान के टूरिज्म की तर्ज पर सोचना होगा। भूटान का टूरिज्म बहुत एक्सक्लूसिव टूरिज्म है तथा वहां के स्थानीय लोगों के लिए इन्क्लूसिव टूरिज्म है।

मैं सदन का ध्यान एक और इश्यू की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विभिन्न इंडस्ट्रीज, कॉलेजिस और इंस्टिच्यूट्स में एम्प्लॉयमैंट को लेकर मैं देख रहा हूं कि आए दिन हमारे बच्चों की आइडैंटिफिकेशन में दिक्कत आ रही है। जैसे ही छः महीने या आठ महीने होते हैं उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है और फिर वे धरने पर बैठते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एम0एम0यू0 कॉलेज है। यह बहुत अच्छा इंस्टिच्यूट है लेकिन आज वहां जो बच्चे लगभग 16 वर्षों से काम कर रहे थे और उन्हें अलग-अलग कांट्रैक्टर्ज के द्वारा रखा गया था, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। आज हमारे लेबर लॉज कमजोर हुए हैं। इस सदन के माध्यम से नियम-130 के तहत मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं कि इस प्रकार से हमारे प्रदेश के जो बच्चे एम्प्लॉयड होते हैं उनके जीवन पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उनकी सिक्योरिटी के लिए हमारे पास उनका डेटा होना चाहिए तथा बच्चों की काबिलियत के अनुसार उन्हें नौकरियां मिलनी चाहिए। आज कोई धरना-प्रदर्शन करता है तो वह उनका हक है। मेरे विधान सभा क्षेत्र तथा प्रदेश के युवाओं के भविष्य को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, हमें इस पर विचार करना होगा।

मैं ज्यादा न बोलते हुए अंत में एक बात कहना चाहता हूं। हम टूरिज्म पर बहुत मेहनत कर रहे हैं इसलिए हमें बसों को ऑनलाइन करना चाहिए, चाहे वह प्राइवेट बस हो या सरकारी बस हो। उसके लिए एक एप्लीकेशन होनी चाहिए, जिसमें हमें यह जानकारी हो कि कौन-सी बस यहां से क्रॉस करने वाली है जिससे उस बस का कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। जब हमारा टूरिस्ट यह जानकारी रखेगा कि यदि वे इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कौन-से रेस्ट हाउस में रहना है, कौन-सी बस से जाना है यह सभी जानकारी उपलब्ध होगी। मैंने आपके सामने यह सारी प्रक्रियाएं और टूरिज्म को स्ट्रेंथन करने से संबंधित मुद्दे रखे हैं।

01.09.2026/1650/AG/PB/2

मैं धन्यवाद करता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जो विचार किया है उसके द्वारा हिमाचल आगे बढ़ेगा, हिमाचल का स्किल आगे बढ़ेगा और हिमाचल के युवा आगे बढ़ेंगे। यह सरकार युवाओं की सरकार है। इसमें कोई चीटिंग नहीं है, कोई करप्शन नहीं है...(व्यवधान) मामा जी तो चले गए हैं, मामा जी बाहर गए है। हमारी सरकार ने कर्मचारियों को ओ0पी0एस0 दिया और हमें इस बात पर गर्व है। हमारी सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। हम अपने आप हिमाचल को आगे ले जाने में सक्षम हैं। मैं यही कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद।

01.09.2026/1650/AG/PB/3

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री दीप राज भाग लेंगे।

श्री दीप राज : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तापुरी जी यदि शेर अच्छा लगेगा तो दाद फरमाइएगा।

सूबे के शहर में इश्तिहार चमका दिए,
सूबे के शहर में इश्तिहार चमका दिए।
काम कुछ किया नहीं, बस फ्लेक्स लगा दिए।
काम कुछ किया नहीं, पूरे प्रदेश में बस फ्लेक्स लगा दिए।
पूछने लगे जब हिसाब चार सालों का
तो सत्ता पक्ष ने सदन में झूठे आंकड़े सुना दिए।

सभापति महोदय, रोज़गार के विषय पर चर्चा चली है और युवाओं के रोजगार के विषय पर चर्चा है। मुझे लगता है कि सबसे पहले सत्ता पक्ष को यह समझने की आवश्यकता

है कि युवा अवस्था कौन-सी मानी गई है। मुझे लगता है कि 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष का जो युवा होता है वह अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद टिक-टिकी निगाहों से अपने परिवार की पूरी आशाओं के साथ सरकार की तरफ देखता है। वह सोचता है कि सरकार हमारे लिए ऐसे निर्णय लेगी और हमारे लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराएगी। ऐसा ही झुनझुना सत्ता पक्ष ने चुनावों से पहले युवाओं को दिया। लेकिन इस सरकार की मंशा युवाओं के प्रति क्या है, उसका मैं एक छोटा-सा उदाहरण सत्ता पक्ष के सामने रखना चाहूंगा। हमने देखा कि हमारे इस विधान सभा में जो सबसे युवा मंत्री हैं उन्हें एक कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। सभापति महोदय, यह चिंता का विषय है कि यह युवा का अपमान है, एक मंत्री का अपमान है या एक झंडे का अपमान है। ...(व्यवधान) यह 15 अगस्त के कार्यक्रम में हुआ है। यह वर्तमान सरकार की और मुख्य मंत्री जी की युवाओं के प्रति तथा सदन के युवा विधायकों के प्रति उनकी मंशा को दर्शाता है।

01.09.2026/1650/AG/PB/4

सभापति महोदय, सदन में बार-बार केंद्र सरकार द्वारा दो करोड़ नौकरियां दी जाने की बात कही गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की पांच ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसके माध्यम से स्टार्ट-अप शुरू किया जा सकता है। आज वर्ष 2014 के बाद सौ से अधिक ऐसी कंपनियां हैं जो युनिकॉर्न बन गई हैं। सत्ता पक्ष को मैं बता दूं कि युनिकॉर्न...

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

01.09.2026/1655/ए0एस0-ए0पी/-01

नियम-130 पर चर्चा जारी .....श्री दीप राज जारी .....

बन चुकी हैं। सत्तापक्ष को मैं बतां दूं कि यूनिकॉर्न का मतलब, 1 बिलियन डॉलर की कंपनी होता है। जिसका मतलब 95,000 करोड़ रुपये होता है। अब अगर सौ से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां बनेगी तो उनमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। इस बात को समझने का नजरिया भी हमें देखना चाहिए। लेकिन जब मैं हिमाचल प्रदेश में स्टार्टअप को देखता हूं तो

मुझे लगता है कि या तो यहां अधिकारी मुख्य मंत्री जी को समझा नहीं पा रहे हैं या मुख्य मंत्री जी के जो साथी हैं, वे नहीं समझा पा रहे हैं। आदरणीय अवस्थी जी, पठानिया जी, हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका भी गए थे। स्टार्टअप और इंसेंटिव में क्या फर्क होता है, यह तो आप समझाइए। एक स्टार्ट-अप उसको कहा जाता है, जिसमें एक युवा अपना एक आइडिया लेकर आता है। अभी कह रहे थे। सर, एंटरप्रेन्योर और कंपनियों की बात कर रहे थे। स्टार्ट-अप में एक युवा अपना आइडिया लेकर आता है, जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है और उसके साथ बहुत सारे रोजगार पैदा किए जाते हैं। लेकिन प्रदेश में क्या स्टार्ट-अप है? यहां जो इंसेंटिव मिल रहा है, उस इंसेंटिव को स्टार्ट-अप का नाम दे दिया गया है। सबसे पहले टैक्सी की बात करना चाहता हूं। जब कोई युवा साथी गाड़ी लेगा तो वह खुद ही उसे चलाएगा। वह किसी दूसरे आदमी को रोजगार कहां से उपलब्ध करवाएगा? इसके अलावा, आप लोगों ने बात कही कि हल्दी उगाओ, अदरक उगाओ, प्राकृतिक खेती करो, भांग उगाओ। सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश की 80 प्रतिशत से ज्यादा जनता के पास दो बीघा से भी कम जमीन है। वर्ष-2023 के बाद लगातार हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आ रही है। आपदा की वजह से लोगों के बगीचे बह गए हैं और कई लोगों के खेत भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जब लोगों के पास जमीन ही नहीं है तो वे आपकी इन सुविधाओं का लाभ कहां से उठा पाएंगे? सत्तापक्ष लोगों को किस तरह का स्टार्टअप और किस तरह की योजनाएं बता रहा है। दूसरा, आपने एक ओर स्टार्टअप बताया। आपके इस गाड़ी वाले स्टार्टअप को देखकर मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक युवा ने गाड़ी खरीदी थी। गाड़ी लेने के बाद उसने सोचा कि सरकार की 55 रुपये की दूध की योजनाएं हैं। उसने एक सोसायटी के माध्यम से गांव में जाकर अपने क्षेत्र की महिला किसान जो गाय का दूध बेचने का काम करती हैं। उनसे दूध

01.09.2026/1655/ए0एस0-ए0पी/-02

इकट्ठा करके सोसायटी में ले कर जाएगा तो इससे उसकी कुछ आय बढ़ेगी और साथ-साथ गांव की उन महिलाओं को भी कुछ-न-कुछ रोजगार मिलेगा और जिन महिलाओं ने गाय खरीदी है उनको भी आय का साधन मिलेगा। लेकिन फैट और एस0एन0एफ0 के चक्कर में वह बेचारा युवा बेरोजगार भाई गांव में सबसे लड़ता रहा कि 51 रुपये, 48 रुपये

रेट मिल रहा है। उस साथी को महिलाओं के साथ झगड़ना करना पड़ता है कि डिग्री का सिस्टम है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो वहां आठ हजार लीटर की कैपेसिटी है। आपकी इन योजनाओं को देखकर पता नहीं कितने युवाओं ने और कितनी हमारी माताओं-बहनों ने गाय खरीद ली। उसके बाद जब उनको पैसे मिलने की बारी आई तो उन्हें दो-तीन महीने का इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद पैसे मिलते हैं। अब अगर किसी ने गाड़ी की किस्त देनी है या अपने घर का खर्च चलाना है तो उसको पैसे तो समय पर ही चाहिए। बिना पैसों के वह कैसे कर पाएगा...(माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राज जी की ओर इशारा करते हुए) आम लोगों का गुजारा नहीं होता। यह शेयर स्पेशल मलेंद्र जी के लिए।

अदरक-हल्दी के सपने बेचे, दूध और प्राकृतिक खेती के गाये गाने

व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने खाली कर दिए सारे खजाने।

कैसे युवाओं को ठगा जाए। कैसे अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लोगों, ओ0बी0सी0 वर्ग के लोगों और महिलाओं को किस तरह से लूटा जाए। सभापति महोदय, इसका उदाहरण आज हमारे सामने है। आज से एक साल पहले पटवारी की भर्ती निकाली जाती है। उसमें सबसे आठ-सौ रुपये फीस ली गई। अगर कोई ओ0बी0सी0 वर्ग, एस0सी0 वर्ग, एस0टी0 वर्ग या कोई महिला उसका एग्जाम देती थी तो उसको कन्सेशन दी जाती थी और फीस कम ली जाती थी। लेकिन इस बार सभी से आठ-सौ रुपये लिए गए। कितने ही हजारों बेरोजगार युवाओं से पैसे लिए गए। लेकिन उनको नौकरी के नाम पर सिर्फ झुनझुना दिया गया। अभी तक पटवारी भर्ती की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। इस भर्ती में कब क्या होगा, इसका कोई अता-पता नहीं है। इसको कहते हैं युवाओं के साथ घोर अन्याय। इनको तो अपना भी अता-पता नहीं है। इसके अलावा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एन0टी0टी0 की

01.09.2026/1655/ए0एस0-ए0पी/-03

आउटसोर्स पर भर्ती की गई। जिसको आउटसोर्स का टेंडर मिला, उसने पांच-सौ रुपये फीस तय की और उसने वह फीस तो ली ही साथ ही में 25-25 हजार रुपये कमीशनखोरी भी ली।

माननीय सदन की बैठक को आधे घंटे के लिए, 05:30 बजे तक बढ़ाया गया।

श्री दीप राज : एन0टी0टी0 भर्ती के लिए सभी युवाओं से पांच-सौ रुपये लिए गए और साथ ही, उनसे कमीशन भी ली गई है कि तुम्हारी नौकरी लगेगी। किसी से 25 हजार, किसी से 50 हजार और किसी से एक लाख रुपये लिए गए है। मैं बड़े तथ्यों के साथ यह कह रहा हूं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं ये नाम भी सदन में रख दूंगा। आया हेल्पर के टेस्ट हुए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के टेस्ट हुए, उन सब में सभापति महोदय,

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

01.09.2026/1700/AT/AS/01

श्री दीप राज जारी...

सिर्फ और सिर्फ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के कार्य चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदया, इन सब योजनाओं को देखकर आजकल एसा लगता है जैसे वह भी कपिल शर्मा के शो की टी0आर0पी0 की तरह डाउन हो गई हैं। अध्यक्ष महोदया, सरकार की कार्यगुजारी और योजनाओं को देखकर लोग इतना हंसते हैं कि सरकार को लगता है कि लोग खुश हैं। सभापति महोदया, वे खुश नहीं हैं...(व्यवधान) पठानिया जी, वे आपको देखकर हंस रहे हैं और आने वाले समय में आपको इसका परिणाम जरूर मिलेगा।...(व्यवधान) और तो और, सबसे बड़ी बात, ...(व्यवधान) सभापति महोदया, हिमाचल प्रदेश में सेब की बात की जाती है। सेब की पांच हजार करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था है। पिछले तीन वर्षों में कई लोगों के बगीचे बह गए, उसको तो छोड़िए, उनको मुआवजा नहीं मिला। लेकिन जो सेब की बोरियां लोगों ने खरीदी थीं, उन सेब के बगीचों में कौन काम करने जाता है? वहां बेरोजगार साथी काम करने जाते हैं। अब बगीचों के मालिकों को पेमेंट ही नहीं मिल रही है। उनको कहा जा रहा है कि अपना किसानी का सर्टिफिकेट लेकर आओ। जब सेब की बोरियां खरीदी थीं, तब क्यों नहीं मांगा सर्टिफिकेट? और उन बेरोजगार साथियों को उनकी पेमेंट तक नहीं मिली है। मैं उस अंतिम व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो किसी सेब के बगीचे में जाकर दिहाड़ी पर काम करता है।...(व्यवधान) ठीक है ना, रोहित ठाकुर जी? नहीं मिली ना? देखिए, वे भी मेरे साथ सहमत हैं। श्री केवल सिंह पठानिया जी, आप भी

थोड़ा हाथ हिला देते तो बढ़िया हो जाता। अध्यक्ष महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हमारे लोगों ने लंबे समय तक प्रतीक्षा की। वहां सतलुज जल विद्युत निगम का प्रोजेक्ट लगा। लोगों के मन में बड़ी मंशा थी कि जब कोई प्रोजेक्ट आयेगा तो हमें रोजगार मिलेगा और रोजगार के माध्यम से हमारा क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा।

आज उस क्षेत्र की चार पंचायतों के लैंड लूजर लोग हैं, जिन्होंने अपनी जमीन खोई है, जब कोई अपनी जमीन खोता है तो वह केवल अपना घर ही नहीं खोता, वह अपने बचपन की यादों को खोता है। वह अपना पूरा जीवन जिस स्थल पर गुजारता है, उस

01.09.2026/1700/AT/AS/02

स्थल को खोता है। सभापित महोदया, लेकिन आज उनके साथ क्या हो रहा है? उनको कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। वहां सड़क तक नहीं है।

आज स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के तहत, ...(व्यवधान) श्री केवल सिंह पठानिया जी, उसके तहत अगर कहीं पर हाइड्रो प्रोजेक्ट लगता है तो उसकी 70 प्रतिशत राशि उसी क्षेत्र में खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, आपने शिमला ग्रामीण में 70 करोड़ रुपये दिए हैं। हमें उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है लेकिन क्या मेरे विधान सभा क्षेत्र में आदमी नहीं है? सभापति महोदया, जंगल हमारे, पेड़ हमारे, पानी हमारा, सब कुछ हमारा, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ धोखा मिल रहा है। उस प्रोजेक्ट में रोजगार के नाम पर वहां के युवाओं को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है और बहुत जल्दी वहां पर जनाक्रोश होने वाला है। लोगों के मन में बहुत गुस्सा और आक्रोश है। वहां पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है। मैं इस सदन के माध्यम से आपको पहले से सचेत कर रहा हूं। सभापति महोदया, यह अभी कह रहे थे कि 1500 करोड़ रुपये नहीं दिए।, मेरे विधान सभा क्षेत्र में डेढ़-दो साल होने वाले हैं और 31.80 करोड़ रुपये सी0आर0एफ0 के तहत आए हैं। उसका टेंडर लगेगा तो सड़क चौड़ी हो जाएगी। अगर सड़क चौड़ी हो जाएगी तो दो-चार दुकानें खुल जाएंगी और वहां कोई रोजगार साथी ढाबा ही चला लेगा।

31.80 करोड़ रुपये का टेंडर आप लोगों से ढाई साल में नहीं लग रहा है। क्या वह पैसा ढाई साल में 31.80 करोड़ रुपये से बढ़कर 60 करोड़ रुपये हो गया? और इनको चाहिए 1500 करोड़ रुपये।

सभापति महोदया, दो साल पहले उस रोड के टेंडर की इवैल्यूएशन हुई थी। रेत का रेट बढ़ गया, रोड़ी का रेट बढ़ गया है, लेबर रेट बढ़ गया है। उसकी दोबारा इवैल्यूएशन होगी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या यह करसोग के युवाओं के साथ धोखा नहीं है?

टूरिज्म की बड़ी बात की जाती है। कौन आएगा हिमाचल में टूरिज्म के लिए? सड़कें देखी हैं आप लोगों ने? कभी गांव में जाइए।...(व्यवधान) करसोग नहीं गए? आप कभी

01.09.2026/1700/AT/AS/03

मेरे विधान सभा क्षेत्र में आइए और फिर सड़कें देखिए। सभापति महोदया, जब हमारे क्षेत्रों की सड़कें ही ठीक नहीं होंगी तो टूरिज्म कैसे बढ़ेगा?

आज के समय में देश के लोगों के मन में एक भय है। मैं भी कई बार दिल्ली जाता हूं और अपने दोस्तों से कहता हूं, हिमाचल आओ घूमने शिमला आओ, मनाली आ जाओ। पर अच्छे टूरिस्ट होता है। जिसके पास पैसा ज्यादा होता है और जो ज्यादा पैसा खर्च करगा है वह टूरिस्ट हिमाचल नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि हमारी सुविधाएं इस तरह की नहीं हैं। पर जो पैसा आता है, वह पैसा आपसे खर्च होता नहीं है और आप बार-बार 1500 करोड़ 1500 रुपये नहीं आए, 1500 रुपये नहीं आए। 31.80 करोड़ रुपये का टेंडर कब लगा रहे हैं? इस सदन के माध्यम से मेरा सत्ता पक्ष से निवेदन है कि वे जरूर बताएं।

सभापति महोदय, और तो और एक बेरोजगार आदमी के पास गाड़ियां नहीं होती हैं, वह पैदल चलता है। अगर उसके पास गाड़ी हो या बाइक हो तो वह कैसा बेरोजगार? अब सत्तापक्ष ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में 35 बसों के रूट बंद कर दिए। उन बसों में बेरोजगार युवा अपना कार्ड बनाकर कार्ड के माध्यम से सफर करते थे। लेकिन आप लोगों ने बस का सफर तो छुड़वाया ही छुड़वाया, जिंदगी में भी आपने उनको सफरिंग में डाल दिया है।

मेर विधान सभा क्षेत्र से अगर कोई शिमला आता है। तो शिमला से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर एक तत्तापानी नामक स्थान है, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। सभापति महोदया, वहां पर बहुत बड़ी लेक है, बहुत बड़ी झील है। वहां वाटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन पिछले साढ़े तीन साल में एक रुपया भी वहां के लिए नहीं आया। हम मानते हैं कि वहां से मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आया हूं, लेकिन वहां कांग्रेस के भी तो लोग हैं। उनका क्या? वहां के लिए सड़क तो बन ही रही है अगर वहां पर वाटर स्पोर्ट्स के लिए कुछ पैसा

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी.....

01.09.2026/1705/av/dc/1

श्री दीप राज--------- जारी

इंवेस्टमैंट की जाती है तो उससे किसी-न-किसी रूप में हिमाचल की आय बढ़ती। मगर सरकार द्वारा आय नहीं बढ़ाई जा रही अपितु भ्रष्टाचार कैसे बढ़ाया जाता है, मैं उसके बारे में बताता हूं। हिमाचल प्रदेश की इम्प्लॉयमैंट एक्सचेंज में 6 लाख युवा रजिस्टर्ड हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश के ही बद्दी, नालागढ़ इत्यादि क्षेत्रों में इतनी ज्यादा इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं। उनसे जो सी0एस0आर0 का फण्ड आता है, वह फण्ड भत्ते के रूप में प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं को मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर 6 लाख में से एक प्रतिशत यानी 6000 युवाओं को भी बेरोज़गारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप इस संदर्भ में सदन के अंदर लिस्ट रख दीजिए। हम भी देख लेते हैं कि आपकी बातों में कितने तथ्य हैं।

मैं जब विधान सभा में नया-नया चुनकर आया तो मैंने यहां सदन के अंदर पेप्सी की बड़ी-बड़ी बातें सुनी थीं। मैं बड़ा खुश हुआ था कि लीजिए, हिमाचल प्रदेश की तरक्की हो गई। अब हमारे यहां पर पेप्सी भी बनेगी। मैं थोड़े दिन पहले कांगड़ा गया था। माननीय श्री केवल सिंह पठानिया, वहां पर क्या पेप्सी मिल रही थी। हमने अमेरिका में पी थी मगर उससे ज्यादा अच्छे टेस्ट वाली पेप्सी यहां मिल रही थी। आपने भी पी होगी जो इन्दौरा में पेप्सी बन रही है। ...(व्यवधान) हां, वह भी ऐसे ही चल रही है जैसे आपका चिड़िया घर चल रहा

है। ...(व्यवधान) कैसी फैक्ट्री? जब सदन के अंदर इस बारे में जवाब आए तो ये तथ्य भी जरूर पेश कीजिए कि उसमें कितने लोगों को रोज़गार मिला। ...(व्यवधान) हमारे प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं के लिए जो शानदार चिड़िया घर बन रहा था, क्या वह बन गया? मुझे लगता है कि यह सरकार फ्यूचर इनडेफिनेट टेन्स से बाहर ही नहीं आ रही है। हर बार 'होगा और करेंगे' वाली बात करते हैं। सरकार को वर्तमान और तथ्यों पर आधारित बातें करनी चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे पत्रकार साथी लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ हैं। लोग अखबारों को बड़ी शिद्दत से पढ़ते हैं और अखबार वाले भी आम लोगों का बड़ा ध्यान रखते हैं। पहले अखबार वाले अपने अखबार में एक चुटकुला कॉर्नर रखते थे ताकि लोग दुःखद समाचार पढ़कर परेशान न हो जाए। परंतु सत्ता पक्ष की खबरें इतनी

01.09.2026/1705/av/dc/2

ज्यादा हास्यास्पद होती है कि अब चुटकुलों की बारी ही नहीं आ रही और मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष वाले अपने कार्यकाल में अखबार के एडिटर की नौकरी भी खा जाएंगे। ...(व्यवधान) लोग उस पेज तक पहुंच ही नहीं पा रहे।

आपने महिलाओं को बहुत बड़ी बात कही। माना, 1500 रुपये देना तो सम्भव नहीं हो पाएगा परंतु आपने प्रदेश की महिलाओं को कई बातें कह कर ठगा है। आपने जैसे गाय के दूध के नाम पर प्रदेश की जनता को ठगा और अब उनको एस0एन0एफ0 तथा फैट के नाम पर लड़ने के लिए छोड़ दिया। हमें फूड प्रोसैसिंग, हैण्डीक्राफ्ट, डिजिटल वर्क्स, हैल्थ केयर, टूरिज्म और होम-बेस्ड एंटरप्राइजिज में ऑनलाइन बिजनेस की तरह सोचना चाहिए कि हम उन लोगों के स्किल व गवर्नमैंट की योजनाओं को किस तरह से आपस में कनेक्ट करें ताकि हमारे यहां पर ज्यादा-से-ज्यादा रोज़गार के अवसर क्रिएट हो सकें। आगे आने वाला युग डिजिटल टैक्नोलॉजी का युग है। अब ए0आई0 धीरे-धीरे कार्यों को समाप्त कर रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे सदन के अंदर सब कुछ ऑनलाइन होता है। ऐप ऑनलाइन चलती है और कैमरे में सब कुछ कैद हो जाता है। आज सुबह अध्यक्ष महोदय भी कह रहे थे कि ये कैमराज बंद करने पड़ेंगे। यहां पर 8-10 वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं हमें इस दिशा में

भी सोचना होगा कि आज से 5-10 वर्षों बाद किस प्रकार की जॉब्स क्रिएट होंगी। मेरे वहां आई0टी0आई0 की बिल्डिंग का कार्य काफी वर्ष पहले शुरू हुआ था और आज वर्ष 2026 समाप्त होने की कगार पर है परंतु उसकी अभी तक छत नहीं लगी है। हम बोलते-बोलते थक गए हैं। अगर आप करसोग के युवाओं को स्किल सीखने के लिए कोई इन्स्टिच्यूट ही नहीं बनाएंगे तो मेरे विधान सभा के युवक किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। इस सरकार की कार्य प्रणाली पर यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है।

सभापति महोदय, मेरा सदन के माध्यम से प्रदेश सरकार में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व जनता को एक बहुत बड़ा सुझाव रहेगा कि हम सभी लोगों को अपने खाते उसमें चाहे सैलरीड अकाउंट या बीमा हो या फिर कोई और सेक्टर हो; उसको कोऑपरेटिव बैंक के खाते में शिफ्ट करना चाहिए। हमें यह भी सोचना चाहिए कि कोऑपरेटिव मशीनरीज को कैसे एडवांस किया जाए और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ाया जाए क्योंकि यूको बैंक वाले प्रति ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये काट लेते हैं। इसलिए

01.09.2026/1705/av/dc/3

अगर हमें यह पैसा देना ही है तो हिमाचल प्रदेश के बैंक को क्यों न दें। हमारा जब अपना बैंक होगा तो उससे कुछ-न-कुछ राजस्व जनरेट होगा।

धर्मशाला और कसुम्पटी में एस0टी0पी0आई0 का पार्क है। वहां कॉल सेंटर वाले लोग बैठे हैं और वे लोगों को 5-5 हजार रुपये में रखते हैं। वहां पर जो बच्चा केवल 5 हजार रुपये की नौकरी कर रहा है उसकी कोई सेफ्टी और सेक्योरिटी नहीं है। उसको वहां से कभी भी निकाला जा सकता है, उनकी चिन्ता कौन करेगा? सरकार को उस विषय में भी कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हम हिमाचल प्रदेश में डेटा सेंटर स्थापित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए कोई बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती। आप चार-पांच कमरों में एक डेटा सेंटर स्थापित कर सकते हैं। हमारा आने वाला समय दिन-प्रतिदिन डिजिटलाइज होता जा रहा है, इसलिए आने वाले समय में वह हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प होगा।

टी सी द्वारा जारी

01.09.2026/1710/**टी0सी0वी0/एच0के0**-1
श्री दीप राज... जारी

आज अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चाहे बेंगलुरु की बात हो, दिल्ली की बात हो या देश से बाहर की बात हो तो आई0टी0 इंडस्ट्री में बहुत से ब्रिलियंट लोग हैं। मेरा खुद का क्लासमेट आज यूके में गूगल मीडिया का हैड है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इस दिशा में कार्य करे।

सभापति महोदय, अंत में एक शेर सुनाकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

"डिग्रियां हाथों में हैं और युवा सड़कों पर बेकार है,
इस सदन में बैठी कांग्रेस सरकार इसके लिए जिम्मेदार है।"

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर जी भाग लेंगे।

श्री नीरज नैय्यर : सभापति महोदय, आज नियम 130 के तहत जो एक महत्वपूर्ण चर्चा सदन में लाई गई है उसके ऊपर मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं। युवा देश का भविष्य हैं। अगर भारत की बात करें तो पूरी दुनिया में यहां युवाओं की संख्या बहुत अधिक है और हमारे देश में आज के समय में बहुत अच्छी यंग पॉपुलेशन पाई जाती है।

मैं अपने विपक्ष के साथियों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था और उनके सजैशन्ज भी सुन रहा था कि रोजगार के लिए क्या बेहतरीन कार्य किए जा सकते हैं। मैं सदन के समक्ष यह बात रखना चाहता हूं कि जब हिमाचल प्रदेश बना तो यह भली-भांति सबको पता था कि 'Himachal Pradesh is not financially viable State' लेकिन कांग्रेस की

सरकार दिल्ली के अंदर शासन कर रही थी और हमारे प्रथम मुख्य मंत्री डॉ0 वाई0 एस0 परमार की बदौलत हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।

यहां सरकारें आईं और सरकारें गईं तथा हिमाचल प्रदेश तरक्की की राह पर अग्रसर हुआ। विभिन्न सरकारों ने लोन लिए चाहे वे भाजपा की सरकारें थीं या कांग्रेस की सरकारें

01.09.2026/1710/टी0सी0वी0/एच0के0-2

थीं लेकिन किसी भी सरकार ने लोन को वापिस करने के बारे में नहीं सोचा। अब एक ऐसी स्टेज आ गई है कि हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक बच्चा जब पैदा होता है तो उस पर पैदा होते ही तकरीबन एक लाख रुपये का ऋण हो जाता है। हमारे पास ऐसा कोई साधन भी नहीं है कि एक दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश समृद्ध या डैब्ट-फ्री हो जाएगा। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसे घर का कोई व्यक्ति होता है उसके के पास सौ रुपये की कमाई होती है तो जब वह पैसे खर्च करता है तो वह देखता है कि इतने पैसे इस चीज के लिए या फलानी चीज के लिए खर्च करने हैं, इतने पैसे सेविंग के लिए रखने हैं और इतना लोन लिया है, उसकी वापसी भी करनी है। इसी प्रकार ये चीजें किसी भी सरकार ने चाहे भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो नहीं सोचीं। लोन्स आसीन से अवेलेबल थे लेकिन लोन की वापसी के बारे में सोच नहीं रखी गई। आज हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि जब हिमाचल के मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल प्रदेश की कमान संभाली

एन0एस0 द्वारा जारी ...

1-9-2026/1715/NS-HK/1

श्री नीरज नैय्यर-----जारी

तो उन्होंने यह पाया कि पिछली सरकार 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज छोड़कर गई। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो फिगर्ज यहां सुने हैं उसके अनुसार पिछली सरकार को पिछले

पांच वर्षों में हमारी सरकार की तुलना में लगभग 40,000 से 50,000 करोड़ रुपये ज्यादा मिले। अब तो हमारी आर0डी0जी0 भी बंद हो गई है। उनके पास उस समय मौका था। आज मैं यहां पर कई वक्ताओं को सुन रहा था और वे बोल रहे थे कि डी0ए0 की किश्तें नहीं दी गईं और सैलरीज टाइम पर नहीं मिल रही है। लेकिन जब हमारी सरकार आई तो आर0डी0जी0 बंद कर दी गई। 75,000 करोड़ रुपये का ऋण हमें पहले ही मिला था लेकिन जब आपका समय था तो आपके पास यह स्थिति थी कि आप उसमें कुछ बेहतरीन कर सकते थे। आपको शायद उस समय यह पता नहीं था कि आर0डी0जी0 बंद होगी। शायद आपने यह सोचा होगा कि अगले पांच वर्षों में आर0डी0जी0 मिलती रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी यह सोच रही हो वरना जब आपको हमारी सरकार की तुलना में 40,000 करोड़ रुपये ज्यादा मिले तो मुझे लगता है कि आप प्रदेश के कर्ज को कुछ कम कर सकते थे। लेकिन आपने कर्ज को कम करने के बजाय संस्थान खोलने में जोर दिया। आप संस्थान पर संस्थान खोलते गए। मैं यह बोलना चाहूंगा कि जहां तक मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात है तो मेरे यहां चम्बा में पी0जी0 कॉलेज है और मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर पी0जी0 कॉलेज की स्ट्रेंथ लगभग 4800 है और वहां बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारे पास अब जगह भी अवलेबल नहीं है। वहां इससे भी ज्यादा बच्चे एनरोलमैंट लेना चाहते हैं लेकिन जगह न होने के कारण कुछ बच्चे धर्मशाला जा रहे हैं। आसपास के एरियाज में भी कॉलेज खुले हैं जहां 100 बच्चे, 200 से 250 बच्चे हैं लेकिन कोई भी बच्चा उन कॉलेजों में एडमिशन लेने का इच्छुक नहीं है। वह सोचता है कि अगर चम्बा में मुझे एडमिशन नहीं मिल रही है तो it is better that I go to Dharamshala क्योंकि मेरा यह मानना है कि जहां बच्चे ज्यादा होते हैं वहां बच्चों की ओवरऑल डवलपमैंट बहुत बेहतर होती है। यहां पर कहा जा रहा था कि अभी इतने स्कूल बंद कर दिए गए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी स्कूल बंद हुए जहां मुश्किल से दो बच्चे थे। मुझे भी पता नहीं था और मैं पहली बार चुनाव लड़कर आया और मेरे पास भी वहां से काफी लोग आए कि ये स्कूल बंद हो रहे हैं, हमारा नुकसान हो जाएगा। जब मैंने बाद में तफ्तीश की तो they were pressurized by the teachers. वहां जो टीचर्स लगे हुए थे उनकी यह सोच थी कि

1-9-2026/1715/NS-HK/2

उन्हें वहां से कहीं और जाना पड़ेगा। वहां पर जो चपरासी लगे हैं उनको ट्रांसफर होकर शायद अपने घर के एरिया से दूर जाना पड़ रहा था। सभापति महोदय, जब तक हम व्यावहारिक रूप से नहीं सोचेंगे तब तक यह बेरोजगारी कैसे दूर होगी? हमें कटु फैसले लेने पड़ेंगे। कुछ फैसले हमारी सरकार ने किए हैं और आगे भविष्य के गर्भ में क्या रखा है, यह तो भगवान ही जानता है। मैं वर्तमान मुख्य मंत्री जी को तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा कि जिस पोजिशन और जिस सिचुएशन में आज वह मुख्य मंत्री बने हैं और सरकार चला रहे हैं, वित्तीय हालात कैसे हैं, वह किसी से भी छुपे नहीं हैं। सभी लोग इसे भली-भांति जानते हैं लेकिन उन्होंने फैसले लिए हैं। उन्होंने पहली बार प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए चाहे पानी पर सैस लगाना हो। पहले शराब के ठेकों की जो नीलामी होती थी उसमें 10 प्रतिशत इन्क्रीज करके ठेके दे दिए जाते थे लेकिन मुख्य मंत्री जी ने उसके अंदर भी सीधे ऑक्शन प्रोसैस शुरू किया और उससे भी हमारी आय बढ़ी। अभी वाइल्डफ्लावर हॉल 1 करोड़ रुपये की सालाना लीज पर दिया गया। उसमें भी प्रदेश सरकार

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

01.09.2026/1720/RKS/HK-1

श्री नीरज नैय्यर जारी...

ने न्यायालय में केस जीता। माननीय मुख्य मंत्री ने अनेक ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिनके आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। कोई अलादीन का चिराग या ऐसा स्विच नहीं है कि आज उसे दबाया और कल पूरे प्रदेश में रोशनी फैल जाए। लेकिन उन्होंने एक सही दिशा में आगे बढ़ने का कार्य किया है। जहां तक नौकरियों का प्रश्न है, मैं सदन के समक्ष यह कहना चाहता हूं कि विपक्ष के कई साथियों ने कहा कि आउटसोर्स आधार पर दी जाने वाली नौकरियां शोषण का माध्यम है। मैं भी मानता हूं कि आउटसोर्स की नौकरी शोषण है लेकिन यदि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे पास लगभग 10,000 आवेदन रोजगार की मांग को लेकर आए हुए हैं। इनमें आठवीं, दसवीं बारहवीं पास युवा शामिल हैं जो रोजगार की तलाश में हैं। चंबा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और वहां कोई उद्योग स्थापित नहीं हैं। इसी कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र के अनेक युवा बद्दी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे वहां

10,000 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर नौकरी करते हैं। तीन-तीन युवक एक कमरे में किराए पर रहते हैं और सामूहिक रूप से अपना भोजन बनाकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो धन बचता है उसे अपने परिवारों को भेजते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आउटसोर्स के माध्यम से नर्सों की भर्ती हो रही है या जल शक्ति विभाग में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं तो वह अच्छी बात है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि उनका वेतन बहुत कम है। आज के समय में 6,000 रुपये का वेतन कुछ भी नहीं होता है। फिर भी यदि किसी व्यक्ति के पास अपना घर व अपनी भूमि हो और उसे अपने ही क्षेत्र में 10,000 रुपये प्रतिमाह का रोजगार प्राप्त हो जाए तो वह सुबह से शाम तक कार्य करने के बाद अपने परिवार के साथ रह सकता है। यदि एक ही परिवार के दो या तीन सदस्य आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर लेते हैं तो उस परिवार की प्रतिमाह 10, 20 या 30 हजार रुपये इंकम होती है। इसलिए सरकार ने यह प्रयास किया है कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति को किसी-न-किसी रूप में रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार आउटसोर्स नीति के संबंध में भविष्य में कोई व्यापक नीति नहीं बनाना चाहती। सरकार इस दिशा में भी प्रयास करेगी। पिछली सरकारें भी इस चुनौती का सामना करती रही हैं और हमारी सरकार भी कर रही है। यह एक बहुत बड़ा निर्णय है। बड़ी संख्या में युवा आउटसोर्स व्यवस्था के

01.09.2026/1720/RKS/HK-2

अंतर्गत कार्यरत हैं और यह एक गंभीर वित्तीय चुनौती है कि इन सभी कर्मचारियों को किस प्रकार नियमित किया जाए। भविष्य में परिस्थितियां कैसी होंगी, यह समय के गर्भ में छिपा है। यदि प्रदेश आर्थिक रूप से और अधिक समृद्ध होता है तो निश्चित रूप से हमारे हालात बेहतर होंगे और इस संबंध में नीति भी बनाई जाएगी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो हमें तीन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन है। चाहे उसे टेंपल टूरिज्म कहा जाए, एडवेंचर टूरिज्म, वेलनैस टूरिज्म, नेचुरल थैरेपी टूरिज्म या हैल्थ टूरिज्म कहा जाए, किसी भी स्वरूप में पर्यटन हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना है और यहां के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करवाना है तो पर्यटन क्षेत्र को प्राथमिकता देनी होगी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम अत्यंत

सौभाग्यशाली हैं। यदि हिमाचल प्रदेश की land to population ratio देखी जाए तो हम हिंदुस्तान से बिल्कुल अलग पाए जाते हैं। We are not like Bihar and U.P. वहां की जनसंख्या 20 करोड़ है और भूमि की उपलब्धता इसकी तुलना में इतनी ज्यादा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति के पास औसतन डेढ़ से दो बीघा भूमि उपलब्ध है। इसलिए यदि हिमाचल प्रदेश को समृद्ध बनाना है तो सबसे पहले पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। इसके अतिरिक्त हाइड्रो इलैक्ट्रिसिटी और सोलर पावर जैसे क्षेत्रों में भी कार्य करने की आवश्यकता है ताकि रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर होंगे।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

01.09.2026/1725/बी.एस./ वाई.के.-1

श्री नीरज नैय्यर जारी...

क्योंकि मैं जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज सोचता हूं तो मुझे यह लगता है कि इंडिया के अंदर अगर कहीं आपने इन्वेस्टमैंट करनी है तो कहीं भी जाकर आंख बंद करके जमीन खरीद लो चाहे वह खड्ड ही हो या कहीं भी लैंड हो। क्योंकि 140 करोड़ की हमारी आबादी होने को हो रही है। तो डेफिनिटली आज आपने जो जमीन खरीदी है कल उसकी कीमत दस गुना होगी। बैंक में भी पैसे आप जमा करके रखेंगे तो उतनी तेजी से उसकी एस्केलेशन नहीं होगी।

आने वाले वक्त के अंदर हमारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर हिमाचल प्रदेश के लिए और युवाओं के लिए भी गेम चेंजर हो सकता है। मेरे अपने स्कूल के कुछ मित्र हैं जो they are like MBA from ivy league, उन्होंने नौकरियां छोड़कर राजस्थान के अंदर 10-20-25 बीघे जगह एक्वायर की है और उस जगह को एक्वायर करके वे वहां हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में अपने आपको इनरोल कर रहे हैं and they are doing exceptionally well. हमारा तो वातावरण भी बहुत बढ़िया है।

मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि जब आप जैविक खेती की बात करते हैं प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, चाहे हल्दी की बात करते हैं, चाहे अन्य खेतीबाड़ी से रिलेटिड चीजों की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि देश के युवाओं को अगर हमने समृद्ध करना है तो रोजगार का इससे बेहतर माध्यम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में देखना होगा और मैं इन्हें नम्बर वन पर रखता हूं।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री नीरज नैय्यर : कई मेरे विपक्ष के साथियों ने बोला है कि सेब की बहुत छोटी-सी जगह के अंदर बहुत ज्यादा प्लांटेशन की जा सकती है लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हम सब लोग सेब के ऊपर ही फोकस्ड हैं। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि मेरे इलाके का जो क्लाइमेट है उसके अंदर अफगानिस्तान में होने वाले पिस्ता भी यहां पर बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि कहीं ट्रीज लगाकर ट्राई करूं।

01.09.2026/1725/बी.एस./ वाई.के.-2

इस तरीके से we will have to think कि जरूरी नहीं है कि जो चीज सेब सारी जगह हिमाचल में लग रहे हैं तो सेबों से ही इनकम होगी। बहुत ऐसी कैश क्रॉप्स हैं और जो क्लाइमेटिकली हिमाचल प्रदेश के अंदर सूट करती हैं। लेकिन कहते हैं कि एक भेड़चाल होती है और सारे उसी के पीछे चलते हैं।

जब व्यक्ति समय पर कोई चीज करता है तो पैसे कमाता है लेकिन जब हजारों लोग वही चीज करना शुरू कर देते हैं तो फिर उसकी इनकम भी जीरो हो जाती है। ...(घंटी)...सभापति महोदय, मैंने बोलना तो अभी बहुत कुछ था लेकिन आपने बार-बार घंटी बजा-बजा कर मेरी भी घंटी साथ-ही-साथ बजा दी है।

सभापति महोदय, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। मेरे विपक्ष के साथी 1,800 कोविड वॉरियर्स जो बाहर किए हैं उनके बारे में बोलते हैं। मैं उस वक्त विधायक नहीं था। मुझे याद है कि कोरोना हुआ और आउटसोर्स पर इन लोगों को नौकरियां देना सरकार ने

शुरू किया। मेरे पास भी एक चम्बा में ठेकेदार आया जो मेरा जान-पहचान का था। मैंने भी 8-10 बच्चों को कोविड वॉरियर्स के रूप में हॉस्पिटल के अंदर नौकरियां दिलवाईं।

वह मेरे पास 8-10 वर्दियां ले आया। जब मैं उन्हें वर्दियां देने लगा तो मैंने उन्हें बोला कि बच्चों यह नौकरी दो-तीन महीने के लिए होगी। हमें यह पता नहीं था कि कोरोना ढाई-तीन वर्ष चलेगा। हमने तो सोचा था कि शायद यह तीन-छः या आठ महीने में खत्म हो जाएगा।

परंतु यह बहुत लंबा चला और ये जो 1,800 बच्चे बाहर निकले हैं ये हमारी सरकार ने बाहर नहीं निकाले हैं। परिस्थितियां ऐसी बनीं कि जब कोरोना आया तो इनको जो पैसा मिलता था उसका 90 प्रतिशत गवर्नमैंट ऑफ इंडिया देती थी और 10 प्रतिशत स्टेट गवर्नमैंट फंड करती थी। जब कोरोना खत्म हो गया तो स्वाभाविक रूप से यह व्यवस्था चलती रही। कोरोना का समय दो-अढ़ाई वर्ष तक चला।

जब इनको निकालने लगे तो मैं भी मुख्य मंत्री जी के समक्ष गया और मैंने कहा कि सर मेरे यहां 200-300 लोग हॉस्पिटल में लगे हुए हैं। ये बच्चे सारे बाहर हो जाएंगे तो

01.09.2026/1725/बी.एस./ वाई.के.-3

समस्या पैदा होगी। मुख्य मंत्री जी ने भी उनको एक-दो महीने की एक्सटेंशन दी और फिर दिल्ली की सरकार से पत्राचार भी हुआ लेकिन non availability of funds आगे के लिए ...(व्यवधान)

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

01.09.2026/1730/DT/YK-1

श्री नीरज नैयर जारी...

सभापति : माननीय सदस्य, कृप्या एक मीनट बैठ जाएं। आप मुझे यह बताइए कि आप अपनी बात रखने में और कितना समय लेंगे?

श्री नीरज नैयर : सभापति महोदय, मात्र पांच मीनट।

सभापति : ठीक है। अब इस मान्य सदन की बैठक पांच मीनट के लिए और बढ़ाई जाती है। माननीय सदस्य पर पांच मीनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री नीरज नैयर : सभापति महोदय, नौकरियों के बारे में अगर विपक्ष के साथी बोलें कि हमने क्या बोला या आपने क्या बोला, तो मुझे लगता है कि इस पर बात करना कोई मायने नहीं रखता। अगर हमने एक लाख रोजगार देने की बात कही है तो भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही है। अगर हमने प्रत्ये महीला को 1,500 रुपये प्रतिमाह देने की बात कही हैं तो केंद्र सरकार सभी के खातों में 15 लाख-15 लाख रुपये आने की बात बोली है। इस बारे में अगर बात ही करनी है तो इस पर टोटैलिटी में बात हो।

सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा।

सभापति : अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, 02 अगस्त, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

दिनांक : 01 सितम्बर, 2026 **यशपाल शर्मा**
शिमला- 171004 **सचिव**